खण्ड-06 सत्र -06 (भाग-01) / अंक-61

मंगलवार 10 अक्तूबर 2017 / 18 अश्विन, 1939 (शक)

दिल्ली विधान सभा

की

कार्यवाही

सत्यमेव जयते

छठी विधान सभा

छठा सत्र

अधिकृत विवरण

(सत्र-06 (भाग-01) में अंक 59 से अंक 62 तक सम्मिलित हैं)

दिल्ली विधान सभा सचिवालय

पुराना सचिवालय, दिल्ली-110054

विषय सूची

सत्र–6 भाग (1)   मंगलवार, 10 अक्तूबर, 2017 / 18 अश्विन, 1939 (शक)   अंक–61

1.	सदन में उपस्थित सदस्यों की सूची	1–2
2.	माननीय अध्यक्ष द्वारा व्यवस्था	3–10
3.	ध्यानाकर्षण (नियम–54) मैट्रो के किराये बढ़ने से उत्पन्न स्थिति पर	11–111
4.	माननीय परिवहन मंत्री द्वारा चर्चा का उत्तर	112–125

दिल्ली विधान सभा

की

कार्यवाही

सत्र–6 भाग (1) मंगलवार, 10 अक्तूबर, 2017 / 18 अश्विन, 1939 (शक) अंक–61

दिल्ली विधान सभा

सदन अपराह्न 2:00 बजे समवेत हुआ।

माननीय अध्यक्ष महोदय (श्री राम निवास गोयल) पीठासीन हुए।

सदन में उपस्थित सदस्यों की सूची

निम्नलिखित सदस्य सदन में उपस्थित हुए :

1. श्री शरद कुमार
2. श्री संजीव झा
3. श्री पंकज पुष्कर
4. श्री पवन कुमार शर्मा
5. श्री अजेश यादव
6. श्री महेन्द्र गोयल
7. श्री सुखवीर सिंह दलाल
8. श्री ऋतुराज गोविन्द
9. श्री रघुविन्द्र शौकीन
10. श्री जितेन्द्र सिंह तोमर
11. श्री राजेश गुप्ता
12. श्री अखिलेश पति त्रिपाठी
13. श्री सोमदत्त
14. सुश्री अलका लाम्बा
15. श्री आसिम अहमद खान
16. श्री विशेष रवि
17. श्री हजारी लाल चौहान
18. श्री शिव चरण गोयल

19. श्री गिरीश सोनी
20. श्री मनजिंदर सिंह सिरसा
21. श्री राजेश ऋषि
22. श्री नरेश बाल्यान
23. श्री आदर्श शास्त्री
24. श्री गुलाब सिंह
25. सुश्री भावना गौड़
26. श्री सुरेन्द्र सिंह
27. श्री विजेन्द्र गर्ग
28. श्री प्रवीण कुमार
29. श्री मदन लाल
30. श्री सोमनाथ भारती
31. श्रीमती प्रमिला टोकस
32. श्री नरेश यादव
33. श्री अजय दत्त
34. श्री दिनेश मोहनिया
35. श्री सौरभ भारद्वाज
36. सरदार अवतार सिंह कालकाजी
37. श्री सही राम
38. श्री नारायण दत्त शर्मा
39. श्री अमानतुल्लाह खान
40. श्री राजू धिंगान
41. श्री मनोज कुमार
42. श्री नितिन त्यागी
43. श्री ओम प्रकाश शर्मा
44. श्री एस.के. बग्गा
45. श्री अनिल कुमार बाजपेयी
46. श्री सरिता सिंह
47. मो. इशराक
48. श्री श्रीदत्त शर्मा
49. चौ. फतेह सिंह
50. श्री जगदीश प्रधान
51. श्री कपिल मिश्रा

दिल्ली विधान सभा

की

कार्यवाही

सत्र–6 भाग (1) मंगलवार, 10 अक्तूबर, 2017 / 18 आश्विन, 1939 (शक) अंक–61

सदन प्रातः 11.30 बजे समवेत हुआ।

माननीय अध्यक्ष महोदय (श्री राम निवास गोयल) पीठासीन हुए।

अध्यक्ष महोदयः सभी माननीय सदस्यों का हार्दिक स्वागत।

माननीय सदस्यगण, आज माननीय सदस्य श्री सही राम जी का जन्म दिन है। मैं इस अवसर पर उनको अपनी ओर से तथा पूरे सदन की ओर से हार्दिक बधाई देता हूं तथा कामना करता हूं कि वे अपने व्यक्तिगत तथा राजनीतिक जीवन में नई उंचाइयां प्राप्त करें।

माननीय अध्यक्ष द्वारा व्यवस्था

मुझे कुछ माननीय सदस्यों से नियम–54 और नियम–55 के अंतर्गत सूचनाएं प्राप्त हुई हैं।

श्री सुरेन्द्र सिंहः अध्यक्ष महोदय, एक बहुत ही गंभीर विषय है जो सामने आया है, सैनिकों से जुड़ा हुआ।

अध्यक्ष महोदयः मैं ये विषय जरा पूरा कर लूं कमांडो जी, मैं विषय पूरा कर लूं।

मुझे कुछ माननीय सदस्यों से नियम–54 और नियम–55 के अंतर्गत सूचनाएं प्राप्त हुई हैं। विषयों के महत्व को ध्यान में रखते हुए मैट्रो के किराये पर चर्चा तथा माननीय उपराज्यपाल महोदय के संदेश को सूचीबद्ध किया गया है। आज कार्यसूची में सूचीबद्ध विषयों के अतिरिक्त किसी अन्य विषय पर विचार नहीं किया जा सकता। इसलिए किसी भी सूचना को मैं स्वीकार नहीं कर पा रहा हूँ।

मैं माननीय सदस्यों का ध्यान नियम–291 एवं नियम–293 की ओर दिलाना चाहता हूं जिसके अनुसार अध्यक्ष का निर्णय अंतिम होता है तथा इस पर कोई आपत्ति नहीं की जा सकती।

हां, बताइये क्या कह रहे हैं कमांडो जी?

श्री सुरेन्द्र सिंहः अध्यक्ष महोदय, अभी हाल ही में जो अरूणाचल प्रदेश के अंदर एक हैलीकॉप्टर क्रेश हुआ, उसके संबंध में मैं अपनी बात रखना चाहता हूं।

अध्यक्ष महोदयः उस पर सदन संवेदना प्रकट कर चुका है।

श्री सुरेन्द्र सिंहः नहीं, जो हाल ही में जो शहीदों के साथ जो उनके यहां पार्थिव शरीरों को लाया गया, उनके साथ में बहुत ही ज्यादा अनजस्टिस हुआ है और पूरे देश के सैनिक तथा पूरी जनता उसमें जवाब चाहती है कि इस प्रकार क्यों हुआ? उन शवों को कार्टनों में बांध बांध के, गठरियों में बांध बांध के लाया गया।

अध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से इस सदन का ध्यान एक बहुत ही गंभीर विषय की तरफ दिलाना चाहता हूं। छह अक्टूबर 2017 को अरूणाचल प्रदेश के तवांग नामक स्थान पर वायुसेना के हेलीकॉप्टर के दुर्घटनाग्रस्त हो जाने से भारतीय सेना और वायुसेना के सात जवान उसके

अंदर शहीद हुए। उनके पार्थिव शवों को लाने की व्यवस्था की गई। वह बहुत ही निंदनीय है और गंभीर विषय है कि आज भी हमारे शहीदों के पार्थिव शरीरों को लाने के लिए कोई उचित व्यवस्था केन्द्र सरकार नहीं कर पाई है। देश के लिए जान न्यौछावर करने वाले शहीदों को इस तरह गत्ते के डिब्बों में बंद करके लाया गया। उससे जवानों की शहादत नहीं, पूरा देश शर्मसार हुआ है। मैं एक सैनिक हूं और मैं अपना आधा जीवन भारतीय सेना की सेवा बिता चुका हूं। मैं इस कृत्य की घोर निंदा करता हूं जिस तरह से इन सैनिकों की शहादत का अपमान हुआ है।

अध्यक्ष महोदयः कन्क्लूड करिये कमाण्डो जी, कन्क्लूड करिये।

श्री सुरेन्द्र सिंहः वह पूरी तरह निंदनीय है।

अध्यक्ष महोदयः कन्क्लूड करिये कमाण्डो जी, कन्क्लूड करिये।

श्री सुरेन्द्र सिंहः इसका देश के सैनिकों के मनोबल बहुत प्रभाव पड़ा है। सैनिकों के लिये उसके देश का सम्मान सर्वोपरि होता है। वह अपना पूरा जीवन देश की सेवा में समर्पित कर देता है। शहीदों ने देश के लिए अपना सर्वस्व न्यौछावर कर दिया है अपने प्राणों की आहुति देकर लेकिन एक तरह से उनकी शहादत के साथ प्रशासन के संबंधित अधिकारी और केन्द्र सरकार ने खिलवाड़ किया है। किसी शहीद के साथ ऐसे असभ्य व्यवहार की कल्पना भी नहीं की जा सकती। उसका पार्थिव शव इस ढंग से अव्यवस्थित प्रकार...

अध्यक्ष महोदयः हो गया विषय। कन्क्लूड करिये प्लीज।

श्री सुरेन्द्र सिंहः निंदा की जाती है। इस घटना से कारगिल युद्व के शहीदों व जवानों के ताबूत घोटाले की याद ताजा कर दी है। उस समय भी केन्द्र में भारतीय जनता पार्टी की सरकार थी। आज भी उसी पार्टी की

सरकार है जिसके शासन काल में शहीदों के साथ हुआ बहुत बड़ा मजाक हुआ। उसको देखकर प्रत्येक नागरिक शर्मिदा हुआ है। मैंने अपने सैनिक जीवन में साथियों को...

अध्यक्ष महोदयः कमांडो जी, अब कन्क्लूड करिये प्लीज।

श्री सुरेन्द्र सिंहः अपनी आखों के सामने शहीद होते देखा है। कन्क्लूड करिये कमांडो जी, अब इसको कन्क्लूड करिये, हो गया।

श्री सुरेन्द्र सिंहः दुःख के सागर में डूबते हुए शहीदों के परिवारों के लिए...

अध्यक्ष महोदयः कन्क्लूड करिये कमांडो जी, अब इसको कन्क्लूड करिये, हो गया।

श्री सुरेन्द्र सिंहः बहुत बड़ा सहारा किया है, सम्मान मिलता है। प्रेरणा में शहीद सैनिकों का सिर गर्व से ऊंचा खड़ा होता है।

... (व्यवधान)

श्री सुरेन्द्र सिंहः इससे केन्द्र सरकार के अनुरोध करूंगा कि अपने स्तर पर ... (व्यवधान)

अध्यक्ष महोदयः अब कमांडो जी इसको कन्क्लूड करिये, कमांडो जी। ... (व्यवधान)

श्री सुरेन्द्र सिंहः इस प्रकार से अपना देश का सैनिक प्राण न्यौच्छावर करने के लिए हमेशा तैयार रहता है।

अध्यक्ष महोदयः कमांडो जी, इसको कन्क्लूड करिये।

अध्यक्ष महोदयः चाहे देश के अंदर पीस हो या काउन्टर इन्सर्जेन्सी हो या बाहरी दुश्मनों के साथ मुकाबला हो।

अध्यक्ष महोदयः कमांडो जी, ये विषय हो गया, कन्क्लूड कीजिए।

श्री सुरेन्द्र सिंहः जब देश के सैनिक पाकिस्तान में घुसकर सर्जिकल स्ट्राइक करते हैं...

अध्यक्ष महोदयः कमांडो जी, बैठ जाइये। अब बैठिए प्लीज। विषय हो गया। बैठिए अब।

अध्यक्ष महोदयः कमांडो जी ये विषय हो गया कमांडो जी।

श्री सुरेन्द्र सिंहः जब देश के सैनिक पाकिस्तान में घुसकर सर्जिकल स्ट्राइक करते हैं

... (व्यवधान)

अध्यक्ष महोदयः विषय हो गया बैठिये। अब विषय हो गया। आपकी भावनाओं से सदन सहमत है, आप बैठिये। मैं मानता हूं आपकी भावनाओं से...

... (व्यवधान)

अध्यक्ष महोदयः आप बैठ जाइये प्लीज। नहीं, अब हो गया। अब ये भाषण नहीं हो सकता। सदन आपकी भावनाओं से सहमत हैं, बैठ जाइये प्लीज, बैठिये।

... (व्यवधान)

अध्यक्ष महोदयः प्लीज कमांडो जी, मैं प्रार्थना कर रहा हूं, बैठिये प्लीज।

... (व्यवधान)

अध्यक्ष महोदयः कमांडो जी, मैं प्रार्थना कर रहा हूं, बैठिये प्लीज।

... (व्यवधान)

श्री सुरेन्द्र सिंहः देश की जनता को खदेड़ा जाता है तो वो पूरे देश में घूम घूम के उसका श्रेय लेते हैं, पर उन सैनिकों के साथ जो उनके साथ जब उनके पार्थिव शरीरों के लाने की बात है तो सरकार उनके साथ बिल्कुल नहीं खड़ी है।

अध्यक्ष महोदयः कमांडो जी, आपका विषय आ गया है।

श्री सुरेन्द्र सिंहः उसके ऊपर कोई भी किसी प्रकार का तर्क नहीं आया है। मैं एक सैनिक हूं।

अध्यक्ष महोदयः कमांडो जी, देखिये मैं बार बार कह रहा हूं, आप नहीं मान रहे हैं। बैठ जाइये प्लीज, बैठ जाइये। कमांडो जी, बैठिये, हो गया विषय ये। भई देखिये, ये बहस का मुददा नहीं है।

... (व्यवधान)

अध्यक्ष महोदयः नहीं, ये बहस का मुददा नहीं है, कमांडो जी ने रख दिया। मैं समझता हूं, उनकी भावनाओं से सदन सहमत है।

... (व्यवधान)

अध्यक्ष महोदयः मैं स्वयं उनकी भावनाओं से सहमत हूं, सदन सहमत है।

... (व्यवधान)

अध्यक्ष महोदयः नहीं, अब हो गया।

... (व्यवधान)

अध्यक्ष महोदयः मैं किसी को समय नहीं दे रहा हूं बोलने के लिए।

... (व्यवधान)

अध्यक्ष महोदय : नितिन जी बैठिये प्लीज।

... (व्यवधान)

अध्यक्ष महोदयः सही राम जी, अपनी कुर्सी पर चलिये आप।

... (व्यवधान)

अध्यक्ष महोदयः नहीं दलाल जी, नहीं। आप कुर्सी पर चलिये अपनी। ये तरीका ठीक नहीं है वैल में आने का। नहीं, आप कुर्सी पर चलिये। नहीं, मैं इसको....

... (व्यवधान)

अध्यक्ष महोदयः कुर्सी पर चलिये आप। नहीं, आप अंदर चलिये। मैंने देखा है सारा। मैंने सब देखा हुआ है। मैंने सारा, अखबारों में आया, मैंने देखा है। आप सीट पर जाइये।

... (व्यवधान)

अध्यक्ष महोदयः कमांडो जी, आप बैठ जाइये। देखिये....

... (व्यवधान)

अध्यक्ष महोदयः कमांडो जी, बैठिये। आपकी बात आ गई, सदन के सामने आ गई है। आप बैठ जाइये, मैं प्रार्थना कर रहा हूं, बैठ जाइये। मैं कोई इजाजत नहीं दे रहा आपको प्लीज।

... (व्यवधान)

अध्यक्ष महोदयः कमांडो जी, प्लीज बैठिये । कमांडो जी, प्रार्थना कर रहा हूं, बैठ जाइये। विषय आ गया।

अब संजीव झा जी। माननीय सदस्य दिल्ली मैट्रो के किराये पर लगातार वृद्वि के संबंध में मंत्री महोदय का ध्यान आकर्षित करेंगे।

श्री संजीव झाः धन्यवाद, अध्यक्ष महोदय।

... (व्यवधान)

अध्यक्ष महोदयः भई कमांडो जी, नहीं, अब नहीं। मैं कोई इजाजत नहीं दे रहा, बैठिये। अब प्लीज।

श्री संजीव झाः धन्यवाद, अध्यक्ष महोदय।

... (व्यवधान)

अध्यक्ष महोदयः कमांडो जी, ये तरीका ठीक नहीं है। नहीं, ये तरीका ठीक नहीं है। ये तरीका बिल्कुल ठीक नहीं है। बातचीत हो गई है। आपका विषय आ गया। ये तरीका ठीक नहीं है। बैठिये, अब प्लीज। मैं रिक्वेस्ट कर रहा हूं। बैठ जाइये प्लीज, कमांडो जी। हो गया आपका, विषय आ गया, आप बैठिये। अब विषय आ गया सदन का ध्यान आपने आकर्षित कर लिया। आपकी बात पर सिरसा जी खड़े हो गये, तो इसका मतलब सदन का ध्यान आकर्षित हो गया। आप बैठ जाइये अब। आप बात की गंभीरता को समझिये, बैठ जाइये।

... (व्यवधान)

जगदीप जी, बैठाइये जरा, ये ठीक नहीं है। बैठिये।

... (व्यवधान)

अध्यक्ष महोदयः मैंने अभी सुनाया ना पढ के, फिर दोबारा सुना देता हूं।

मुझे कई माननीय सदस्यों से नियम 54 और नियम–55 के अंतर्गत सूचनाएं प्राप्त हुई हैं। विषयों के महत्व को ध्यान में रखते हुए मैट्रो के किराये पर चर्चा तथा माननीय उपराज्यपाल महोदय के संदेश को सूचीबद्ध किया गया है। आज कार्यसूची में सूचीबद्ध विषयों के अतिरिक्त किसी अन्य विषय पर विचार नहीं किया जा सकता। इसलिए किसी भी सूचना को मैं स्वीकार नहीं कर पा रहा हूँ।

मैं माननीय सदस्यों का ध्यान नियम–291 एवं 293 की ओर दिलाना चाहता हूं जिसके अनुसार अध्यक्ष का निर्णय अंतिम होता है तथा इस पर कोई आपत्ति नहीं की जा जायेगी।

... (व्यवधान)

अध्यक्ष महोदयः नही, हो गया प्लीज। हां, झा साहब।

ध्यानाकर्षण (नियम–54)

श्री संजीव झाः जी, बहुत बहुत धन्यवाद, अध्यक्ष महोदय।

... (व्यवधान)

अध्यक्ष महोदयः हां, कोई बात नहीं, सारी दिल्ली की दो करोड़ जनता दुःखी है। दो करोड़ जनता दुःखी है। चलिये झा जी, प्लीज करिये।

श्री संजीव झाः धन्यवाद अध्यक्ष महोदय कि आपने मुझे कुछ...

अध्यक्ष महोदयः करिये, शुरू करिये।

श्री संजीव झाः बहुत बहुत धन्यवाद अध्यक्ष महोदय कि आपने मुझे फिर से इस गंभीर विषय पर बोलने का मौका दिया। सुबह में अपने कुछ साथियों से मिला जो लोग मैट्रो में सफर करते हैं, उन्होंने बताया कि आज मैट्रो बिल्कुल खाली सा था। इसका मतलब है कि ये फेयर हॉइक से लोग मैट्रो पर सफर करना कम कर दिया, एंट्री कम हो रही है।

अध्यक्ष महोदय, जब ये निर्णय आया था, तब मैं अपने कुछ विधायक साथियों के साथ माननीय जरनैल भाई थे, प्रवीण देशमुख भाई थे, हम लोग डीएमआरसी चीफ से हमने समय मांगा था। चूंकि वो उस समय दिल्ली में उपलब्ध नहीं थे तो उन्होंने डायरेक्टर, ऑपरेशन को अपना प्रतिनिधि बनाया। हम लोग उनसे मिले। हमने उनसे दो गुजारिश करी थी। हमने ये कहा था कि आज जब हम लोग मैट्रो का फेयर बढ़ा रहे हैं, पिछले दो साल से हम लोग पर्यावरण को लेकर बहुत चिंचित हैं। दिल्ली सरकार ओड—इवन लाई। हमने खूब प्रमोशन किया, हमने खूब जनता को कहा कि पब्लिक ट्रांसपोर्ट का उपयोग आप लोग कीजिए। आज अगर मान लीजिए अगर ये मैट्रो फेयर बढ़ता है तो सबसे बड़ा नुकसान होना है, वो होना है कि जैसा आंकड़ा था कि 30 लाख लगभग मैट्रो की राइडरशिप थी। जब ये मई में मैट्रो फेयर बढ़ा तो राइडरशिप घटके लगभग 25 लाख के करीब रह गयी। मेरा ये कहना है कि ये जो चार पांच लाख राइडरशिप घटा, ये कहां गया? इसका मतलब वो सड़क पे प्राईवेट वेहिकल्स के साथ सड़क पर चल रहा है। इसका मतलब है कि सड़क पे कंजेशन बढ़ रहा है, सड़क पर प्रदूषण, पॉल्यूशन बढ़ रहा है।

हर बार नवम्बर—दिसम्बर या ठंड का जब मौसम आता है तो प्रदूषण का लेबल काफी बढ़ जाता है। पिछली बार भी बहुत कोशिश की गयी थी कि किसी तरह से प्राईवेट वेहिकिल्स को सड़क पे कम किया जाये। लेकिन

इस बार अगर मैट्रो फेयर बढ़ता है तो कंजेशन और पॉल्यूशन सड़कों पर बढ़ेगा।

दूसरा निवेदन हमने उनसे किया था, हमने कहा था कि आप जो ये लॉजिक दे रहे हैं कि फेयर बढ़ाने से हमारा रेवेन्यू बढ़ जायेगा तो सिम्पल मैथमेटिकल कलकुलेशन कहता है कि राइडरशिप घटता है और आपका रेवेन्यू घटेगा और रेवेन्यू बढ़ाने के वर्ल्ड में कई सारे कंट्री ने अपने अपने कमर्शियल मॉडल अपनाया। हांगकांग का मॉडल हमारे सामने है कि जरूरी नहीं है कि आप फेयर हाइक करके रेवेन्यू बढ़ा सकते हैं? रेवेन्यू बढ़ाने के लिए आपको एडवर्टीजमेंट के जरिये या उनके पास जैसे स्पेस एवेलेबल है, उनको यूज करके, जो हांगकांग में किया गया, जो बार बार मेंशन भी किया गया है, उस तरह से आप रेवेन्यू बढ़ा सकते हैं। मेरा ये कहना है कि मुझे एक चीज समझ में नहीं आती। आप सब को बेहतर याद होगा जब एयरपोर्ट मैट्रो चला था। एयरपोर्ट मैट्रो में रिलायंस का लगभग 165 करोड़, डेटा तो मुझे याद नहीं है। 165– 200 करोड़ का नुकसान हुआ था और रिलायंस इंफ्रा न केवल छोड़ के भाग गया, मैट्रो को गाली भी दी। सरकार ने उसको इमेडियेटली टेक ओवर किया और उसको कंपनसेट किया तो मेरा ये कहना है कि आपको प्राईवेट के लिए तो कंपनसेट करने के लिए पैसा है, लेकिन अगर दिल्ली की जनता प्रभावित हो रही है तो फिर आपको फिर सोचने के वक्त नहीं है, उतना नहीं चाहते हैं आप। ये सरकार, साबित होता है, ये सरकार पॉकेटमार सरकार है। ये सरकार जनता का पॉकेट मारना, जनता से पैसा लूट रहा है।

मेरा ये कहना है अध्यक्ष महोदय, हां बड़े बड़े नारे दिये गये थे, 'अबकी बार मोदी सरकार' और अब कहेंगे, 'अबकी बार पॉकेटमार सरकार।' मेरा ये कहना है अध्यक्ष महोदय, मैं एक डेटा देख रहा था कि 2016 से 2017

में जो बिजनेस इंटरपेन्योर हैं, उनके कैपिटल कितने बढ़े हैं। मैंने ये देखा कि मुकेश अंबानी जी का 2016 में, ये बड़ा सरप्राइजिंग है। मुकेश अंबानी जी का 2016 में जो अर्निंग थी, वो 22.7 इयर्स बिलियन डॉलर था। 20017 में बढ़कर 38 बिलियन डॉलर हो गया। यानि कमोवेश 75 परसेंट की इंक्रीमेंट है। मैंने अंबानी का देखा 6.3 इयर्स बिलियन डॉलर से बढ़के ये 11 बिलियन डॉलर हो गया तो मेरा ये कहना है, मेरा ये कहना है कि आज नोटबंदी से आज जीएसटी से व्यापारी परेशान हैं, नुकसान में हैं पर इनका बिजनेस दिन दूना, रात चौगुना बढ़ रहा है। आज इसके कई सारे कारण हैं। अगर हम ये गिनाने लगें कि किस तरह से अंबानी और अदानी को सरकार फायदे पहुंचा रही है तो ये पूरा दिन बीत जायेगा। तो मेरा ये कहना है कि बड़े बड़े वादों के साथ ये सरकार आयी थी। आज जब ये वोट लेने का वक्त था तो बड़े बड़े अब, 'बहुत हुई मंहगांई की मार, अबकी बार मोदी सरकार।' बहुत हुआ भ्रष्टाचार, अबकी बार मोदी सरकार।' अब अब उल्टा हो गया कि 'बहुत परेशान हैं जनता इनकी मंहगाई की मार से, बस करो अब मोदी सरकार से।' तो मेरा ये कहना है अध्यक्ष महोदय कि आज आप किसके लिए काम कर रहे हैं? ऐसा क्यों कर रहे हैं? मैं कह रहा हूं कि दिल्ली की जनता, दिल्ली के चुने हुए विधायक, दिल्ली सरकार ये चाह रही है कि मैट्रो का फेयर न बढ़े, लेकिन उसके वाबजूद आप ये कह रहे हैं कि नहीं, मैट्रो का फेयर बढ़ेगा। बार बार ये हवाला दिया जा रहा है कि फेयर फिक्सेशन कमेटी की रिपोर्ट बाईंडिंग है। वो कह रहे हैं कि आज सेक्शन–37 का हवाला देकर ये बार बार कह रहे हैं कि फेयर बिजनस कमेटी ने जो रिपोर्ट दिया, वो बाईंडिंग है, वो होगा ही। लेकिन उसी फिक्सेशन कमेटी में आपने खुद ही वॉयलेशन किया। आठ महीने, कभी पहले रिपोर्ट आयी थी कि 2016 में क्यों नहीं बढ़ा, तो आठ महीने बाद क्यों बढ़ाया? तो फेयर फिक्सेशन कमेटी की रिपोर्ट, ये बाईंडिंग थी कि ज्यों ही ये रिपोर्ट आता

बिल्कुल नहीं लागू होना चाहिए तो उससे आपने वॉयलेट कर दिया। आज दिल्ली की जनता तो प्रभावित हो रही है तो आप कह रहे हैं कि हम ये फेयर फिक्सेशन कमेटी की रिपोर्ट है, अब इसको नहीं कर सकते। बल्कि सेक्शन 87 में बकायदा व्यवस्था की गयी है कि इस के बाद की स्थिति में सैंट्रल गवर्नमेंट इंटरवीन कर सकता है। तो मेरा ये कहना है, मैं ये बहुत सोच रहा था कि आखिर क्या फायदा है! वैसे तो नुकसान है। दिल्ली की जनता खिलाफ हो जाएगी, देश की जनता खिलाफ हो जाएगी, लेकिन उसके बावजूद इतना बड़ा रिस्क क्यों ले रहे हैं? बहुत मैंने खोजबीन किया तो कुछ चीजें हाथ लगी। मजे की बात है अध्यक्ष महोदय, मैंने कुछ रिपोर्ट निकाला। ओला, ई—रिक्शा लांच कर रहा था। खुद ओला के प्रमोटेड ई—रिक्शा पे प्रधानमंत्री जी गये थे। यहां वो एक फोटो भी है। मैं लेके आया था, ये फोटो है। इसमें ओला के ब्रांड एम्बेसडर बन रहे हैं प्रधानमंत्री जी। जब स्वच्छता अभियान की बात चली तो प्रधानमंत्री जी ने चिट्ठी लिखा है इनके ओनर को कि आप हमें सहयोग कीजिए। ये अच्छी बात है, लिखना चाहिए, पर मेरा ये कहना है कि इन लोगों को चिट्ठी लिखा आपने तो इसका मतलब है कहीं न कहीं से, कोई न कोई तो रिश्ता तो है। इसका मतलब है कि ये जान—बूझकर ये चाह रहे हैं कि मैट्रो फेयर का इतना हाइक कर दो कि कमर्शियल वेहिकिल्स सड़क पे आ जायें, कमर्शियल वेहिकल को फायदा हो। तो मेरा ये कहना है अध्यक्ष महोदय, कि आज दिल्ली की जनता बहुत परेशान है। अचानक आज आसाम का एड फिल्म देख लेंगे, मुझे लगता है जितने साल मैट्रो चल रहा है फिफ्टी परसेंट राइडरशिप कम जाएगी तो अल्टीमेटली मैट्रो को नुकसान होना है, लेकिन ये सब जो बात हम समझ रहे हैं, जो बात कॉमनमेन समझ रहा है, वो बात सेंट्रल गवर्नमैंट नहीं समझ रहा है, ऐसा नहीं है, इनका अपना कमर्शियल बेनिफिट है। इन लोगों को कहीं न कहीं से सांठ—गांठ है और इसीलिए

जान–बूझकर आम जनता को परेशान करके और ये जो बड़े बड़े इनका, जिनका मैंने आपको डेटा दिया कि किस तरह से इनका बिजनेस बढ़ रहा है, ये बिजनेस बढ़ाने के लिए सरकार काम कर रही है तो मेरा एक कहना है अध्यक्ष महोदय, कि हमने जो भी हो सकता है, हमने किया। हम सारे विधायक साथी, कल भी चर्चा हुई हाउस में, हाउस बैठा, हम लोग जाकर के मैट्रो चीफ से मिलने की बात करी, हमने उनसे निवेदन किया, दिल्ली सरकार ने, दिल्ली सरकार के ट्रांसपोर्ट मिनिस्टर खुद भी, मुख्यमंत्री जी ने लिखा कि भई, जो कंपनसेशन होता है, उसका फिफ्टी परसेंट देने के लिए हम तैयार हैं। लेकिन उसके बावजूद भी अगर इस पे लगाम नहीं लगाई गई, अगर मैट्रो का फेयर हाईक ये यू हीं अनवरत रहा तो अब सड़क पर आने के सिवाय दूसरा कोई रास्ता नहीं है। तो मुझे ये लगता है कि चाहे जो भी करना पड़े, सड़क पर आंदोलन करना पड़े, जनता के बीच में जाना पड़े, इनको घेरना पड़े, दिल्ली की जनता ये नहीं चाह रही है कि इस तरह से उनके पॉकेट पर बोझ बढ़े। मेरी विधान सभा बुराड़ी कांस्टिटयुएंसी है। मैं पहले यहां से 10 रूपये में पहुंचता था जीटीबी अब वो 20 रूपये में पहुंचूंगा यानि आने जाने में वहां तक पहुंचने में जो पहले खर्चा मेरा 30 रूपये हुआ करता था अब वो 100 रूपये हो जाएगा तो मेरा ये कहना है अध्यक्ष महोदय कि आज ऐसे ही देश में लोग नोटबंदी से परेशान हैं, जीएसटी से परेशान है।

मैं एक डेटा देता हूं, एक बड़ा अच्छा उदाहरण है, मैं अभी अपने होम टाउन गया था। बिहार में बहुत बाढ़ आई। वहां एक गांव में एक परिवार सारी उसकी प्रॉपर्टी बह गई, सब कुछ खत्म हो गया। तीन बच्चे थे, वो तीन बच्चों के साथ दिल्ली आया, पहले जहां नौकरी करता था, जब वो दिल्ली आया तो पता चला कि उसकी कंपनी बंद हो गई। मेरे पास कुछ लोग आए थे कि पिछले दो महीने से वो दिल्ली में सड़कों पर भीख मांग

रहा है, कोई चारा नहीं है उसके पास। तो मैं ये कह रहा हूं कि आपने देश को नोटबंदी करके, जीएसटी करके दिल्ली की जनता को, दिल्ली के प्रदेश के व्यापारियों को आपने परेशान कर रखा है और इस तरह से अगर महंगाई बढ़ाएंगे आप तो कैसे दिल्ली की जनता अपना घर चलाएंगी, अपना परिवार चलाएंगी! तो इसीलिए अध्यक्ष महोदय, मैं इसीलिए इस गंभीर विषय को आपके जरिए मंत्री जी के संज्ञान में लाना चाहता था कि मैट्रो फेयर के हाईक को रोकने के लिए जो भी कोशिश हो सकती है, हम उनके साथ करें, हमें वो करना चाहिए।

बहुत–बहुत धन्यवाद कि आपने मुझे बोलने का मौका दिया।

अध्यक्ष महोदयः सौरभ भारद्वाज जी।

श्री सौरभ भारद्वाजः अध्यक्ष जी, बहुत–बहुत धन्यवाद कि आपने इस महत्वपूर्ण विषय पर मुझे बोलने का मौका दिया। संजीव भाई ने बड़ी अच्छी बात बताई कि क्या रिश्ता है केंद्र सरकार का मैट्रो के फेयर्स के साथ। मैट्रो के और अलग–अलग चीजें बताई कि अंबानी साहब की जो दौलत है, वो कई गुणा बढ़ गई। अदानी जी के बारे में भी कुछ दिनों पहले ऑस्ट्रेलिया की एक न्यूज एजेंसी ने खबर की थी कि उन्होंने भी मोदी जी के राज में गुजरात में बहुत पैसा कमाया और अभी भी काफी पैसे वो कमा रहे हैं। लोग कहते है वहां भी थोड़ा रिश्ता है।

ओला के बारे में जो बार–बार कहा जा रहा है कि ओला जो कंपनी है, उससे केंद्र सरकार का क्या रिश्ता है? ऐसे बहुत सारे हमारे सामने आंकड़े आए हैं जिसके अंदर ये बात साबित होती है कि अगर मैट्रो का किराया बढ़ता है तो जो शॉर्टर डिस्टेंसिस हैं खासकर कि 5 किलोमीटर, 10 किलोमीटर तक के जो डिस्टेंसिस थे, उसके लिए लोग उबर और ओला

या इस तरीके के जो छोटे कैब के जो एग्रीगेटर्स हैं, इनका जो व्यवसाय हैं, वो बढ़ेगा। उसका बड़ा कारण ये है कि ये जो ओला, उबर जो हैं, ये प्वाइंट टू प्वाइंट आपको कनेक्टिविटी पहुंचाते हैं, आपको अपने घर से उठाकर आपको जहां डेस्टिनेशन है, वहां पर पहुंचाते है और अगर आप उनके शेयरिंग का मॉडल देखेंगे तो शेयरिंग के मॉडल के अंदर अब जो है मैट्रो से सस्ता जो है, वो ओला का किराया पड़ेगा अगर आप शेयरिंग के अंदर करेंगे तो जाहिर तौर पर ये एक बड़ी पुरानी थ्योरी है कि अगर आपको किसी का धंधा बिठाना है या किसी का धंधा उठाना है तो उसके कॉम्पेटिटर्स का जो बिजनेस है, उसको आप खराब कीजिए। सेम मनीष सिसोदिया जी पहले बोलते थे कि जिन भी नेताओं के यहां बड़े–बड़े प्राइवेट स्कूल थे या जिनकी भी प्राइवेट स्कूलों के अंदर, उनके कारोबार के अंदर दखल रहा, उनकी ये साजिश रही कि सरकारी स्कूलों का जो लेवल है, उसको धीरे–धीरे गिरा दिया जाए, स्टेण्डर्ड गिरा दिया जाए, प्राइवेट स्कूलों का धंधा अपने आप चमकेगा। मुझे लगता है बिल्कुल उसी नियम पर काम करते हुए जो सरकारी एन्टरप्राइजेज हैं जैसे कि डीएमआरसी है, उसको नुकसान पहुंचाया जा रहा है, उसको कमर्शियली कंज्यूमर के लिए अनवॉएअबल किया जा रहा है ताकि लोगों को जो है, अट्रैक्शन जो है, उनका ओला की तरफ बढ़ेगा और ऐसे बहुत सारी चीजें आई हैं कि हैरानी की बात ये है कि 'स्वच्छ भारत' के लिए प्रधानमंत्री जी ओला के मिस्टर अग्रवाल को खत लिखते हैं। ओला के अग्रवाल जी तुरंत एक एप बना के वापस खत लिखते है कि हमने एप बना दी अब उस एप से जितने भी टॉयलेट्स हैं, वो हमारे टैक्सी ड्राइवर्स को उस एप के अंदर दिख जाएंगे, उससे 'स्वच्छ भारत' के अंदर बहुत बड़ा योगदान हो जाएगा। जैसे कि अगर उस एप में ना दिखते तो किसी ड्राइवर को सड़क पर कोई टॉयलेट दिखेगा ही नहीं। उस एप से ही वो ड्राइवर देखेगा। उसके बाद मैं और भी टि्वटर हैंडल

देख रहा था प्रधानमंत्री जी का, उसके अंदर बताया कि एक ओला का टैक्सी ड्राइवर था, नोटबंदी के समय कोई आदमी उसके पास पेटीएम लेकर गया तो उस ड्राइवर ने कहा, कोई बात नहीं साहब, ये नोटबंदी बहुत देश के लिए फायदेमंद है, तो अगर दो पैसे कम भी मिल जाएंगे तो भी मैं काम करूंगा और टिव्टर के अंदर प्रधानमंत्री जी ओला के उस ड्राइवर का गुणगान कर रहे हैं। फिर प्रधानमंत्री जी दुबारा ओला के अंदर सफर करते हैं और उनकी फोटो ओला के एग्रीगेटर के ऊपर दुबारा दिखाई जाती है तो ये कोई साधारण बात नहीं है कि देश का प्रधानमंत्री जिनके पास बहुत विषय हैं, विदेश में घूमने के अलावा भी बहुत विषय हैं देश में, उसके अलावा वो ओला के अंदर इतनी दिलचस्पी ले रहे हैं, एक प्राइवेट कंपनी के अंदर इतनी दिलचस्पी ले रहे हैं।

उसके बाद ये देखना में आता है कि ये जो प्राइस फिक्सेशन कमिटी है, इसकी जो रेकमेंडेशन थी, ये एमसीडी के चुनाव से पहले की रेकमेंडेशन है। अगर ये कहा जाता है कि इसके अंदर कोई पॉलिटिकल इंटरफेयरेंस नहीं है, कोई राजनीति नहीं है, इसके अंदर केंद्र सरकार का कोई दखल नहीं है तो ये ऐसा क्यों है कि ये जो दाम है, जो एमसीडी के चुनाव से पहले बढ़ने थे, उनको आठ महीने रोका जाता है क्योंकि उन्हें मालूम था कि अगर ये दाम उससे पहले बढ़ेंगे तो केंद्र सरकार की बदनामी होगी। एमसीडी के चुनाव के अंदर नुकसान होगा फिर जब एमसीडी का चुनाव हो जाता है फिर उसके दाम बढ़ाए जाते है तो इसके अंदर भी साजिश देखने में आ रही है और बार–बार ये कहना कि प्राइस फिक्सेशन कमिटी जो है, वो बाइंडिंग है। प्राइस फिक्सेशन कमिटी किसने बनाई है? कोई सृष्टि का निर्माण होते वक्त ब्रहमा जी ने तो नहीं बनाई थी। प्राइस फिक्सेशन कमिटी पार्लियामेंट के एक एक्ट के द्वारा ही बनी है ना। वो एक्ट हम ही

लोगों ने बनाया है। केंद्र सरकार दुबारा एक एक्ट ला सकती है। प्राइस फिक्सेशन कमिटी की अगर बाइंडिंग है तो उसको भी हटाया जा सकता है। ऐसा कोई बड़ा मजबूत काम नहीं है कि उसको करना बहुत ही मुश्किल है।

अध्यक्ष जी, मैं पहली बार एक चीज देख रहा था कि अब तक राजनीति के अंदर ये देखा जाता था कि डीटीसी के दाम बढ़ते थे, सरकार कहती थी, नहीं, दाम बढ़ाने बहुत जरूरी हैं और अपोजिशन कहती थी नहीं बढ़ने देंगे दाम। सरकार ऑटो रिक्शा के दाम बढ़ाती थी, सरकार कहती थी बहुत जरूरी है और ओपजिशन कहती थी, नहीं जी, कैसे बढ़ जाएंगे दाम, हम बढ़ने नहीं देंगे, वो ट्यूब लाईट फोड़ते थे, बसों के अंदर जाम करते थे, चक्का जाम करते थे और ये पहली बार ऐसा देखने में मिल रहा है कि एक चुनी हुई सरकार कह रही है कि दाम नहीं बढ़ने चाहिए और लीडर ऑफ अपोजिशन कह रहे हैं ऐसा कैसे हो जाएगा? दाम तो बढ़कर ही रहेंगे, दाम क्यों नहीं बढ़ने चाहिए? तो ये बड़ी अजीब देखने वाली बात है कि सरकार जो है, वो दाम घटाना चाहती है। सरकार कह रही है कि हमें दाम घटाना चाहिए। गरीब पब्लिक हैं, पब्लिक के ऊपर पैसे की मार वैसे ही पड़ी हुई है, जीएसटी की वजह से, नोटबंदी की वजह से हालात खराब है। राइडर्सशिप मैट्रो के अंदर कम हुई हैं। आप गरीब लोगों के बारे में सोचिए लेकिन ओपजिशन कहती है कि नहीं, ऐसा कैसे हो जाएगा। गरीबों के बारे में हम क्यों सोचेंगे? अरे! मैट्रो के बारे में सोचिए, उसके कमर्शियल मॉडल के बारे में सोचिए। प्राइस फिक्सेशन कमिटी के बारे में सोचिए।

कल भी अध्यक्ष जी, देखने में ये आया बड़ी सरप्राइजिंग बात है कि कल की जो बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स की जो मीटिंग हुई मैट्रो की, उसके अंदर जो दिल्ली सरकार के जो नॉमिनी थे, वो सारे के सारे कह रहे थे कि

भई, नहीं हमारे पास आदेश है सरकार की तरफ से, मुख्यमंत्री की तरफ से आदेश है कि ये जो दाम हैं, नहीं बढ़ने चाहिए और केंद्र सरकार के जितने भी नुमाइंदे थे। उन सबने ये कहा कि नहीं, ये दाम कैसे नहीं बढ़ने चाहिए, दाम जरूर बढ़ने चाहिए। तो ये तो बहुत ही हैरानी की बात है कि केंद्र के अंदर जो भाजपा की सरकार है, या भाजपा की ओपजिशन है, दिल्ली के अंदर ये खुलकर गरीबों का विरोध कर रही है। गरीबों के खिलाफ काम कर रहे हैं और मैट्रो का किराया बढ़ाने में बढ़–चढ़कर ये योगदान दे रहे हैं। इसके अंदर ओला को फायदा पहुंचाने के अलावा हमको और कोई साजिश नहीं दिखती कि ये ऐसा क्यों कर रहे है।

अध्यक्ष जी, एक और मैं खास चीज के बारे में आपका ध्यान दिलाना चाहूंगा। कल मैं पढ़ रहा था, एक शब्द आया टैम्पल एन्टरप्राइजेज, टैम्पल मतलब मंदिर और एन्टरप्राइजेज मतलब व्यवसाय जो पार्टी मंदिर के ऊपर अपनी हमेशा से राजनीति करती रही, उसी पार्टी के अध्यक्ष के बेटे ने अपनी कंपनी का नाम रखा, 'मंदिर व्यवसाय लिमिटेड,' टैम्पल इन्टरप्राइजेज लिमिटेड और मतलब कहीं न कहीं से जो दिल की बात है, वो ऐसा दिख गया कि भई मंदिर के नाम पर भी अब व्यवसाय किए जाएंगे और जो दूसरी कंपनी थी, उसका नाम था कुसुम। कुसुम का मतलब फूल। फूल किसका? कमल का तो और फिर कहते हैं, वो प्राइवेट इंडिविजुअल है। अरे! जिसके मन में, दिल में, दिन–रात मंदिर और कमल का फूल घूमता रहता हो, वो प्राइवेट इंडिविजुअल कैसे हो सकता है! अध्यक्ष जी, मेरा ये भी आपसे निवेदन रहेगा कि उस पर भी आप चर्चा कराइयेगा। बहुत–बहुत धन्यवाद।

अध्यक्ष महोदयः श्री मदन लाल जी, सुश्री अलका लाम्बा जी।

सुश्री अलका लाम्बाः धन्यवाद अध्यक्ष जी, अध्यक्ष जी ऐसा नहीं है कि मैं आज ही मैट्रो से दिल्ली विधान सभा आई हूं मैं अधिकतर मैट्रो का ही

इस्तेमाल करती हूं। आज हाउस 11 बजे का था थोड़ी देरी हुई तो आज मैंने फिर मैट्रो का इस्तेमाल किया और दो सौ रुपये का कूपन चार्ज करवाया और जो टिकट जोर बाग से मुझे दिल्ली विधान सभा पहूंचने में 17 रुपए की लगती थी, आज 27 रुपए की लगी और जब मैं मैट्रो स्टेशन दिल्ली विधान सभा ऊतरी जो मेरी चांदनी चौक विधान सभा में आता है। मुझे बहुत सी महिलाएं मिली वहां पर बहुत से छात्र मिले क्योंकि अगला स्टेशन ही दिल्ली विश्वविद्यालय का है। छात्रों की जेब पर बहुत बड़ा ये बोझ पड़ा है। मैंने आने का 30 रुपए भरा, जाने का 30 रुपया 60 रुपया रोज का, शायद मेरे जैसों के लिए बहुत बड़ी बात नहीं होगी लेकिन यह मेरी अकेली की हमारी बात नहीं है, ये उन सभी आम आदमी, आम लोगों की, गरीब मजदूर जितने लोग भी मैट्रो का इस्तेमाल करते हैं, ये उनकी बात है।

अध्यक्ष जी, अभी संजीव झा जी ने आपको बताया कि पूरा देश आर्थिक मंदी से गुजर रहा है, पैट्रोल–डीजल के दाम आसमान छू रहे हैं, वो भी उस समय पर जब अन्तर्राष्ट्रीय बाजार में तेल की कीमतें जो हैं, वो जो है, 40–50 डॉलर प्रति बैरल है, उसके बावजूद भी। ट्रक चालकों की दो दिन से हड़ताल है, महाराष्ट्र में। देश को कितना नुकसान होगा इन ट्रक चालकों की हड़ताल से, पैट्रोल–डीजल के दाम बढ़ने से दो हजार करोड़ का नुकसान इन दो दिनों में केवल इस देश को होने वाला है। जिम्मेदार कौन है? केन्द्र में बैठी मोदी सरकार, जिनकी कान में जूं तक नहीं रेंगती है। अगर ये हड़ताल आगे बढ़ी अध्यक्ष जी, तो मैं नहीं, कल टीवी की रिपोर्ट बता रही थी कि इसका असर ट्रकों की हड़ताल, जो पैट्रोल–डीजल के दाम बढ़ने से परेशान हैं, दो हजार करोड़ तो दो दिन का बता रहे हैं, अगर लम्बा चला तो उसका असर पूरे देश के ऊपर देखा जाएगा क्योंकि मंहगाई बढ़ेगी, सब्जी और फलों के दाम बढ़ेंगे लेकिन केंद्र की सरकार पर कोई

असर ही नहीं है। मोदी जी गुजरात के अपने चुनावी प्रचार में रोड शो में व्यस्त हो चुके हैं। बीजेपी के अध्यक्ष पूरे देश में प्रचार कर रहे हैं लेकिन उनकी सरकार केन्द्र की बीजेपी सरकार महंगाई को कम करने के लिए क्या कर रही है, उसके लिए इनके पास कोई जवाब नहीं है। हम ये चाहते हैं कि अडानी, अम्बानी का जिक्र तो संजीव झा जी ने किया कि किस तरह से पूरा देश आर्थिक मंदी में व्यापार उद्योग डूब रहे हैं। नोटबंदी और जीएसटी के बाद लेकिन हैरानी होती है जय शाह, कौन है! जय शाह श्री अमित शाह बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष के पुत्र हैं और उनके पुत्र जिन्होंने 2004 में अध्यक्ष जी कम्पनी खोली। मैं इसलिए इस बात का जिक्र कर रही हूं कि जनता सुने, जनता मैट्रो के दाम जो केंद्र की मोदी सरकार ने बढ़ाये हैं तानाशाह होके, उसकी चिन्ता मत करें, क्योंकि आपकी जेब में भी बहुत पैसा आ सकता है और वो फार्मूला कोई ओर नहीं, भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष श्री अमित शाह जी के बेटे इस देश को बताएं, मेरी अपील है उनसे। ताकि हमें चिन्ता ही ना हो कि पैट्रोल, डीजल के दाम बढ़ते हैं। अरे! बढ़ जाने दीजिए, किसी को चिन्ता नहीं है मैट्रो के दाम, क्या फर्क पड़ेगा क्योंकि हमें श्री अमित शाह जी के बेटे जय शाह जी फार्मूला बताने वाले हैं कि किस तरीके से बिना कोई व्यापार धन्धा किए, आप सिर्फ एक साल के अंदर अपनी डूबती कम्पनी को ऊपर ही नहीं लाते हैं, हजारों से 16 हजार गुणा करके करोड़ों रुपया कमा लेते हैं और वही फार्मुला हम भाजपा से निवेदन करेंगे, अमित शाह जी के बेटे से कि आप प्रेस कॉफ्रेस करिए और फार्मूला देश के बेरोजगार युवाओं को बता दीजिए, बहुत भला होगा आपका। जहां हम कहते हैं कि आपने बहुत बड़ा भ्रष्टाचार किया, मनी लांड्रिंग की है, आप कहते हैं कि नहीं, अमित शाह जी के बेटे जय शाह का व्यापार तो डूब गया, बन्द कर दिया, 2016 अक्तूबर में। तो चलिए यही मान लीजिए कि देश भर में, केन्द्र में मोदी सरकार आने के बाद भाजपा

के राष्ट्रीय अध्यक्ष का बेटा भी नहीं बचा, उसका भी व्यापार जो है, केन्द्र की मोदी सरकार ने ठप्प कर दिया। घाटे में कर दिया, नुकसान में कर दिया। कुछ तो बात मानिए या तो मानिए मनीलांड्रिंग की है, भ्रष्टाचार किया है कि 50 हजार से 80 करोड़ कमा जाते हैं रातरों रात में जय शाह जी और या फिर ये मान लीजिए कि हाँ, मोदी जी की नीतियों की वजह से केन्द्र सरकार की नीतियों की वजह से आज देश की अर्थव्यवस्था चरमरा रही है जीएसटी नोटबंदी के बाद पूरे देश का व्यापार ठप्प हो रहा है जिसमें अमित शाह जी के बेटे जय शाह जी का भी हो गया हो। लेकिन मैं उम्मीद करती हूं और सबसे बड़ी बात कि बाबा रामदेव ने काले धन के ऊपर बहुत डमरू बजाया, उन्होंने बहुत तांडव किया उन्होंने कि 2014 में केन्द्र की मोदी सरकार चाहिए। कहाँ है काला धन, बाबा रामदेव से पूछिए? क्यों इनपे देश की अर्थव्यवस्था जो चरमरा रही है व्यापार धन्धे बंद हो रहे हैं, उसका असर अदानी, अंबानी और बाबा रामदेव पर क्यों नहीं होता है? जय शाह के बाद मैं बाबा रामदेव जी से कहूंगी अध्यक्ष जी, आपसे भी निवेदन करूंगी कि आप लोगों को लेक्चर के लिए यहां बुलाते रहते हैं। बाबा रामदेव जी को और जय शाह जी को भी बुला लीजिएगा। कम से कम देश का भला हो जाएगा। हम विधायकों का तो भला हो ही जाएगा जिनकी सैलरी जो है आज भी जो है 50 और 80 हजार में घूम रही है और जिसका प्रचार इन भाजपाईयो ने करकर के बदनाम कर दिया कि लाखों रुपए की सैलरी हो चुकी है। कम से कम हमें ही वो फार्मुला बता दें, हम विधायकों का भी भला हो जाए। बाबा रामदेव जी जो योग सीखाते थे, जो योग से व्यापार में आ गए, मोदी सरकार के आने के बाद और जिनकी कमाई 25 सौ करोड़ रुपया बढ़ जाती है और जिनका व्यापार 2011–12 में 446 करोड़ था, वो आज 10 हजार करोड़ पहुंच गया है, केन्द्र की मोदी सरकार आने के बाद। मैं यही चाहती हूं जब केन्द्र की मोदी सरकार आने के बाद अदानी, अंबानी,

जय शाह, अमित शाह जी के बेटे और बाबा रामदेव का भला हो सकता है तो इस देश के गरीब–किसान, मरती जनता, बेरोजगार युवाओं का भी भला कर दीजिए, पूरा देश आपको दुआएं देगा।

अब मैं मैट्रो पर ही आती हूं अध्यक्ष जी। ये कहते हैं घाटे में जा रहे हैं, हम मान लेते हैं कि आप घाटे में जा रहे हैं पर ये देश आपका घाटा देखना चाहता है। ये उसका अधिकार है या नहीं, आप हमें दिखा दीजिए कागजों पर कि आपको क्यों घाटा हो रहा है, किन कारणों से हो रहा है और कितना हो रहा है, ये देश की जनता घाटा उठा लेगी, ये दिल्ली की जनता घाटा उठा लेगी, लेकिन आप उस घाटे के बारे में देश को बताएंगे नहीं, क्योंकि असलियत में आप घाटे में नहीं जा रहे, आपको घाटे की चिन्ता कब होती है, जब एयरपोर्ट मैट्रो स्टेशन जिसकी जिम्मेदारी रिलाएंस के पास थी, उन्होंने कहा हम घाटे में जा रहे हैं, हम एयरपोर्ट रिलाएंस जो मैट्रो स्टेशन है, उसे बंद कर देंगे। इनको कितना दर्द हुआ कि लोकसभा में जो है, रिलाएंस का दर्द जाहिर किया कि वो ऐसा हो रहा है लेकिन आज देश का अगर दिल्ली का मैट्रो घाटे में जा रहा है तो मैं ये कहूंगी ये कहाँ का तरीका है कि सरकार, केन्द्र सरकार की नाकामी, केन्द्र सरकार के भ्रष्टाचार की वजह से अगर कहीं कोई घाटा होता है तो उसका खामियाजा दिल्ली और देश की जनता क्यों भुगतेगी, मैं जानना चाहती हूं। अध्यक्ष जी, अगर इसमें आपकी नाकामी नहीं है, अगर इसमें आपका भ्रष्टाचार नहीं है और अगर केंद्र की सरकार फिर मानती है कि मैट्रो घाटे में जा रही है तो देश की जनता, दिल्ली की जनता की जेब से आप वसूल रहे हैं ना, उन्हें बताइए तो सही, कहां और कितना घाटा हो रहा है?

अध्यक्ष जी, डीएमआरसी का वायदा था कि एक साल में एक बार हम लोग बढ़ाएंगे और कभी भी सात प्रतिशत से ज्यादा नहीं बढ़ाएंगे। पहले तो

बात इनकी है कि इन्होंने आज तक फेयर फिक्सेशन कमेटी का आज तक गठन ही नहीं किया। 2009 से 2016 तक कोई कमेटी नहीं थी, कभी इनकी चिन्ता नहीं हुई कि फेयर बढ़ रहा है, फेयर बढ़ाने की जरूरत है, घाटे में जा रही है। कोई घाटा नहीं था, कोई फेयर फिक्सेशन कमेटी नहीं थी, कोई फेयर बढ़ाने की बात नहीं थी। अचानक 2016 में ये नींद से जागते हैं और देखते हैं अरे! हम तो घाटे में जा रहे हैं, जो हमें लगता है कि नहीं जा रहे। बिल्कुल घाटे में नहीं जा रहे, लेकिन ये कहते हैं, घाटे में जा रहे हैं। इसलिए 2016 में फेयर फिक्सेसन कमेटी का गठन रातों रात हो जाता है और वो बैठ के ये तय कर देते हैं कि अब हम फेयर के ऊपर बात करेंगे और फेयर कम करने पर बात नहीं, फेयर बढ़ाने पर बात करते हैं। हमेशा जब भी ये करेंगे और 10 रुपया इन्होंने अभी मई में, पहले कहते थे साल में एक बार बढ़ेगा। अब 6 महीने में दूसरी बार अध्यक्ष जी, अगर एक परिवार के 4 सदस्य सफर करें, 10 और 10, 20 रुपए बढ़े, जाने के बीस आने के बीस यानि की एक आम आदमी के ऊपर 40 रुपया एक दिन का बोझ आ गया जो बढ़ाया है और अगर वो अपनी पत्नी के साथ ट्रैवल कर रहा है, तो आप सोचिए, 80 रुपए अगर उसके आगे 4 बच्चे हैं तो आप सोचिए कितना बोझ इस मंहगाई में हम इस गरीब जनता के ऊपर डाल रहे हैं!

अध्यक्ष जी, मेरे यहां एक बात साफ है। हमें इसे हल्के में नहीं ले रहे। आज मेरी ही विधान सभा में, चांदनी चौक मैट्रो स्टेशन आता है, जामा मस्जिद मैट्रो स्टेशन आता है, सिविल लाइन्स मैट्रो स्टेशन, विधान सभा मैट्रो स्टेशन, कशमीरी गेट, चावड़ी बाजार, दिल्ली गेट, लाल किला, आजाद पुर ये सारे 8 से 9 मैट्रो स्टेशन सिर्फ और सिर्फ चांदनी चौक विधान सभा में आते हैं। आज जनता आराम से नहीं बैठी, जनता सड़कों पर सारा दिन निकलेगी और मजबूर करेंगे, सदन से लेके सड़क तक कि केन्द्र की सरकार,

केन्द्र के मंत्री श्री पुरी जी इस फैसले को वापिस लें। हम इसे हल्के में नहीं लेंगे और अध्यक्ष जी, हम देखते आएं है, इसी विधान सभा के इसी सत्र में, सबसे पहले गैस्ट टीचर का मुद्दा उठाया, किस तरीके से दबाव डाला गया कि गैस्ट टीचर की जो नौकरियों को पक्का करने को रोकने का प्रयास किया, उससे पहले हमने देखा कि एलजी साहब ने किस तरह से मोहल्ला क्लीनिक्स को रोकने की कोशिश की, अब हम देख रहे हैं कि विधान सभा की कमेटियों तक पर इन लोगों की जो है, नजर है कि किसी तरह इन्हें कमजोर किया जाए और आज मैट्रो फेयर जिसपे कल पूरे दिन सदन ने चर्चा की, पूरे सदन ने अपना मत रखा, एक मत होके, और अध्यक्ष जी, ये सदन कहां से आया है? ये सदन लोगों ने चुनकर भेजा है और पूरे दिल्ली की एक ही आवाज थी ये फेयर, इतनी मंहगाई में, त्यौहारों में नहीं बढ़ने चाहिए और अगर घाटा है तो जनता के सामने रखिए।

अध्यक्ष जी, मैं वापस उस बात को दोहराती हूं। ये विधायक नहीं, ये लोगों से चुनकर आए दिल्ली के दो करोड़ की आबादी की आवाज हम यहां पर उठा रहे हैं। वो जनता चाहती है कि ये फेयर वापस हो, वो जनता ये चाहती है ये घाटा दिल्ली के लोगों के सामने रखा जाए ताकि लोगों को लगे कि हां, जो भी हो रहा है, वो जायज हो रहा है। लेकिन दुःख की बात है कि केन्द्रीय मंत्री श्री हरदीप पुरी जी, जो न तो राज्यसभा से चुनकर आए, न लोकसभा से चुनकर आए, चंद दिन पहले उनको देश का जो है, वो केन्द्रीय मंत्री बना दिया गया और जो ये कहते हैं कि मैं दिल्ली मैट्रो को डीटीसी नहीं बनने दूंगा और दूसरी तरफ वो दिल्ली सरकार से कहते हैं हमें 3000 करोड़ दो। ये पहली केन्द्र की सरकार देखी है, जो धमकी देती है और फिरौती मांगती है कि अगर आपने हमें 3000 करोड़ नहीं दिया, हम फेयर बढ़ा देंगे। ये फिरौती मांगना और धमकी देना केन्द्र

की सरकार को कहिए, बन्द कर दीजिए। ये वो सरकारें नहीं है जो आपकी हर बात को सुन लेंगे और हरदीप पुरी जी से केन्द्रीय मंत्री जी से हाथ जोड़कर कहना चाहूंगी कि अच्छा होता आप लोकसभा या राज्यसभा, किसी भी सदन से चुनकर आते लोगों के बीच से आते उनके दर्द को समझते, कभी मैट्रो में सफर किया होता, कभी डीटीसी की बसों में सफर किया होता तो आपको दर्द महसूस होता लेकिन नहीं आप तो तानाशाह हो चुके हैं। आपको तो एक आदेश मिल गया है, उसको आपने पीटना है और उसको लागू करना है। आपके उपर उसका कोई असर नहीं है।

अध्यक्ष जी, मैं दोबारा दोहरा रही हूं ये हाउस ये सदन सड़कों पर उतरेगा, आंदोलन करेगा, इस सरकार को मजबूर कर देगा, इन बढ़े हुए किरायों को वापिस लेने के लिए। क्योंकि हमें मंशा मालूम है। मैट्रो का कोई किसी तरीके का घाटा नहीं हो रहा, वरना हमारी दिल्ली की जनता और हमारे बार–बार कहने पर वो घाटा क्या है, कितना है, वो जरूर जनता के सामने अभी तक रख दिया गया होता। लेकिन घाटा नहीं है, सच्चाई कुछ और है। सच्चाई क्या है? सच्चाई हमारे सामने है। ये वही ओला गाड़ी है, प्राइवेट गाड़ियां जिसमें देश का प्रधानमंत्री ओला की गाड़ियों में बैठकर प्रचार करते हैं लोगों को कहते हैं कि आप सरकारी वाहनों का इस्तेमाल मत करिए, आप प्राइवेट गाड़ियों का इस्तेमाल करिए। क्योंकि मोटा माल चुनावों में इन्हीं से मिलता है इनको। ये एक कारण है। तो अध्यक्ष जी, अन्त में ये तस्वीर सदन के सामने रखते हुए कहना चाहती हूं, हमें पूरा यकीन है कि मैट्रो किसी भी तरह के कोई भी घाटे में नहीं है, सच्चाई सिर्फ यही है अदानी, अंबानी, बाबा रामदेव, जय शाह, श्री अमित शाह जी के बेटे की तरह ओला जैसी प्राइवेट कंपनियों को फायदा पहुंचाने के लिए ही केन्द्र की मोदी सरकार ने ये इतना बड़ा बोझ इस महंगाई के दौर में दिल्ली की जनता के उपर

थोपा है। इसके ऊपर हम सब सख्त हैं और सड़कों पर उतरेंगे, जय हिन्द जय भारत।

अध्यक्ष महोदयः धन्यवाद। नरेश यादव जी।

श्री नरेश यादवः धन्यवाद अध्यक्ष जी, जो आपने इतने महत्वपूर्ण मुद्दे पर मुझे बोलने का मौका दिया।

अध्यक्ष जी, साल में दूसरी बार ये मैट्रो के फेयर बढ़ाए गए हैं तो मैं तो यही सोच रहा था कि दिल्ली की जनता ने ऐसा क्या कसूर किया है जिससे कि दिल्ली की जनता के ऊपर इस तरह का बोझ डाला जा रहा है और वो भी ऐसे वक्त पर जब पूरे देश की इकॉनमी कैसे बैठी हुई है, नोटबंदी और जीएसटी की वजह से। तो ये सारी जनता ये देख रही है अध्यक्ष जी, कि किस तरह से जो एक चुनी हुई सरकार, अरविंद केजरीवाल जी की सरकार इस मैट्रो फेयर हाइक का हम लोग विरोध कर रहे हैं और उसके बावजूद भी जब कि दिल्ली सरकार मैट्रो में 50 परसेंट की पार्टनर है और किस तरह से किसी भी तरह के कोई सजेशन को माना नहीं जा रहा है। जनता को ये बिल्कुल क्लीयर है कि उनकी चुनी हुई सरकार ने पूरा विरोध दर्ज किया है। तो जनता भी अपना सोच रही है कि 2019 ज्यादा दूर नहीं है कि जिस तरीके से अरविंद केजरीवाल जी आज उनकी ये लड़ाई लड़ रहें हैं, तो अगर हम चुने हुए सारे रिप्रेजेंटिव्स की बातों को ये लोग नहीं सुन रहे हैं तो जनता इनको 2019 में कन्क्लूड जरूर कर देगी। जैसा कि हमारे महेन्द्र भाई जी ने कल कहा था। लेकिन ये क्या है, क्यों ऐसा हो रहा है, इसके पीछे कोई तो साजिश होगी।

अध्यक्ष जी, मैं अपना एक्सपीरियंस बताता हूं शेयरिंग के लिए जैसे अभी ओला कंपनी का नाम आया। वसंत कुंज से कनॉट प्लेस तक के लिए शेयरिंग

की, ओला कैब में मैं गया, उसमें मात्र 40 रूपये का खर्चा आया और मैट्रो में अगर जाते हैं तो 60 रूपये से ज्यादा का खर्चा है तो ये सारी की सारी साजिश, कहीं न कहीं प्राइवेट कंपनियों को फायदा पहुंचाने वाली है। दिल्ली की सरकार तो आम जनता की सरकार है लेकिन केन्द्र में जो बैठी हुई सरकार है, वो पूंजीपतियों की सरकार है। वो हमेशा कंपनियों को अंबानी, अडानी उद्योगपतियों को फायदा पहुंचा रही है। ये साजिश दिल्ली की जनता समझ रही है और वक्त आने पर दिल्ली की जनता इसका जवाब देगी। आज ऐसा माहौल बन रहा है पूरी दिल्ली में, पूरे देश में कि किस तरह से क्या सोच कर केन्द्र की सरकार मोदी जी के हाथों में दी थी और आज वो बिल्कुल सारे उद्योगपतियों के हाथों में ही खेल रहे हैं, उन्हीं के लिए सोच रहे हैं। किसी भी तरह से आम जनता के लिए कोई ऐसा कदम नहीं दिखता कि उस पर वो सहमत होते हों। आज हम लोग सत्ता में हैं और हम लोग कह रहे हैं इस बात को कि मैट्रो के फेयर नहीं बढ़ने चाहिए लेकिन जो अपोजिशन में हमारे बीजेपी के जो सदस्य हैं, ये लोग उसका विरोध कर रहे हैं तो इससे बिल्कुल स्पष्ट है कि आम जनता की जो सरकार है, जो माननीय केजरीवाल जी की जो सरकार है, वो जनता की लड़ाई लड़ रही है लेकिन केन्द्र सरकार नहीं लड़ रही है। इसके अलावा जब पिछले दो सालों में जो आंकड़ा राइडरशिप का था और पीछे मई में जो मैट्रो के फेयर बढ़ाए गए, उसके बाद में वो घट गया। तो अभी ये अगर बढ़ रहा है तो इससे और ज्यादा घटेगा। जब लोग सवारी करेंगे नहीं मैट्रो में तो पैसा बढ़कर कैसे आएगा? ये तो एक क्वेश्चन सभी के मन में आ रहा है कि अगर सवारी घट जाएगी राइडरशिप घट जाएगी तो रेट बढ़ा देने से फायदा होगा या नुकसान! ये सारी की सारी एक साजिश है अध्यक्ष जी, जो प्राइवेट कंपनियों को फायदा पहुंचाने के लिए कर रहे हैं हम सभी लोग, पूरा सदन इसका विरोध कर रहा है और इसके लिए अगर जरूरी हुआ

तो हम लोग सड़कों पर भी जायेंगे और पूरा जनता के साथ हम लोग खड़े होकर इस विरोध को हम इस कोशिश के साथ कि ये मैट्रो के जो फेयर जो बढ़ा दिए गए हैं, आज से ये वापिस हो जाएं और आम जनता पर इस तरह का बोझ आज के समय में जब ये मंदी का दौर चल रहा है, वो न पड़े, बहुत–बहुत धन्यवाद अध्यक्ष जी जो आपने मुझे बोलने का मौका दिया, धन्यवाद।

अध्यक्ष महोदयः थैंक्यू। श्री अजय दत्त जी।

श्री अजय दत्तः अध्यक्ष जी, धन्यवाद कि आपने मुझे इस गंभीर विषय पर बोलने का मौका दिया।

अध्यक्ष महोदय, आज मैं मैट्रो से आया हूं और कई बार क्योंकि मेरी विधानसभा करीबन 25 से 27 किलोमीटर दूर है और कई बार मैं मैट्रो आता हूं और अपने साथी विधायकों के साथ लिफ्ट लेकर के आता हूं क्योंकि हम सभी विधायक जो हमें सेलरी मिलती है, उससे हम अब कार अफोर्ड नहीं कर पाते और आपको पता है हमारा बेसिक पे 12 हजार रूपये है और ये भाजपाई ने पूरे देश में फैला रखा है कि इनकी सेलरी दो लाख कर दी है, ढ़ाई लाख कर दी है, तीन लाख कर दी है। सिर्फ 12 हजार रूपये का बेसिक पे है जो हमें मिलता है और उसमें कार अफोर्ड करना बड़ा मुश्किल है तो आज जब मैं मैट्रो से आया तो मैंने एक बहुत विचित्र दृश्य देखा सर! ये तो करोड़ों की बात करते हैं, हम लोग तो नौकरी पेशा वाले आदमी थे जी।

... (व्यवधान)

श्री अजय दत्तः ऐसा है शर्मा जी, अगर ऐसे ऑफर आपने हमारे खुद्दार लोगों को पहले भी दिए आम आदमी पार्टी का एक भी व्यक्ति जिंदगी में

कभी भाजपा में नहीं जाएगा और जो गया, उसका हश्र आपने देखा, अभी बवाना में क्या हुआ! तो ये दिल्ली की जनता अच्छे से जानती है और हमारे विधायक न तो पहले पॉलिटिशियन थे, न आज हैं। हम तो सेवा करने की इच्छा रखते थे और सेवा करने आए हैं, सब कुछ लुटा के सेवा करने आए हैं। तो आज जब मैं मैट्रो की लाइन में लगकर किराए के लिए टोकन ले रहा था तो मैंने एक महिला को देखा। उस महिला के पास 10 रूपये थे। उसने 10 रूपये का टिकट लेने के लिए टोकन लेने के लिए दिया तो उसको मना कर दिया। 20 रूपये हो गए। महिला ने कहा, नहीं 10 का है। वो कह रहा है कि नहीं, 20 का है ऑर्ग्युमेंट्स शुरू। महिला ने कहा, भाई साहब, कल तो मैंने 10 का लिया था कि नहीं जी, 20 का है। तो वो महिला सकपका कर रह गई और वो बेचारी लाइन से बाहर आ गई और बड़ा दुःख हुआ। उस महिला के पास सिर्फ एक जगह जाने का 10 रुपये किराया था। उसके पास 10 रुपये एक्सट्रा भी नहीं थे और वो एक दम सकपका गई। उसके बाद दूसरा वाकया देखा कि एक स्टूडेंट उसने भी अपना 10 रुपये दिए और टिकट के लिए हाथ बढ़ाया, उसको भी कहा 20 रूपये। उसने तो लिटरली गाली दे दी। ये कहा, ये क्या हो गया है, हम कैंसे जाएंगे! तो लोग बहुत परेशान हैं। मैंने भी एक हाथ बढ़ाया 30 रूपये दिए। उसने मुझसे 50 मांग लिए। मैंने कहा अगर मेरे पास 50 नहीं होते आज तो मुझे भी यहां तक नहीं आने को मिलता तो मैट्रो का किराया अचानक से बढ़ा दिया, यकायक बढ़ा दिया और किराए में 100 परसेंट तक की वृद्धि कर दी गई। 100 परसेंट और ये तो पाँच से 21 किलोमीटर तक के किराए में 100 परसेंट की वृद्धि कर दी गई। अब ये बताइए कि ये कौन सा बिजनेस चला रहे हैं, केन्द्र सरकार कौन सा धंधा चला रहे हैं कि 100, 100 परसेंट की अगर ये इन्क्रीज करेंगे किराए में, तो दिल्ली और दिल्ली के नागरिक कहां जाएंगे? मुझे लगता है दिल्ली के नागरिकों

ने जैसे ही इन्हें पिछली बार एक बहुत बड़ा आइना दिखाया था। मुझे लगता है इस बार केन्द्र में भी पूरे देश की जनता इन्हें आइना दिखाएगी। ये उस ढ़र्रे पे चल रहे हैं। क्योंकि जनता के पेट पे लात मार रहे हैं। ये वो लोग हैं जो अपनी रोजी कमाने के लिए 10 किलोमीटर ट्रेवल करते हैं, 10 रुपये में। ये वो बच्चे हैं जिनको गिन के 30 रुपये, 40 रुपये, 50 रुपये घर से मिलते हैं और उसी में उसको छोले ले के रोटी भी खानी है और उसे उसी में अपने कॉलेज भी जाना है। ये उन लोगों के पेट पे लात मारी जा रही है और वो स्टूडेंट जो इस देश का भविष्य बना रहा है। मुझे लगता है कि आज उसको इस मैट्रो में चलने का अधिकार छीना जा रहा है। इस मैट्रो के किराए को बढ़ाने के लिए कमेटी का गठन होना था 2009 में और 2009 से 2016 तक वो कमेटी नहीं बनाई जिसको मैट्रो का किराया फिक्स करने की जो जिम्मेवारी दी गई थी। तो मैं ये जानना चाहता हूं कि ये भाजपा के लोगों ने इस दिल्ली मैट्रो के साथ ऐसा घिनौना व्यवहार क्यों किया गया कि भई वो मैट्रो की कमेटी नहीं बनाई और उस कमेटी को 2016 में बना के दो बार मैट्रो किराए हाइक की तरफ ले जाया गया। जिसमें दिल्ली सरकार ने बाकायदा रिटर्न में लिख के दिया है कि हम किराया बढ़ाने के लिए सहमति नहीं दे रहे, ये बिल्कुल लिख के दिया है। उसके बावजूद भी दिल्ली सरकार, एक चुनी हुई सरकार को दरकिनार करके इन लोगों ने किराया बढ़ाया। मुझे समझ नहीं आ रहा कि ये क्या करना चाहते हैं!

अध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से दिल्ली वालों को ये बताना चाहता हूं कि ये विरोध नफरत की और बदले की भावना की राजनीति कर रहे हैं। दिल्ली के लोगों ने इन्हें दिखाया कि हम एक अच्छी ईमानदार सरकार चाहते हैं। लेकिन ये बदले की राजनीति ले के दिल्ली के लोगों को बार

बार परेशान कर रहे हैं। डीएमआरसी का किराया बढ़ा और डीएमआरसी के कुछ अपने ऐक्ट हैं अध्यक्ष महोदय, 2000–2002 का ऐक्ट है जिसमें सेक्शन–37 में बाकायदा लिखा हुआ है कि अगर एक साल में दो बार किराया बढ़ाया जाएगा तो उसे फिर फिक्सेशन कमेटी डिसाइड करेगी और उसको भी उन्होंने ताक पर रख दिया। ये कहते हैं कि हम कानून से चलते हैं, बार बार हमारे विपक्ष के जो नेता हैं, वो आज नहीं हैं मुझे लगता है उन्हें भी बहुत शर्म आ रही होगी इस विशय पर यहां खड़े रहने और यहां पर अपनी प्रजेंस दिखाने में। वो बार बार रूल की बुक दिखा देते हैं। कहते हैं जी, ये रूल है। अरे! मुझे बताइए ये रूल को ताक पे क्यों रखा जा रहा है? ये रूल्स से कैसे आप आगे जाएंगे? और रूल भी उन्होंने दरकिनार कर दिए।

अध्यक्ष महोदय, मैं एक बहुत आपका ध्यान एक दूसरी तरफ ले के जा रहा हूं, शिक्षा, क्या शिक्षा एक ऐसा विषय है जो हमारी दिल्ली सरकार किसी बिजनेस की तरह कर रही है? हमारे शिक्षामंत्री हमारे मनीष सिसोदिया जी, अरविंद केजरीवाल जी, सीएम साहब ने शिक्षा का स्तर इतना बढ़ा कर दिया है। इतनी इंवेस्टमेंट की है कि आज पूरा देश और पूरा विश्व उसको देख रहा है। क्या हवा से कुछ निकलके आएगा? हमारे स्वास्थ्यमंत्री ने स्वास्थ्य का स्तर इतना अच्छा कर दिया है कि आज जो लोग आज से 70 साल पहले हमारे ऊपर राज करते थे और उन्होंने कहा था कि इंडिया, इंडियन नहीं चला सकते, वो हमारी चर्चा कर रहे हैं। वो कहते हैं कि स्वास्थ्य बहुत अच्छा हो गया है दिल्ली के अन्दर दिल्ली सरकार ने किया है।

अध्यक्ष महोदयः अजय जी, अब कन्क्लूड करिए प्लीज कन्क्लूड करिए।

श्री अजय दत्तः ये कहना चाह रहा हूं अध्यक्ष महोदय कि ये मैट्रो जो टैक्स हमारी दिल्ली सरकार, दिल्ली के लोग देते हैं, भारत के लोग जो

टैक्स देते हैं, उस टैक्स के पैसे से ये इंवेस्टमेंट की जाती है, इसकी नई लाइनें बिछायी जाती हैं, ये रेल के डिब्बे खरीदे जाते हैं। उस टैक्स के पैसे से जनता को सुविधा दी जाती है। सरकार का काम कोई बिजनेस करना नहीं है। पेंशन जो है, वो सरकार इसलिए देती है कि क्योंकि जनता का पैसा, टैक्स का पैसा उनके हित में खर्च हो रहा है, इसलिए दिए जाते हैं। इसी तरीके से मैट्रो भी एक जनता के लिए सहूलियत का काम है। अगर उसपे खर्चा हो रहा है तो वो जनता के लिए हो रहा है, वो सहूलियत के लिए हो रहा है। तीन दिन पहले जब ये बात उठी कि किराया बढ़ाया जाएगा। हमारे मुख्यमंत्री साहब जो दिल्ली के हरदिल अजीज हैं, जो दिल्ली की जनता और पूरे देश की जनता उन्हें प्यार करती है क्योंकि वो गरीबों के लिए काम कर रहे हैं। उन्हें तुरन्त कहा कि अगर...

अध्यक्ष महोदयः अजय जी, कन्क्लूड करिए प्लीज, कन्क्लूड करिए।

श्री अजय दत्तः तीन हजार करोड़ रुपये अध्यक्ष महोदय, अगर 3 हजार करोड़ रु0 सेन्ट्रल गवर्नमेंट मांग रही है तो 1500 करोड़ रु0 दिल्ली सरकार अरविंद केजरीवाल की सरकार देगी। ये उन्होंने कह दिया और उसके बावजूद भी मुझे बड़ा दुःख है, उसके बावजूद भी केन्द्र सरकार ने मैट्रो के किराए बढ़ाए! जबकि दिल्ली सरकार को 50 परसेंट देने का भी कोई औचित्य नहीं था, उसके बावजूद भी बढ़ाए।

तो मैं अध्यक्ष महोदय, आपके माध्यम से ये कहना चाहता हूं कि दिल्ली का सवा सौ करोड़ रुपये का, सवा सौ करोड़ रुपये का लोन दिल्ली के लोग देते हैं और उस लोन का आप हमें एक परसेंट भी नहीं दे रहे हो। हम कह रहे हैं कि आप 50 परसेंट दे दो, 40 दे दो, 30 परसेंट दे दो और मैं आपको दावा देता हूं कि दिल्ली सरकार अगर आपने 30 परसेंट दे दिया तो मैट्रो का, तीन करोड़, तीन हजार करोड़ क्या, पांच हजार करोड़

भी अपनी तरफ से दे देगी क्योंकि हमारे अरविंद केजरीवाल जो दिल्ली सरकार के जो मुखिया हैं वो....

अध्यक्ष महोदयः चलिए हो गया अजय दत्त जी, बैठिए प्लीज, कन्क्लूड करें। नहीं, अब कन्क्लूड करिए अजय दत्त जी।

श्री अजय दत्तः सर एक मिनट और दें मैं अपनी बात कहके, सर, मैं ये कहना चाहता हूं कि केन्द्र सरकार क्या यहां बिजनेस कर रही है? क्या ओला को बिजनेस करने के लिए बुला रही है कि रिलायंस के लिए कुछ प्रॉफिट करा रही है? क्या अमित शाह के बेटे जय शाह को 80 करोड़ रुपये का प्रॉफिट पहुंचाने के लिए काम कर रही है? ये दिल्ली की जनता सहेगी नहीं और मैं केन्द्र की बीजेपी सरकार से ये कहना चाहता हूं कि अगर गरीबों का हक मारोगे तो एक दिन गरीब तुम्हें कुचल के रख देंगे, नेस्तनाबूद कर देंगे, ये बात आप ध्यान में रखें। इस बढ़े हुए किराए को वापिस लें और दिल्ली मैट्रो को जो पुराना किराया है, उसपे लाएं, जय हिन्द, जय भारत।

अध्यक्ष महोदयः श्री सोमनाथ भारती जी।

श्री सोमनाथ भारतीः अध्यक्ष महोदय, आपका बहुत बहुत धन्यवाद कि आपने मुझे इस विषय पे अपने विचार रखने का मौका दिया। अध्यक्ष महोदय, जब हमारे साथी ये कह रहे थे कि हमारे सैलरी 12 हजार रुपये बेसिक है तो विपक्ष के साथियों ने कहा कि भाजपा में आ जाओ। ये मन से बात निकली क्योंकि एक यही पार्टी है जो जानती है कि 16 हजार गुना कैसे मुनाफा कमाया जाता है। इन्हीं के पास ये पीएचडी हासिल है। जैसे अलका जी ने कहा कि पूरे देश को पता है, हमारे नौजवान साथी देश के अन्दर रोजगार ढूढ़ रहे है। उनको बताएं, किस तरह से मुनाफा कमाया जाता है

और मुझे तो लगता है कि अगर कारपोरेट गवर्नेन्स, कारपोरेट अफेयर्स मिनिस्ट्री इतने काबिल आदमी को दिया जाए तो बेहतर रहेगा। भई अरूण जेटली साहब ने तो कोई कमाल किया नहीं। तो अगर देश के हित में हम कहते हैं भाजपा के साथियों से अपने आकाओं तक बात पहुंचाये कि जय अमित शाह जी एक नया चेहरा बनके उभरे कि किस तरह से 16000 गुना,! युवा चेहरा, युवा नेता! भई, कई नाम उन्होंने कमाये पिछले दिनों में और मुझे लगता है कि आज भाजपा के साथी इसमें कोई ऑब्जेक्शन नहीं उठा रहे हैं। भई सबसे बड़ी बात है, महेन्द्र गोयल जी, आज सबसे बड़ी बात है कि आज भाजपा के साथी बिल्कुल ऑब्जेक्शन नहीं उठा रहे हैं इस बात पर। इस बात पर राजी हैं। इस बात पर राजी है। ये इस बात पर राजी है।

... (व्यवधान)

अध्यक्ष महोदयः ओमप्रकाश जी, शान्तिपूर्वक चल रहा है न सदन। क्या दिक्कत है। नहीं, क्या बोला उन्होंने गलत? उन्होंने गलत तो नहीं बोला कुछ। नहीं उन्होने क्या गलत बोला?

श्री सोमनाथ भारतीः अब कोई बात नहीं। ओमप्रकाश जी।

... (व्यवधान)

अध्यक्ष महोदयः अभी आपकी बारी आने वाली है। इनके बाद। उनके बाद आपकी बारी है,, अपनी बात रखिए। अभी उनके बाद आपकी बारी, आप अपनी बात रखिएगा। बैठिए प्लीज।

... (व्यवधान)

अध्यक्ष महोदयः अखिलेश जी। अखिलेश जी बैठिए। अभी आपकी बारी आने वाली है। चिन्ता न करिए आप।

श्री सोमनाथ भारतीः ये सलाह आपका ही था वैसे। आपने कहा कि भाजपा में आ जाओ तो काम हो जाएगा। तो आपने कहा, हमने उसको आगे एक्सप्लेन कर दिया। अध्यक्ष महोदय, सभी साथियों ने अपने विचार इस मुद्दे पर रखे कि भई, क्या जरूरत है, ये किराये बढ़ाने की! आज तक मैंने पहले भी कई बार इस सदन के पटल पर रखा कि आज तक इतिहास में और पूरे देश में ऐसी कोई सरकार न हुई जिसके वित्त मंत्री ये कहते हों सदन के अन्दर खड़ा होके कि उनके लिए इलेक्शन प्रामिसेज, इलेक्ट्रोल प्रामिसेज... कोई साधारण काम नहीं, वो कान्ट्रैकचुअल आब्लिगेशन है। ये सिर्फ हमारी सरकार के वित्त मंत्री ने कहा कि हमारे जुमले नहीं हैं, हम जुमलेबाज नहीं हैं। हम देश के साथ धोखा करने नहीं आए हैं। ये जिस तरह से इन्होंने देश को बेवकूफ बनाने का प्रयास किया है। ये नोटबन्दी को ऐसे बेच रहे थे, पता नहीं देश की कौन–कौन सी समस्याएं खत्म हो जाएंगी। आतंकवाद खत्म हो जाएंगा! कालाधन आ जाएगा! कालाधन आ जाएगा! अन–एम्प्लायमेन्ट खत्म हो जाएगा! वो सब खत्म हो जाएगा! लेकिन निकला क्या?

... (व्यवधान)

अध्यक्ष महोदयः सोमनाथ जी, आप बात रखते रहिए अपनी।

श्री सोमनाथ भारतीः खोदा पहाड़, निकली चूहिया। अध्यक्ष महोदय, दिल्ली के अन्दर जो एक विकास, एक तो विकास पैदा वहां हुआ। सबने ढूढ़ा कि भई, विकास हम ढूढ़ रहे थे, कहां पैदा हुआ? कहां पैदा हुआ? विकास तो घर में ही निकला। एक जो दिल्ली का सचमुच का विकास पैदा हुआ दिल्ली के अन्दर, जो कि केजरीवाल साहब के नेतृत्व में सरकार चल रही है, जो बिजली के अन्दर पिछले ढाई साल में एक बार भी दाम नहीं

बढ़ने दिया। इसके लिए उनको बहुत–बहुत मुबारकवाद देता हूं। पानी के अन्दर इन्होंने कहा कि भई, सब्सिडी दे दोगे, सब्सिडी दे दोगे। अरे भाई, पानी के अन्दर अजूबा करके दिखाया! बीस हजार लीटर पानी प्रति महीना, प्रति फेमली मुफ्त दिया। उसके बावजूद।

... (व्यवधान)

अध्यक्ष महोदयः नहीं, वो बात रख रहे हैं। उसमें क्या, कहां, क्या दिक्कत है? नहीं, आप बैठिए, सिरसा जी। नहीं, वो ठीक हो रही है चर्चा। ठीक हो रही है चर्चा। ठीक ट्रैक पर जा रही है।

... (व्यवधान)

अध्यक्ष महोदयः गोविन्द जी। आप चलिए प्लीज। ऋतुराज जी, आपकी बारी, आपने लिखके भेजा है न? आपकी बारी आएगी न। आप बैठिए ओमप्रकाश जी बैठिए। प्लीज बैठिए। सोमनाथ जी, करिए, करिए। गोविन्द जी, ऋतुराज जी।

श्री सोमनाथ भारतीः अध्यक्ष महोदय, जब पानी के क्षेत्र में मेरी सरकार ने एक अजूबा करके दिखाया तो इन लोगों को मालूम पड़ा कि भई, इसका जवाब कैसे! मुफ्त देने के बावजूद कहते है की 22–23 लाख कनेक्शन्स में से कोई 12 लाख कनेक्शन पानी दिल्ली में मुफ्त पीता है। उसके बावजूद हमने प्रॉफिट करके दिखाया। ये कहां हुआ? इनके इकोनामिक्स एक हैं। ये घर वालों में ही 16000 गुना बढ़ा रहे हैं और हम सरकार के खजानों में और पैसे ला रहे हैं, और पैसे ला रहे है।

अध्यक्ष महोदय, जैसा सौरभ भाई ने कहा कि टैम्पल इन द प्राईवेट लिमिटेड रवैया! कम से कम मन्दिर को छोड़ देते। भई मन्दिरों के नाम पर

कब तक चूसोगे? अब तो अपने पाप के भागीदार भी बना रहे हैं मन्दिरों को। जो भगवान राम को न छोड़े, जो भगवान श्रीराम के न हुए... ये कहते हिन्दू हैं, हिन्दू हैं, हिन्दू हैं। अरे! हिन्दू, हिन्दू शब्दों से नहीं होता। हिन्दू करनी से होता है। ऐसा नहीं कि पितारूपी आडवाणी जी को धक्का मारके बोला, ''मैं बैठूगा गद्दी पर।''

अध्यक्ष महोदयः सोमनाथ जी, थोड़ा सा विषय पर। प्लीज।

श्री सोमनाथ भारतीः अध्यक्ष महोदय, एजूकेशन में हमने ऐसा क्रान्ति लाया दिल्ली के अन्दर लेकिन एजूकेशन में क्रान्ति लाने के लिए मनीष जी ने ये नहीं कहा कि मैं टैक्स बढ़ाऊंगा। ये तो नहीं कहा, ये तो नहीं कहा। मेरी सरकार ने हेल्थ केयर के अन्दर मोहल्ला क्लीनिक बनाने के लिए, पॉली क्लीनिक बनाने के लिए, अस्पताल बनाने के लिए ये जो क्रान्ति लेके आयी, इसकी चर्चा पूरे विश्व में हुआ। हमने नहीं कहा कि हम टैक्स बढ़ाएंगे। फिर वो बात पैदा हुई कि भई, एकाउन्टेबल गवर्नमेन्ट का मतलब क्या होता है? भई, गवर्नमेन्ट एकाउन्टेबल है। किसको एकाउन्टेबल है, किसके प्रति उत्तरदायी है ये? तो एक सरकार दिल्ली में है जो चौबीस घंटा प्रयत्न कर रही है कि दिल्लीवासियों के लिए, दिल्लीवासियों के बच्चों के लिए, उनके भविष्य के लिए सरकारी खजाने का सदुपयोग हो। स्कूल बनें, अस्पताल बनें और एक सरकार उधर है केन्द्र में! वो किसके प्रति उत्तरदायी है, ये हमारे साथियों ने अभी बताया, खुलके बताया। वहां भी विकास हो रहा है। एक तो घर में पैदा हुआ। सबने देखा। फिर देखा कि करीब तीन सौ करोड़ रूपये का बाबा रामदेव जी का एसेट में इन्क्रीज हुआ है, लैण्ड में। सिर्फ लैण्ड में उनको मिला है ये मदद! और उनके एड कैसे आते हैं टी.वी. के ऊपर। देशवासियों को ऐसा मूर्ख बनाने वाला कम्पनी और ऐसा मूर्ख बनाने वाला प्रधानमंत्री आज तक नहीं देखा! कहता है कि अंग्रेजों से लड़ना है

तो हमारे सामान खरीदो। ये अच्छा हुआ भाई! अंग्रेजों से लड़ना है हमारा सामान खरीदो। देश प्रेम हो तो हमारे सामान खरीदो। अरे! सबका व्यापार कर लोगे! भगवान राम का व्यापार कर लिया! अब देश का व्यापार कर लोगे! देश प्रेम का व्यापार कर लोगे! किस—किस का व्यापार करोगे? किस—किस को बेचोगे?

अध्यक्ष महोदय, बहुत दुःख होता है जान के। इनकी एकाउन्टेबिल्टी है किसके प्रति? फिर एक वो आज मैंने पता करने का प्रयास किया। भई 3000 करोड़ रूपया ये फिगर कहां से पहुंचा? ये फिगर आया कहा से आखिरकार!

अध्यक्ष महोदय, जैसा हमारे साथी संजीव ने आज कहा वो रिलायन्स को जो प्रोजेक्ट मिला था मैट्रो वाला। उसमें बात निकल के आई। चूंकि जब इनको लगा कि इनकी नहीं बन रही है तो ये चले गये कि हम तो चैलेन्ज कर रहे हैं। हम डीएमआरसी को चैलेन्ज कर रहे हैं। तो एक आउट ऑफ कोर्ट सेटलमेन्ट के लिए इन्होंने आर्बिट्रेशन बनाया। अब आर्बिट्रेशन में थ्री मेम्बर कमेटी बनी। अब वो पता नहीं वहां पर कैसे घुट्टी क्या पिलाई उनको। 2950 करोड़ रूप्या का आर्बिट्रेशन ये जीत गए। जीत गए तो मतलब अब डीएमआरसी को देना पड़ेगा। डीएमआरसी कह रही है हम कोर्ट जाएंगे। लेकिन ये बिल्कुल मिलता—जुलता फिगर है 3000 करोड़ और 2950 करोड़। तो रिलायन्स का, अपने दोस्तों का बड़ा ख्याल रखते हैं। एक बात तो है ही। जिस—जिस ने इनको लाने का वहां, मोटा भाई कहते हैं, उनको मोटा भाई कहते हैं। मोटा माल, मोटा भाई। तो मोटा भाई, मोटा माल वाला इस कदर से मोदी जी कुछ उद्योगपतियों का सहारा लेकर के यहां पहुंचे। इनका दायित्व है। उनके प्रति कम से कम, वहां तो बेईमानी में ये ईमानदार हैं। देश के प्रति ईमानदार न हों लेकिन उनके प्रति ये ईमानदार हैं जिन्होंने

कि इनको पैसे देकर के, फण्ड देकर के यहां पहुंचाया। अब ये रिलायन्स को फायदा पहुंचाना है तो डीएमआरसी को चूना लगाना है और डीएमआरसी को जो चूना लगेगा वो जनता के जेब पर भारी पड़ेगा। तो ये पैसा 3000 करोड़ कहां से आएगा? ये दिल्लीवासियों के जेबों से आएगा।

अध्यक्ष महोदय, यह कहा जा रहा है कि डीएमआरसी ने जानना चाहा, भई who were at fault? डीएमआरसी जाना चाह रही थी कोर्ट, लेकिन आउट ऑफ कोर्ट सैटलमेंट करने के लिए इन्होंने आर्बिट्रेशन कमेटी बनाई और उसके अंदर से मैनेज करके इन्होंने वो निकाल लिया और कहा यह जा रहा है, अगर यह ऑर्डर डीएमआरसी चैलेंज करती है तब भी कोई नीति आयोग इन्होंने बनाया, प्लानिंग कमीशन का नाम कर दिया नीति आयोग, लगा कि बहुत कुछ हो जाएगा। नाम बदलने से काम नहीं बदल रहा इनका।

अध्यक्ष महोदय, अब कहा जा रहा है कि 75 परसेंट of the award against the bank guarantee even if they challenge the order. इसका मतलब जो सरकार पर बोझ पड़ने वाला है, डीएमआरसी पर जो बोझ पड़ने वाला है, वो करीब–करीब चार हजार आठ सौ करोड़ का बोझ पड़ने वाला है। दो हजार दो सौ दस करोड़ और इंट्रेस्ट मिलाकर के करीब–करीब चार हजार आठ सौ करोड़ रुपये का बोझ पड़ने वाला है। even if they challenge the order.

अध्यक्ष महोदय, यह मामला क्या है, इनको तनिक भी कहीं भी चुभता नहीं है कि आज वो जो संजीव ने बताया और साथियों ने बताया, अजय ने बताया कि जो गरीब मां चढ़ना चाह रही थी मैट्रो पर, उसको दस की जगह बीस देने को कहा गया तो वो लाइन से हट गई। उनका जो श्राप है, वो इनको नहीं लगेगा? लगेगा कि नहीं लगेगा?

... (व्यवधान)

अध्यक्ष महोदयः सोमनाथ जी, अब कन्क्लूड करिये।

श्री सोमनाथ भारतीः अध्यक्ष महोदय, मैं एक बात पूछना चाहता हूं, चूंकि साथियों ने आज अच्छे से खोलकर बताया।.... श्राप लगेगा भइया! देख लो, और श्राप देखो ऐसा लगेगा, देखिये, अध्यक्ष महोदय, आज इन्होंने फिर गलती करी है, इन्होंने आज फिर पर्सनल कमेंट किए हैं। इस इंसान को पहले बाहर किया गया, सदन से बाहर किया गया, ये सुधरे नहीं हैं।

अध्यक्ष महोदयः सोमनाथ जी, आप मत ध्यान दीजिए, उनकी आदत है।

श्री सोमनाथ भारतीः देखो भइया, हम आपके जैसे नहीं है।

... (व्यवधान)

अध्यक्ष महोदयः सिरसा जी, फिर आप कहेंगे, आप सुन लेना पर्सनल कमेंट।

... (व्यवधान)

अध्यक्ष महोदयः उन्होंने कोई पर्सनली नहीं बोला है। उन्होंने बोला पार्टी पर श्राप लगेगा, आप पर्सनल कमेंटस कर रहे हैं। उन्होंने पार्टी के लिए बोला है। आपका नाम नहीं लिया। क्या बात करते हैं? फिर आप कहते हैं, फेवर लेते हैं, निष्पक्ष आप नहीं हैं, कंट्रोल आपका अपने ऊपर नहीं है। ऋतुराज जी, बैठिये।

... (व्यवधान)

अध्यक्ष महोदयः सोमनाथ जी, अब कन्क्लूड कीजिए प्लीज।

श्री सोमनाथ भारतीः अध्यक्ष महोदय, आप हमको गाली दे दो, कोई बात नहीं लेकिन श्राप लगेगा उन माताओं का, उन बहनों का। वो श्राप लगेगा, मैं बता रहा हूं।

दूसरी बड़ी बात अध्यक्ष महोदय, जो कि मैं आपके माध्यम से संज्ञान में लाना चाहता हूं अपने सदन के साथियों को अगर यह मामला अहमदाबाद मैट्रो का होता, मान लो तो क्या ये रेट बढ़ता वहां? क्या रेट बढ़ता वहां? ये चुनाव को देखकर के काम करते हैं। इनको मालूम है कि दिल्लीवासी इनको रिजेक्ट कर चुके हैं। इनको पता है कि दिल्ली में केजरीवाल साहब, मनीष सिसोदिया साहब ने जो एक क्रांति पेश की है, दो मूलभूत समस्याओं के ऊपर स्वास्थ्य और शिक्षा के अंदर उसके बाद दिल्ली में इनकी दाल नहीं गलने वाली, इसलिए दिल्लीवासियों से ये बदला लेना चाहते हैं। अगर ये इस सवाल का जवाब दे दें, क्या अगर गुजरात के अंदर अभी चुनाव होने वाला है, खाकरा का तो गिरा दिया, अब ये अपने अंदर पूछे कि यह जनता है, जनता–जर्नादन मालिक है डेमोक्रेसी की। अभी हमारे माननीय केजरीवाल साहब ने सदन के माध्यम से बताया कि यह डेमोक्रेसी है, हमारे लिए जनता भगवान है। अगर आप दुश्मनों की तरह ट्रीट करते हो तो आप जानो, लेकिन हमारे लिए जनता भगवान है। उनके हकों के लिए, उनके अधिकारों के लिए पूरी सरकार, सारे विधायक साथी पूरी पार्टी एक साथ लड़ेगी और जब तक उनको न्याय न मिले, तब तक लड़ती रहेगी।

अध्यक्ष महोदय मैं आपको बहुत–बहुत धन्यवाद देता हूं कि आपने मुझे मौका दिया। धन्यवाद।

अध्यक्ष महोदयः श्री जगदीप सिंह जी।

श्री जगदीप सिंहः नमस्कार सर, आपका बहुत धन्यवाद है, आपने मुझे मौका दिया। सोमनाथ भारती जी ने बड़े अच्छे से सारी बातों को रखा। उसी ऐपिसोड को मैं आगे बढ़ाते हुए चार–पाँच मोटी–मोटी बातों को सिर्फ रखूंगा कि जैसे रामदेव की बात अभी सोमनाथ भारती जी ने की है। सोमनाथ

भारती जी बाद में बातें कीजिए, पहले सुनिये इधर, रामदेव जी का प्रोग्राम आता था, जहां पर वो टीवी पर दिखाते थे कि कैसे दंतमंजन बनाना है। कह रहे हैं फॉरेन की पेस्ट छोड़ो दंतमंजन बनाओ, हल्दी–उबटन बनाओ, साबुन बनाओ। वहीं फ्री में सिखाते थे। लोग कहते थे ये व्यायाम करने वाला योगी यह बहुत बढ़िया आदमी है, जो फ्री में हमें ये सारी चीजें बनानी सिखा रहा हैं। लोग बड़े अच्छे दिल से सीख रहे थे लेकिन एकदम यकायक पता नहीं क्या हुआ कि वही रामदेव एकदम बड़ी सी कम्पनी खोल देता है, जैसे ही भाजपा की सरकार आती है और करोड़ों रुपया पता नहीं कहां से आ जाता है, चारों तरफ पतांजलि के स्टोर खुल जाते हैं। मैग्गी को बंद कर दिया जाता है। जो योग सिखाते हुए कहता था मैग्गी नहीं खानी, वो कहते हैं आप पतांजलि की मैग्गी खाओ। वो पता नहीं कहाँ से ये सारी चीजें आ जाती हैं! बिल्कुल ठीक बात कही सोमनाथ भारती जी ने कि पहले तो वो सेंटीमेंट्स का व्यापार करते थे और फिर उसको पैसे में बदल देते हैं। पहले तो लोगों की भावनाओं से खेलते हैं, उनसे कहते हैं मंदिर बनाएंगे, मंदिर तो नहीं बना लेकिन उसके नाम की फर्म बना दी, टैम्पल एंटरप्राइजेज प्रा.लि. बना दिया और मजे की बात कि टैम्पल एंटरप्राइजेज बनता है सिर्फ 50 हजार रुपये के कैपिटल से, जिसमें हमारे पूरे हिंदुस्तान के अध्यक्ष भाजपा के, जो उसमें पार्टनर है उनका बेटा, उनका पार्टनर है, उसकी वाइफ उनकी पार्टनर होती है और 80 करोड़ रुपया एकदम से 2015–16 में वहां पर आ जाता है। यह लीगली घूस खाने का तरीका है जी और बड़ा क्लियर से है बेचारे अखबार और न्यूज वालों को इतना डरा दिया गया है कि उस न्यूज को छापते हुए भी उनको डर लग रहा है कि उनका पता नहीं, क्या कर दिया जाएगा। मेरा कहना यही है कि गवर्नमेंट का जो एक स्ट्रक्चर बनता है, उसका मकसद यही होता है कि it is by the people, for the people and of the people and it is for the welfare of the people. उनका

मकसद यह नहीं होता कि डीएमआरसी एक कम्पनी है जो लाइफलाइन बन चुकी है। वो चाहे दंतमंजन बनाना सिखा रही हो, ये आज दंतमंजन बेचना शुरू कर दे या आज जिसकी वजह से लोग आज ट्रेवल कर रहे हैं दिल्ली में तो उसका प्राइस इंक्रीज करके लोगों को ब्लैकमेल करना शुरू कर दे। सिर्फ गवर्नमेंट का यह ध्यान रहता है कि उसको किसी तरीके से मैनेजमेंट करके कमेटी को दोबारा से इसको रिवाइव करके देखना चाहिए कि किस तरीके से उसको मैनेज करके, चाहे जितने भी मैट्रो के स्टेशन्स हैं, वो बहुत प्रोमिनेंट प्लेस पर है, वहां पर मॉल खोले जा सकते हैं, दुकानें खोली जा सकती हैं, मैट्रो में एड वहां पर लगाए जा सकते हैं। एडवरटाइजमेंट का बहुत अच्छे से व्यापार किया जा सकता है लेकिन दिल्ली की गरीब जनता, जो एक जगह से दूसरी जगह जाने के लिए उसका प्रयोग कर रही है। तो उस मां को या उस बेटे को या उस गरीब को जो है, वो मैट्रो छोड़नी न पड़े। हम उसमें बहुत सारी इकॉनोमी मैनेजमेंट कर सकते हैं जिसकी वजह से ये सारी चीजें हो सकती हैं। लेकिन कल मुझे बहुत अचंभा हो रहा था कि जब पूरी दिल्ली सरकार कह रही है कि इसके रेट घटने चाहिए। एक–एक विधायक खड़े हो–होकर कह रहा है कि इसके रेट घटने चाहिए लेकिन लीडर ऑफ अपोजिशन ने, मुझे लग रहा था कि किसी के एजेंट की तरह बिहेव कर रहे थे कि नहीं, इसका प्राइस बढ़ना चाहिए, इसका प्राइस बिल्कुल बढ़ना चाहिए। नहीं तो तीन हजार करोड़ रुपया दो, तीन हजार करोड़ रुपया तो वो ऐसे मांग रहे थे जैसे कि कोई इंट्रेस्ट लेने वाला वो बैंकर होता है जो लोगों से मांगता है, तो उस तरीके से मांग रहे थे। उन्होंने एक बार भी नहीं कहा। हम दिल्ली की जनता के लिए कुछ वेल्फेयर करें। इस पर मैनेजमेंट का कोई ऐसा तरीका लगाएं कि तीन हजार करोड़ रुपये का जो बोझ है, न वो केन्द्र सरकार पर पड़े, न दिल्ली सरकार पर पड़े। कोई 15 सौ करोड़ रुपये किसी को न देने पड़ें लेकिन वो एक ही

बात पर टिके रहे। यहां से दिखाई देता है कि उनकी नीयत नहीं है, वो सिर्फ किसी न किसी तरीके से जिस तरीके से ओला उबर को फायदा पहुंचाया जा रहा है। हमारे प्रधानमंत्री ओला उबर की ऐड कर रहे हैं और वो यहां पर उनके एजेंट की तरह बिहेव कर रहे हैं। यहां पर कह रहे हैं कि किसी तरीके से मैट्रो का रेट बढ़ा दो ताकि वो ओला जो है, वो दबा कर चल सके। हमारे सुखबीर दलाल जी वाला नाम नहीं ले रहा मैं, आप चिंता न करें। ठीक है जी। डीएमआरसी एक लाइफलाइन है पूरी दिल्ली की मैं आपसे सिर्फ यही आग्रह करूंगा कि ये सरकार.... बहुत आम आदमी चुनकर आए हैं। ये दिनेश मोहनिया देख रहे हैं, जरनैल सिंह देख रहे हैं आप। ये छोटे छोटे लड़के.... अजेश जी, ये अपना छोटा छोटा व्यापार कर रहे थे ये लोग, लेकिन ये लोग उस दुःख में से निकलकर आए हैं और आज लोगों की बातों को इस विधानसभा में रख रहे हैं। पूरी विधानसभा इस बात पर संज्ञान ले। एक बार दोबारा से मीटिंग होकर उस प्राइज को जो है, उसको कंसीडर किया जाए और दिल्ली की जनता की पाकेट पर ये बोझ न डाला जाए, धन्यवाद।

अध्यक्ष महोदयः श्री ओमप्रकाश जी।

श्री ओमप्रकाशः अध्यक्ष जी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद जो डीएमआरसी के ऊपर मुझे आपने बोलने का मौका दिया।

मैं पूरे सदन को और माननीय अध्यक्ष जी, सीएम साहब को भी मैंने इसके विषय में सुना। दिल्ली मैट्रो में 50 परसेंट की भागेदारी दिल्ली सरकार की है और यह जिस प्रकार से चर्चा हो रही है उसमें लगता यह है कि दिल्ली सरकार थर्ड पार्टी बन चुकी है जिसका मैट्रो से कोई लेनादेना नहीं है। इसमें अनेकों अनेक चीजें आईं। रिलायंस का भी यहां जिक्र किया और आज मैट्रो में जो किराया बढ़ने की जो आज स्थिति बनी, उनके कारणों

पर कोई चर्चा अब तक किसी सदस्य ने नहीं की। 2002 में मैट्रो का फेयर फिक्स किया गया और 2009 तक चार बार में करीब 121 परसेंट इसका किराया बढ़ा। उसके बाद 2016 में फोर्थ फेयर फिक्सेशन कमेटी का गठन हुआ जिसमें दिल्ली सरकार की ओर से दिल्ली के चीफ सेक्रेटरी ने उसका प्रतिनिधित्व किया और ये पूरा सिलसिला चलते चलते मई 2017 में 91 परसेंट फेयर बढ़ेगा, दो हिस्सों में ये तय हुआ। ये जो बार बार कहा जा रहा है कि दो बार किराया बढ़ा। किराया बढ़ाना किसी को अच्छा नहीं लगता। इस देश का कोई भी नागरिक किसी भी पार्टी का यह नहीं चाहेगा कि नागरिक सुविधाओं में जो किराया या दूसरी चीजें हैं, उसमें बढ़ात्तरी हो। लेकिन ये जो दिल्ली सरकार का थर्ड फेज और फोर्थ फेज में उसके ऊपर ध्यान नहीं देना, जिसकी वजह से मैट्रो का थर्ड फेज डेढ़ साल और फोर्थ फेज ढ़ाई साल लेट होना, यदि ये चीजें समय पर हों तो सवारियां बढ़ेंगी, इनकम भी बढ़ेगी और इसके अलावा जो बात मई 2017 में तय हुई, उसको दिल्ली की सरकार, केजरीवाल जी ने केवल दस दिन पहले संज्ञान में लिया। इतने दिन क्या वो सोते रहे? यदि उसके विषय में कोई बातचीत करनी थी तो 50 परसेंट के आप पार्टनर हैं। आप बैठते एमाइकेबली कोई उसको सोल्यूशन आपको निकालना था। लेकिन चार महीने आप सोते रहे। दस दिन पहले आप हड़बड़ाहट में जागे और एक जो लगातार जो केन्द्र सरकार के ऊपर तोहमत लगाने का एक तरीका है....

... (व्यवधान)

श्री ओमप्रकाशः आप कृपया सुन लीजिए। मेहरबानी करके सुन लीजिए।

अध्यक्ष महोदयः आप अपनी बात रख लीजिएगा जिस मेंबर ने बोलना है, उसको दे दीजिए।

श्री ओमप्रकाशः बार बार ये मामला आया कि रिलायंस का जो मैट्रो एयरपोर्ट वाला राजीव गांधी चौक से उसके बारे में भी मैंने लोगों की बात सुनी। अरे भई, इसका जवाब तो आप दीजिए। 50 परसेंट के पार्टनर आप हैं। जब आप 50 परसेंट के पार्टनर हैं तो रिलायंस के साथ जैसा कि आप कह रहे हैं, कोई घोटाला हुआ, उसमें कोई लेनदेन हुआ। तो 50 परसेंट तो आप लोगों ने भी उसमें लिया होगा और अगर नहीं लिया था तो ये तब बोलना था आपको। आज आपको क्यों याद आ रहा है? जिस दिन ये कान्ट्रेक्ट का ये मामला हुआ था, उस दिन आपको बोलना था। आप यहां तरह तरह की बात कर रहे हैं। तरह तरह की चीजों को लेने की बात कर रहे हैं। मैं अध्यक्ष जी से निवेदन करता हूं, हमने लिख लिखकर दिया है। आज पूरी दिल्ली पानी के लिए हाहाकार कर रही है। लेजीटिमेट लोगों को पीने का पानी... या तो पानी उचित मात्रा में उपलब्ध नहीं है और यदि उपलब्ध है तो उसमें सीवर का मिला हुआ पानी आ रहा है। तो जो जो बेसिक जरूरत की जो चीजें हैं, उनके ऊपर आप सदन में चर्चा के लिए समय नहीं देते हैं। अभी यहां पर सैनिकों का भी मामला आया। किसी भी देश के लिए गर्व और गौरव उसके सैनिक होते हैं। यदि सैनिकों के शवों के साथ किसी स्तर पर कहीं कोई किसी प्रकार की गलती हुई है तो उसके लिए कमेटी भी बैठनी चाहिए और उसके लिए जो लोग जिम्मेदार हैं, उनको सजा भी मिलनी चाहिए, इसके लिए हर देशवासी एकमत है। इसमें कहीं कोई किसी पार्टी का लेना देना नहीं है। लेकिन आज जो हम ये हाहाकार डीएमआरसी के लिए कर रहे हैं। ये चार महीने हम सोते रहे, जब हमारा रिलायंस का ये कांट्रेक्ट था, उसमें सरकार को पैसा देना पड़ा, तब तो दिल्ली सरकार का कोई बयान नहीं आया। तो आज वो समय बीत जाने के बाद जो आप बातें कर रहे हैं, इनका कोई अर्थ है नहीं तो दिल्ली

की जनता को जो विश्व के स्तर की जो एक सुविधा मिल रही है, ये लगातार चले और इसके लिए 50 परसेंट की पार्टनर दिल्ली सरकार होने के नाते अपने दायित्व को निभाये, न कि केवल नाटक और नौटंकी करे। जब हम कोई व्यापार करते हैं तो उस व्यापार में समय भी देना पड़ता है और व्यापार के साथ जुड़ना भी पड़ता है। केवल सदन में बात करने से बातें नहीं बनती हैं। आपने, दिल्ली की सरकार ने अपना दायित्व नहीं निभाया है और इस फैसले में जो फैसला मई में हुआ है, उसमें दिल्ली सरकार सहमत थी तो दिल्ली सरकार जब मई 2017 में सहमत थी तो एक हफ्ते पहले अब यानि कि इस अक्टूबर में आकर असहमत क्यों हो गई? तो ये मेरी समझ से बाहर है और आप जिस प्रकार की भाषा की बात कर रहे हैं, यदि आप उसके पार्टनर हैं और पार्टनर होने के नाते आपको जिस जिस स्तर पर आपका उसके अंदर पार्टीसिपेशन है, उसको आप अपना उपयोग करते हुए जनहित में कम से कम किराये में, आपने मंगूसिंह को भी हटा दिया। आप जो काम करते हैं... आपकी परिधि में आए न आए, आप हटाएं, भगाएं, दूसरा लाएं, तीसरा लाएं, हमें उससे कोई ऐतराज नहीं है। जो आएगा सो काम करेगा। कभी आप कहते हैं हम दिल्ली के मालिक हैं। अरे! दिल्ली के मालिक हो तो तन्ख्वाह क्यों लेते हो? मालिक कभी तन्ख्वाह नहीं लेता है। आप जब यहां चिल्लाते हो, दिल्ली का जो मालिक बहादुरशाह जफर के बाद अंग्रेज रहे हैं। आज जो भी है, वो केयरटेकर है और केयरटेकर को जब ये भ्रम होता है कि वो दिल्ली का मालिक है, तब तब इस प्रकार की दुर्घटनाएं होती हैं। तो मेरा आपसे नम्र निवेदन दिल्ली सरकार से ये है कि इन चीजों को इस तरीके से सड़क पर उछालने की बजाय जो आपका दायित्व है, आप इसमें 50 परसेंट के पार्टनर हैं, जहां जहां आपकी सहभागिता है, उस प्लेटफार्म पर इसको उठाएं और एमाइकेबली दिल्ली की जनता को एक जो वर्ल्ड क्लास सुविधा जो मिल रही है, इसमें क्वेश्चनमार्क न लगाएं। इसकी

जो गरिमा है, उसको खराब न करें और दिल्ली की जनता की जो जरूरत की चीजें हैं; चाहे वो बिजली हो, सड़क हो, पानी हो, शिक्षा हो और या स्वास्थ्य हो, आज दिल्ली त्राहि–त्राहि कर रही है। मेरा आपसे निवेदन है अध्यक्ष जी, मेहरबानी करके इन चीजों की बजाय इनमें से भी किसी न किसी चीज पर एक दिन का पूरा सत्र आप बुलाएं, नमस्कार, जयहिन्द, जयभारत।

अध्यक्ष महोदयः श्री मदन लाल जी ।

श्री मदन लालः अध्यक्ष महोदय, आपने मुझे इस बहुत महत्वपूर्ण विषय पर बोलने का मौका दिया, धन्यवाद।

अध्यक्ष महोदय, 1947 में जब देश आजाद हुआ तो हमारे कान्स्टिट्यूशन निर्माताओं ने राईट टू इक्वेलिटी की बात की और कान्स्टिट्यूशन के फंडामेंटल राईटस में आर्टिकल–14 इनकॉर्पोरेट किया। जिसका मतलब था, सभी को बराबरी का अधिकार। उस बराबरी के अधिकार को मैनटेंन कराने के लिए उसको बरकरार करने के लिए, सब लोगों को समानता का अधिकार देने के लिए, सबको समान बनाने के लिए, बाबा साहब अम्बेडकर का मैं धन्यवाद करना चाहूंगा, उनको नमन करता हूं कि उन्होंने समाज में उस समय फैली डिसपैरिटी को खत्म करने के लिए रिजर्वेशन की बात की और अन्ततः रिजर्वेशन की वजह से समाज का वो डाउन ट्रोडन, वो दलित, वो सबसे ज्यादा कुचला हुआ व्यक्ति भी बराबर आकर खड़ा होने की हिम्मत करने लगा।

आज जब हम देखते हैं कि ट्रांसपोर्ट के साधन; चाहे वो ऐयर हो चाहे, वो बस का ट्रासंपोर्ट हो या रेल का। सबका समान अधिकार है, उनको इस्तेमाल करने का। परन्तु कभी कभी लगता है कि पैसे कि वजह से, बहुत सारे लोग जो अब तक ऐयर ट्रेवल नहीं कर पाते थे, कम्पीटीशन ने उनको

मौका दिया है कि वो आज के दिन ऐयर ट्रेवल कर अपने अधिकारों का वो अपने आप को जो इंडियन सिटिजन होने का गर्व महसूस करना चाहता है, उसको बराबरी का अधिकार मिलने के कारण और समाज में एक नया आयाम, जो आते–आते अभी आज कल आया है और खासकर मैं धन्यवाद करना चाहूंगा हमारे लेबर मिनिस्टर को कि उन्होने पीछे जो मिनिमम वेजिज एक्ट में जो मूलभूत परिवर्तन कर मिनिमम वेजिज को बढाकर लोगों को इतना हक दिया कि वो मैट्रो जैसी आज के दिन जो सरकार सैन्टर सरकार जो लग्जरी बनाना चाहती है, मैं लग्जरी वर्ड क्यों इस्तेमाल करता हूं। हर आदमी इस्तेमाल करना चाहता है मैट्रो को भी। मैट्रो आज के दिन स्टूडेंस का आज के दिन सबसे बड़ा, लेबर का सबसे बड़ा मिडिल क्लास का सबसे बडा साधन है इस्तेमाल करने का। अध्यक्ष महोदय, मैं खुद भी इस्तेमाल करता हूं। जब भी मुझे लगे कि कहीं बहुत जल्दी पहुंचना हो या बहुत सारी विषम परिस्थितियों हों, तब रेलवे सबसे बड़ा साधन है और मुझे लगता है मेरे जैसे हजारों लाखो आदमी इसीलिए मैट्रो का इस्तेमाल करते हैं। अगर मैं कर सकता हूं तो वो मेरा गरीब मजदूर भाई क्यों नहीं कर सकता जो इस देश का बाशिंदा है जिसके लिए अरविंद केजरीवाल जी आज के दिन प्रयत्नशील हैं? वो चाहे मिनिमम वेजिज एक्ट को बढाकर उनकी जो परचेजिंग पॉवर है, उसका बढ़ाने की बात कही गई हो और आज के दिन जब सब ये महसूस करते हैं कि रेलवे का किराया बढ़ाना गरीब और कमजोर लोगों के हित में नही है, तब हम सभी अपेक्षा करते थे कि माननीय केजरीवाल जी की सरकार इसका पुरजोर विरोध करेगी। उन्होंने पुरजोर विरोध किया और केवल विरोध नहीं किया बल्कि दो बातें कही। अध्यक्ष महोदय उन्होंने सबसे पहले ये कहा कि मैट्रो का किराया बिल्कुल नहीं बढाना चाहिए। अगर मैट्रो को पैसे का कैश क्रंच है तो उसके बहुत सारे दूसरे साधन हैं जिसकी वजह से मैट्रो को फायदे का सौदा बनाया जा सकता है। उन्होने इसके

बाद ये कहा कि अगर तीन हजार करोड़ प्रतिवर्ष देने की बात हो तो दिल्ली सरकार पन्द्रह सौ करोड़ देने को तैयार है। सैन्टर की चूंकि भागीदार 50 परसेंट की है, फिफ्टी परसेंट सेंटर दे । हम सभी जानते हैं अध्यक्ष महोदय, यहां सब रोज अखबार भी पढते हैं, टेलीविजन भी देखते हैं कि ये ही केन्द्र की सरकार जो दिल्ली को एक परसेंट भी पैसा देने को तेयार नहीं है, वेस्ट बंगाल में पूरी की पूरी रेलवे लाईन को पूरी मैट्रो लाईन को सब्सिडाईज करने को तैयार रहती है। वो सब जगह जहां कहीं ऐसी सिचुएशन हो, सब्सिडाईज करती है और जहां दिल्ली का नाम आता है, वहीं सौदेबाजी शुरू कर देती है और इसके पीछे एक कारण देखता हूं। माननीय उप मुख्य मंत्री जी ने कल कहा था कि शायद ये ओला और उबर को प्रमोट करने की बात है और अध्यक्ष महोदय मैं बताऊं, पीछे जो मुझे लगता है कि पिछली चाहे वो कांग्रेस की सरकार हो या बीजेपी की सरकार हो, इन्होंने एक–एक करके हमारे सब उद्योग धंधों को बेचने का काम करना शुरू कर रखा है। सबसे पहले दिल्ली महानगर टेलीफोन निगम लि., एमटीएनएल जो इतना बढिया चल रहा था। जो पूरे देश की लाईफ लाइन थी। उसको आहिस्ता आहिस्ता करके बेच दिया और आज के दिन पूरे उद्योग धंधे, पूरी कम्पनियां बाहर की हैं। एमटीएनएल का तो टेलीफोन में तो टेलीफोन का तो नाम लेवा नहीं है। ऐसे करके इन्होंने एक–एक करके बेचना शुरू कर दिया है। चाहे वो किसी देश को बेच रहे हों, चाहे किसी कम्पनी को बेच रहे हों, बहुत सारी है मारूति क्या दुनिया भर की है? अब एक और नया षडयंत्र हो सकता है कि मैट्रो को घाटे का सौदा बताकर किसी प्राईवेट कम्पनी को पूरी की पूरी मैट्रो को सौंप दिया जाए। जिससे ये भी एकछत्र शासन अडानी और अम्बानी जैसे लोगों का हो जाए। हम चाहते हैं, क्यों न गरीब आदमी इस्तेमाल करे मैट्रो को? क्यों वो दस रूपये में इस्तेमाल नहीं कर सकता? Sir, the government has to be a Welfare State. सरकार का

कर्तव्य है अपने सब्जेक्ट का ध्यान रखे। अपने सब्जेक्ट को वो सारी सुविधाएं दें। अपनी सीटिजन्स को जो हर एक आदमी को अधिकार है, चाहे वो अमीर हो, चाहे वो गरीब हो, चाहे वो बिल्कुल नीचे के स्तर पर हो। अगर आज के हम किराये के सेटअप को देखें तो ये किराया इतना बढता चला जा रहा है कि अगर कोई लेबर हो, उस बेचारे के लिए तो पहले जैसे हमारे लिए लग्जरी था हवाई जहाज, आज ये मैट्रो उनके लग्जरी बनता चला जा रहा है ओर मैं ये देखता हूं कि वो दिन दूर नहीं है, अभी तक कुछ संख्या बढी है मैट्रो में सफर करने वालो की। अध्यक्ष महोदय, अगर ये ही हाल रहा तो जो हमारा गरीब मजदूर है, चाहे हमने हिन्दुस्तान में उसकी सैलरी सबसे ज्यादा कर दी, मिनिमम वेजिज एक्ट में सबसे ज्यादा संशोधन करके उसकी तनख्वाह आज के दिन हमने हिन्दुस्तान में सबसे ज्यादा कर दी है, वो भी इसका ऐफोर्ड कर नहीं पाएगा। क्योंकि जिस तेजी से ये किराये बढ़ाए जा रहे हैं, ये बहुत ज्यादा बड़ी मार है और ऐसे में जब दिल्ली गवर्नमेंट बिल्कुल तैयार थी। जब माननीय मुख्य मंत्री जी कह रहे हैं कि हम पंद्रह सौ करोड़ देने के लिए तैयार हैं। पंद्रह सौ करोड़ आप दे दो। जब फिफ्टी–फिफ्टी का शेयर है और हम सब जानते हैं फिफ्टी परसेंट है तो क्यों सैंटर तैयार हो और मैं तो धन्यवाद देता हूं मुख्य मंत्री जी को कि उन्होंने कहा कि मैट्रो हमें दे दो, हम न आपसे पैसे मांगेगे और न इसको घाटे में चलने देंगे, हम मुनाफा कमा कर आपको बता देंगे।

अध्यक्ष महोदय, आज के दिन ये बहुत ही हमारे लिए शर्म और लज्जा की बात है कि हम यहां दिल्ली की चुने हुए विधायक सभी लोग, और हरेक की यह इच्छा थी कि मैट्रो का किराया न बढ़े। ये मैट्रो का बढ़ा हुआ किराया हमारे किसी के घर नहीं जा रहा है, परन्तु हम ये जरूर जानते हैं कि वो गरीब कमजोर व्यक्ति जो मैट्रो को इस्तेमाल करने का अधिकारी है, उसको एक मौका मिलेगा। उसको आज वंचित किया जा रहा है। मैं आपके माध्यम

से उन लोगों तक ये बात पहुंचाने की कोशिश कर रहा हूं, जो लोग इसके बारे में न तो चिन्तित हैं, न इसके बारे में वो सोचना चाहते हैं और अल्टीमेटली उनका केवल एक गोल है कि इस सुविधा को गरीब लोगों से छीन लिया जाए जिससे वो लोग इसका इस्तेमाल न कर सकें और दिल्ली में फिर से एक माहौल पैदा हो जाए जहां, जो दूसरा गवर्नमेंट का ट्रांसपोर्ट का सिस्टम है, उस पर डिपेन्डेन्सी ज्यादा बढ़े जो दिल्ली सरकार के आधीन है और अफरा–तफरी का माहौल है।

इसलिए मैं निवेदन करता हूं और सरकार को धन्यवाद देता हूं कि सरकार ने इस संकट से उबारने की पूरी कोशिश की। पूरी ईमानदारी के साथ ऑफर दिया कि या तो मैट्रो हमें दे दो, हम चलाएंगें, हम आपसे पैसे नहीं मांगेगे, फिफ्टी परसेंट या फिर फिफ्टी गवर्नमेंट दे देती सेंटर फिफ्टी दे देता।

अध्यक्ष महोदय, आपके माध्यम से सरकार से हमारा निवेदन है कि वो इसमें लगातार प्रयत्न करे और इस बढ़ते हुए किराये को रोकने में भरपूर कदम उठाए। सारा सदन आज उनके साथ है।

अध्यक्ष महोदय, इन्हीं शब्दों के साथ मैं माननीय मुख्य मंत्री जी का धन्यवाद करते हुए एक बार कि उन्होने इस किराये की बढ़त को, बहुत ज्यादा मार समझते हुए, सही समय पर इसके लिए काम किया है, मैं आपका धन्यवाद करता हूं।

अध्यक्ष महोदयः बहुत–बहुत धन्यवाद। श्रीमान सत्येन्द्र जैन जी माननीय स्वास्थ्य मंत्री।

स्वास्थ्य मंत्री (श्री सत्येन्द्र जैन)ः आदरणीय अध्यक्ष महोदय, मैं इसी सब्जेक्ट पर दो चार चीजें जरूर आपके सामने बताना चाहूंगा। जब मैट्रो

की कोई भी नई लाइन बनाने का प्रपोजल आता है, उस प्रपोजल के अंदर सबसे पहले ये लिखा होता है कि ये दिस इज नोट ए बिजनेस वैन्चर। ये सोशल वेंचर है। और दिल्ली के अंदर कभी भी उठा कर देख लीजिए 2002 में पहली मैट्रो बनी थी। उससे पहले भी देख लीजिए जब इसका प्रपोजल बना था। फेज—वन बन गया, फेज—टू बना, फेज—थ्री बना, फेज—फोर के भी प्रपोजल मैने खुद देखे हैं। उसका एक ही कारण है कि ये बिजनेस प्रपोजल नहीं है। दिल्ली के अंदर कन्जेशन को खत्म करने के लिए, पॉल्यूशन को खत्म करने के लिए, लोगों को अच्छी सुविधा देने के लिए बनाया जा रहा है। मैं सदन को बताना चाहूंगा आपके माध्यम से कि फेज—थ्री तक एक लाख करोड़ रूपया खर्च हो जायेगा मैट्रो के अंदर अगर जितना हमारे माननीय विपक्ष के सदस्य बिजनेस, बिजनेस, बिजनेस की बातें कर रहे हैं, एक लाख करोड़ रूपये इनवेस्टमेंट करने के बाद मुझे लगता है कि ब्याज भी अगर आठ दस परसेंट लगा लें तो साल का आठ दस हजार करोड़ तो वही बन जाता है मेन्टेनेन्स अगर दो तीन परसेंट भी लगा लें तो दो तीन हजार करोड़ रूपये सिर्फ मेन्टेनेन्स बन जाती है फिर ऑपरेशन के चार्जेज हैं, जो उसके अंदर बिजली का खर्चा है, स्टॉफ का खर्चा है जो ऑपरेशनल चार्जिज हैं और कलेक्शन कितनी हैं मैट्रो की? मुझे लगता है पिछली बार रेट बढ़ाने के बाद दो हजार करोड़ सारी कलेकशन दो हजार करोड़ रूपये की है और ऑपरेटिंग चार्जेज ही दो करोड़ से ज्यादा के होंगे उसके बाद मैन्टेनेन्स को निकाल दीजियेगा और जो शेयर कैपिटल दिल्ली सरकार ने दी, 50 परसेंट और जो केन्द्र सरकार ने दी 50 परसेंट अगर इसको बिजनेस वेंचर मानते तो पैसे के ऊपर कम से कम दो चार परसेंट तो रिर्टन मांगते ना? तो ये रिर्टन के लिए नहीं बनाई गई, सबसे पहले क्लीयर होना चाहिए कि दिस ईज ऐ सोशल वैंचर। दिल्ली का कंजेशन खत्म करने के लिए बनाई थी और ये कोशिश करनी चाहिए थी कि इसके

अंदर ज्यादा से ज्यादा लोग ट्रैवल कर सकें और फेयर जेनुइन होने चाहिये, रीजनेबल होने चाहिए।

मैं आपके सामने एक छोटी सी चीज रखूंगा। एयरपोर्ट मैट्रो है। आपमें से अनेक सदस्यों को पता होगा एयरपोर्ट मैट्रो का किराया पहले 120 रूपये तक था। हमारी सरकार बनी। मुख्यमंत्री जी ने बातचीत की, उनको बुलाया और एयरपोर्ट मैट्रो के रेट आधे करा दिये। मैं सदन को बताना चाहूंगा कि जब 120 रूपये का टिकट था तब जितना कलेकशन होता था, आधा रेट होने के बाद कलेकशन दुगना हो गया। अब ये बताइये कि इनका मकसद किराया बढाना है के कलेकशन बढाना है? अगर मकसद है कि किराया बढाना है, तब तो बिल्कुल बढायेंगे। इनके जो बाकी सदस्यों ने बताया कि इनकी इन्टैन्शन कुछ और है, मैट्रो नहीं है। पोलिटिक्स है या कुछ इनके व्यापारियों से संबंध हैं, जो भी है उसका कारण कुछ और है। अगर कलेकशन न ही बढानी थी, उसके तो बहुत आसान तरीके थे। आप सोच के देखियेगा फिक्स एसेट्स के ऊपर एक लाख करोड़ रूपये खर्च किये।

... (व्यवधान)

श्री ओमप्रकाशः आप बोलते नहीं बैठे हैं तो।

अध्यक्ष महोदयः भई ओमप्रकाश जी, अब ये तरीका ठीक नहीं है। आप बोले नहीं, तो वो अपनी बात रखेगें आप हर जगह, हर बात पर डिस्टर्ब करेगें क्या? रेलिवेंस क्यों नहीं है? फिर आप कहेंगें। मैं बोल रहा हूं। मैट्रो एयरपोर्ट का, जो मैट्रो एयरपोर्ट है, वो किसको दिया गया था? किसके पास ठेका था अनिल अंबानी के पास।

... (व्यवधान)

अध्यक्ष महोदयः हां, रेट कम किये हैं मालूम है, रेट कम किये 60 परसेंट रेट कम किये हैं।

स्वास्थ्य मंत्रीः अध्यक्ष महोदय...

अध्यक्ष महोदयः नहीं, जो वास्तविकता है, वो तो सामने आयेगी। सदन में वास्तविकता को आप, ये नहीं है शोर मचा के दबा देंगे। सदन की वास्तविकता को शोर मचा के नहीं दबायेंगे आप। चलिये।

स्वास्थ्य मंत्रीः अध्यक्ष महोदय, मुझे ऐसा लगता है कि ये विपक्ष को जैसे ही अगर इशारे में भी कहा जाये उन कंपनियों के बारे में, तो बहुत दर्द होता है मैं तो इशारा ही कर रहा था, इन्होंने नाम ले लिया पास...

... (व्यवधान)

अध्यक्ष महोदयः आप बोलिये

स्वास्थ्य मंत्रीः हलवाई की कंपनी नहीं है, लडडू नहीं बनाती, आपकी तरह हलवाई नहीं है।

... (व्यवधान)

श्री नितिन त्यागीः सर, इस आदमी को आप घुसने क्यों देते हो सदन के अंदर?

... (व्यवधान)

श्री नितिन त्यागीः बदतमीज आदमी है सर। ये क्यों आता है सदन में? आप इसे बाहर निकलवाइये।

... (व्यवधान)

श्री नितिन त्यागीः क्यों आता है सदन के अंदर?

श्री सतेन्द्र जैनः अध्यक्ष महोदय, अगर मैट्रो का रेवेन्यू ही बढाना था जो कि इनके प्रपोजल में हमेशा से लिखा होता है, सबसे बड़ी स्टीम है रेवेन्यू की; रियल स्टेट डेवलेपमेंट। रियल स्टेट डेवलेपमेंट के अंदर मैट्रो ने बहुत सारी बिल्डिगें आज तक बना रखी हैं। ईस्ट दिल्ली के अंदर आप शाहदरा मैट्रो स्टेशन देखिये उसमें बहुत बड़ी विशाल बिल्डिग खड़ी है और वो लगता है, म्यूजियम है। उसके अंदर कुछ नहीं है, बस खाली बिल्डिंग है और ऐसी एक नहीं है। प्रताप नगर स्टेशन पर देख लीजियेगा, इन्द्रलोक स्टेशन पर देख लीजियेगा पूरी की पूरी बिल्डिगें, बड़ी विशाल दस दस मंजिल की बिल्डिंग बना दी। अच्छा, मजेदार चीज है कि बिल्डिंगें बना के खाली रख रखी हैं। अरे भई, उनको किराये पर चढ़ा दो। अगर वो किराये पर चढ़ा देंगे तो जनता से किराया इतना मांगने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। केन्द्र सरकार का एक प्रपोजल और हैः *Transit Oriented Development.' Transit Oriented Development के अंदर क्या है कि जितनी भी मैट्रो लाईन्स हैं, मैट्रो लाईन्स के दोनों तरफ आधा किलोमीटर तक या कुछ दो सौ चार सौ मीटर तक जो डेवलेपमेंट है, उसके अंदर एडिशनल एफएआर देंगे। अगर वो उसको लागू कर दें तो मैट्रो की जितनी प्रोपर्टीज हैं, अगर वो सारों की वेल्यू दस हजार करोड़ है तो आज ही वो बीस हजार करोड़ हो जायेगी। वहां से कमा लें जो ये किराया बढ़ा के साल के हजार 15 सौ करोड़ एक्सट्रा करना चाहते हैं इकटठा, वो तो सरकार के एक आर्डर से बढ़ जायेंगे। जनता के ऊपर भार क्यों डालना चाहते हैं? अभी मैंने आपसे बताया एयरपोर्ट मैट्रो के अंदर 120 का रेट कम करके साठ रूपये किया तो कलेकशन दुगनी हो गई। आज मैं सदन के सामने पूरी संजीदगी से कहना चाहता हूं कि आज तारिख है 10 अक्टूबर, मैट्रो से कहियेगा कि

पिछले तीन महीने का डे टू डे कलेकशन अपना पब्लिश कर दें और आज से डेली पब्लिश करना चालू करें। किराया लगभग पैतीस चालीस परसेंट बढ़ाया जा रहा है, कलेकशन देखियेगा कि एक रूपये नहीं बढ़ेगी। अरे फायदा क्या है उस बिजनेस का कि आपने महंगाई तो बढ़ा दी, कलेकशन नहीं बढ़ रही। तो इसका मतलब इनका मकसद, दूसरा वही है जो अभी बात चल रही थी। हमारे को बताया, संजीव जी कह रहे थे कि कुछ प्राइवेट कंपनीज हैं, ये उनको शायद सहयोग करने के लिए कुछ बोला है। अध्यक्ष महोदय, मोटर साईकिल है; कंपीटीशन भी होता है ना किसी मार्किट के अंदर, मैं कहता हूं मैट्रो का किराया आप एक हजार रूपये कर दीजियेगा तो कहां से एक आदमी भी लेकर आयेंगे? क्या? एक आदमी नहीं चलेगा, मैट्रो चलेगी बस। आदमी उसमें नहीं चलेगा। किराया मार्किट फोर्सेज से भी चलता है। मोटर साईकिल के ऊपर पहले दो आदमी अगर चलते थे तो वो मैट्रो में नहीं जाते थे, मोटर साईकिल में जाते थे। अगर वो आज अकेला चलेगा तो वो मोटर साइकिल पर चलेगा, वो मैट्रो में नहीं जायेगा। वो यही चाहते हैं कि मोटर साईकिल वाला आदमी मैट्रो में आ सके। इसी तरह से अब कार वाले को ले लीजियेगा। अगर कार के अंदर सर आज मैट्रो का जो किराया जो इन्होंने आज से किया है, लगभग तीन रूपये किलोमीटर पड़ रहा है। ऐवरेज करें कुछ स्टार्टिंग में तो पांच रूपये किलोमीटर है। ऐवरेज निकालते हैं तो तीन साढे तीन रूपये किलामीटर आता है। अगर दो जने बैठेंगे ना, तो कार सस्ती पड़ती है। तो लोग कहेंगे कि भई, कारें निकाल लो। क्या मैट्रो में जाना! अगर तीन जने हैं या चार जने हैं, तो टैक्सी करेंगे ना, वो मैट्रो क्यों करेंगे? मुझे तो इसमें साजिश की बू आती है कि दिल्ली के अंदर ये कंजेशन बढाना चाहते हैं। फिर बाद में यही लोग चिल्लायेंगे कि देखो सड़क पर बंद है जी। सड़कों पर चलने की जगह नहीं मिल रही है। सड़कों पर चल नहीं सकते जी। तो ये सारी की सारी

जो चीजें हैं, ये साजिश के तहत कर रहे हैं और फिर से मैं इस बात को रिपीट करूंगा कि जो आज से इन्होंने कराये बढाये हैं, वो जनता को तंग करने के लिए बढाये हैं। दिल्ली मैट्रो के अंदर जो केलकुलेशन इन्होंने दिखाई है, ये कहते हैं एक स्केयर मीटर के अंदर 11 लोग ट्रैवल करेंगे। एक मीटर जगह के अंदर 11 लोग इन्टरनेशनल स्टैण्डर्ड जो है, वो पांच से छह लोगों का है। ये ग्यारह लोगों को चला के जो कलेक्शन करना चाहते हैं, चलो, हमने कहा, कोई बात नहीं। 11 भी चल रहे हैं, दिल्ली वाले लोग सहन कर रहे हैं तो अब वो पांच या छह चला के क्या कर लेंगे? आप उसके रेट को बढ़ाते जायेंगे, बढाते जायेंगे, बढ़ाते जायेंगे और इस लेवल पर लेकर जायेंगे! अच्छा, मैं एक चीज और कहता हूं कि ये प्रॉफिट में लाकर दिखायें और रेट दस गुना कर के दिखा दें, तब भी नहीं चलेगा। दस गुने रेट करेंगे तो वहां पर पैसेंजर नहीं मिलेगा। आज जो रेट आ गये हैं, अगर मैट्रो से ये लोग दबाव डालें की डेली पब्लिश किये जायें रेट, और पीछे सौ दिन के अंदर देख लें, अगले सौ दिन में या दस दिन में या 50 दिन में देख लीजियेगा। collection will dicrease. Collection will not increase.

अभी तक, एक चीज और मैं बता देता हूं, ये कल को फिर ये चिल्लायेंगे कि देखो जी, हमारा कलेक्शन एक दिन में तीन करोड़ रूपये था पहले, या पांच करोड़, पांच करोड़ पांच लाख रूपये हो गया। उसके लिखेंगे कि देखो हमने पांच बढा दिया। ऐसा नहीं है। लगभग आठ परसेंट पैसेंजर पर एनम इनके शुरू से आज तक आठ परसेंट बढ़ते हैं। अगर उस पैसेंजर की बढ़ात्तरी को ले लिया जाये तो ये घाटे में जायेंगे, इसके बढाने के बाद और वो उसको कंसीडर नहीं करते हैं। तो भी इनका पैसा बढने वाला नहीं है और सबसे ज्यादा मार किसके ऊपर पड़ेगी? सबसे ज्यादा

मार पडनी है दो कैटैगरी पर; एक जो स्टूडेण्टस हैं। स्टूडेण्टस जो हैं मैट्रो को यूज कर रहे थे पिछले छह महीने के अंदर सात महीने के अंदर किराया दुगने से ज्यादा हो गया है, अब उनको सोचना पड़ेगा। वो मुझे लगता है ग्रुप बना के ओला ऊबर में ही जाएंगे चार बच्चे इकटठे होंगे कि इसको छोड़ो, उसमें चलते हैं। दूसरा जो नौकरी पेशा हैं उनको चुभता है। उन लोगो को, जो तीस रूपये किराया देता था, साठ रूपये किराया देना पड़ेगा साठ रूपये का मतलब जाने के साठ आने के साठ एक दिन में साठ रूपये एक्सट्रा लगे। 25 दिन जाता है तो 1500 रूपये महीना एक्सट्रा लग गये तो इनका तो मुझे ऐसा लगता है जो हमने एक्सट्रा सैलरीज बढाई थी ना, वो सारा का सारा मैट्रो में निकल जायेगी।

अध्यक्ष महोदय, मेरा ये कहना था कि मैट्रो का किराया बढ़ाना इसका सॉलूशन नहीं है। ये प्रॉब्लम को और क्रिएट करने की ये साजिश है, केस को डिफंक्ट.करने की साजिश है कि मैट्रो सफल न हो और इसके अंदर आम आदमी सफर न कर सके इसमें एलीट क्लास के लिए फिक्स कर दिया जाये और फाइनेंसेस को, फिर बाद में थोड़े दिन धक्के खायेंगे, अब दोबारा रेट बढ़ा लेते हैं। मुझे लगता है इसको दोबारा से विचार करने की आवश्यकता है, धन्यवाद

अध्यक्ष महोदयः अब लंच ब्रेक सवा दो बजे हम मिलेंगे।

(सदन की कार्यवाही चायकाल के लिए स्थगित की गई)

सदन अपराह्न 2.21 बजे पुनः समवेत हुआ।

माननीय अध्यक्ष महोदय (श्री राम निवास गोयल) पीठासीन हुए।

अध्यक्ष महोदयः ऋतुराज जी।

श्री ऋतुराज गोविन्दः आदरणीय अध्यक्ष महोदय, आपका बहुत–बहुत धन्यवाद करता हूं कि आपने मुझे इस टॉपिक पर बोलने का मौका दिया। जैसे कि अभी साथी कह रहे थे कि दूसरी बार, कल हम लोगों ने मैट्रो पर जब चर्चा करी थी तो मैंने जैसा कि कहा था कि दिल्ली मैट्रो राजधानी क्षेत्र, दिल्ली की लाइफ लाईन है और ये जो फेयर हाईक हुआ है, इससे सबसे ज्यादा किसी सेग्मेंट ने अगर परेशानी उठाई है तो वो हैं, वो 32 लाख लोग जो हर रोज मैट्रो से अपने वर्कप्लेस पर जाते हैं, एजुकेशन सेंटर्स जाते हैं, कॉलेजिज जाते हैं स्टूडेंटेस, गरीब लोग, लोअर मिडिल क्लास के लोग और वो मिडिल क्लास, जो कि मैट्रो का जो उद्देश्य था, वो ये था कि एक ऐसा ट्रांसपोर्टेशन सिस्टम इस शहर को देना जिससे कि रोड का जो लोड है, वो कम हो सके। पॉल्यूशन जो कि बढ़ता जा रहा था जो कि सबसे बड़ी समस्या बन गई है क्षेत्र के अंदर, शहर के अंदर, उसको हम कम कर सकें। ये जो ट्रांसपोर्टेशन सिस्टम को बैलेंस करने के लिए मैट्रो का कंपलीट ऑब्जेक्टिव था जिसको लेकर के इनिशियली इसका जो प्राइज है, टोकन एमाउंट वो बहुत रिजनेबल रखा गया और जिसका असर भी हमें देखने को मिला कि आज 32 लाख लोग मैट्रो की सवारी करते हैं जिससे कि बहुत ज्यादा इस चीज पर पूरा बैलेंसिंग सिस्टम पर फर्क पहुंचा है। रोड ट्रांसपोर्ट हो, मैट्रो हो, रेल ट्रांसपोर्ट हो लेकिन हमने देखा कि जैसे ही मई के अंदर फेयर हाईक हुआ, हमने देखा कि 2 लाख लोग, 2 लाख कम्यूटर्स की कमी हो गई।

मैंने कल भी इस बात को कहा था, आज फिर कह रहा हूं कि किराया बढ़ाकर के मैट्रो को आप फायदे में नहीं ला सकते हो। फायदे में लाने के बहुत सारे तरीके हैं। मैट्रो के पास बहुत सारी जगह है, कमर्शियल मार्केटस को डिवलेप कर सकते हो, ऐडवर्टाइजमेंट कंपनीज को दे सकते हो और वो तमाम चीजें की जा सकती हैं, कैपेसिटी बिल्डिंग की जा सकती है और भी चीजें की जा सकती हैं। कॉस्ट कटिंग की जा सकती है। बिजनेस मैनेजमेंट के स्टूडेंट रहे हम लोग लेकिन इन्होंने किसी भी तरीके के ऊपर कोई काम नहीं किया। सीधा तरीका एक ही मिला कि इसका दाम बढ़ा दो, उससे जो है, मैट्रो फायदे में आ जाएगी। मैं गारेंटी के साथ रिकॉर्ड पर कह रहा हूं कि इनका घाटा पूरा नहीं होगा। दो लाख लोग पहले कम हुए, अब इन्होंने मैट्रो का किराया बढ़ा दिया। सुबह से मैं तमाम मैट्रो स्टेशन्स पे घुमा हूं, तमाम रूट्स पर गया देखने के लिए, बात करने के लिए। स्टूडैन्टस लिटरली इस बात को कह रहे थे कि ये कैसा तरीका है! हिंदुस्तान की राजधानी है दिल्ली, यहां पर तमाम प्रांतों से बच्चे सब पढ़ने के लिए आते हैं और ऐसी जगह पर रहते हैं, जहां पर उनको सस्ते में घर मिल जाए, सस्ते में कमरा मिल जाए और बड़े–बड़े एजुकेशन सेंटर में जाकर पढ़ते हैं, कॉलेजिज में पढ़ते हैं। बिहार, उत्तर प्रदेश के गरीब लड़के सब आकर पढ़ते हैं और आपने 32 किलोमीटर का किराया 60 रूपये कर दिया, 117 परसेंट का हाईक हो गया। हिन्दुस्तान तो छोड़िए, पूरी दुनिया के किसी भी, किसी भी देश के अंदर कहीं पर भी 117 परसेंट का हाईक आज तक कभी नहीं मिला है, गूगल करके थक गए, कहीं नहीं मिला, किसी भी देश में आज तक कहीं नहीं मिला। अरे 10 परसेंट का हाईक सैलरी में नहीं होता है, 117 परसेंट का हाईक आपने मैट्रो में कर दिया। अगर घाटा हो रहा था, सालों से हो रहा था तो फेयर कमेटी कहां सोई हुई थी आपकी?

ये कोई तरीका थोड़ी होता है कि आप 117 परसेंट का हाईक कर दोगे! स्टूडैंटस से आज मेरी बात हुई जब सुबह तो वो कह रहे थे कि ये इतना बेकार सिस्टम हो गया है कि वो मजबूर हो गए हैं, या तो मोटर साईकिल इस्तेमाल करेंगे या बसेज का इस्तेमाल करेंगे या कोई दूसरा मीन्स ऑफ ट्राँस्पोर्ट इस्तेमाल करेंगे because they cannot afford such a big amount to pay in Metro.

अध्यक्ष महोदय, अब आपके माध्यम से एक चीज कहना चाहते हैं कि हम ऐसे विधान सभा क्षेत्र के प्रतिनिधि हैं, जहां गरीब लोग रहते हैं। वहां पहले क्या था कि जी, पीने का पानी नहीं था और जो डवलपमेंट चार्ज होता है, पानी के कनैक्शन के लिए, वो 440 रुपया पर सक्वैयर मीटर के हिसाब से हुआ करता था। यानि की कोई गरीब आदमी अगर 100 गज का प्लॉट है, पानी का कनैक्शन लेता था तो 50 से 60 हजार रुपया उसको डवलपमैंट चार्ज देना पड़ता था पानी के कनैक्शन के लिए जिसके चलते वो क्या करता था, वो पानी का लीगल कनैक्शन नहीं लेता था। वो 2–3 हजार रुपया प्लंबर को देता था, इलीगल कनैक्शन ले लेता था। उससे क्या होता था कि कम्पलीट सरकार का रेवेन्यू लॉस होता था। हमने क्या किया? हमारी सरकार आई, हमने 87 रुपया गज कर दिया, हर परिवार को 20 से 50 हजार का फायदा हुआ और साथ में 60 हजार लोगों ने पानी का कनैक्शन लिया, उससे क्या हुआ सरकार को करोड़ो रुपए का रेवेन्यू आया और हमने 80 कालोनी में पानी की लाइन बिछा दी। इस फार्मूले से हमारी सरकार काम करती है। हमने वैट को पाँच परसेंट किया, कम किया तो हमारा रेवेन्यू बढ़ गया, इनका फार्मुला है कि जीएसटी को 28 परसेंट कर दो। अगर 28 परसेंट करने से आपका रेवेन्यू बढ़ता तो बता दो आज सबको परेशानी क्यों हो रही है? आपको लगता है कि मैट्रो का किराया बढ़ाने से

घाटा पूरा होगा, ये फार्मुला बिल्कुल गलत है, ऐसा नहीं हो सकता है। मैट्रो का किराया बढाकर के 3–4 लाख लोग और मैट्रो में सफर करते हैं वो सफर करना बंद कर देंगे और दूसरी मीन्स ऑफ ट्राँस्पोर्ट के ऊपर उसका वजन बढ़ेगा और अभी आने वाले समय में ठंड शुरू हो रही है। ठंड के अंदर दिल्ली वैसे ही गैस का चैंबर बन जाता है, इसका ओवर ऑल इम्पैक्ट लोगों के हैल्थ पे पड़ेगा और गैस चैंबर जब बनता है तो सबसे ज्यादा इम्पैक्टिड सैगमेंट जो होता है, वो बच्चे होते हैं, छोटे–छोटे बच्चे होते हैं, कई बार तो डैथ केसिज भी देखा गया पॉल्यूशन की वजह से, सांस की प्रॉब्लम की वजह से, बहुत सारे केसेज खासकर के नवम्बर, दिसम्बर, जनवरी, फरवरी के महीने में आता है, जब दिल्ली के अंदर ठंड हो रही होती है। अध्यक्ष महोदय, तो इसको हमें इस तरीके से देखना पड़ेगा कि ये जो मैट्रो का जो फेयर हाईक हुआ है, ये बिल्कुल भी बर्दाश्त के लायक नहीं है, ये चीज मैंने कल भी कहा था, इसका पुरजोर विरोध हमने किया और शाम को जो है इन्होंने किराया बढ़ा दिया। डीएमआरसी की जो बोर्ड की मीटिंग हुई, उसकी जो बैठक हुई, उसके अंदर हमारे पाँच रिप्रजैंटिड थे, स्टेट गवर्नमेन्ट के, We are 50 percent stake holder. लेकिन हम लोगों ने जब उनपे मीटिंग के अंदर विरोध किया, उसके बावजूद भी हमारी नहीं सुनी गई। ऐसी क्या जल्दबाजी है! घाटा तो कलकत्ता मैट्रो में भी हुआ था जैसा कि कल मैंने कहा था। कलकत्ता मैट्रो भी इस देश के अंदर है। कलकत्ता के अंदर 1971 से मैट्रो चल रहा है उसको भी घाटा हुआ, पांच ही रुपए में मैट्रो चल रहा है, गरीब आदमी सबके लिए चल रहा है लेकिन उसका जब घाटा हुआ तब केन्द्र उसको भरा था और हम तो ये भी नहीं कर रहे कि आप 100 परसेंट घाटा भर दो। माननीय मुख्यमंत्री अरविन्द केजरीवाल जी ने लिखित में इस बात को चिट्ठी लिख कर कहा कि अगर तीस हजार करोड़ रुपए का घाटा हुआ है तो 1500 करोड़ रुपया हम देने के तैयार

है, As we are fifty percent stakeholder. 50 परसेंट स्टेक होल्डर केंद्र है। आप 50 परसेंट दे दीजिए, 50 परसेंट हम दे देते हैं।

अध्यक्ष महोदय, जबकि हकीकत है कि दिल्ली से लाख, एक लाख करोड़ से भी ज्यादा रुपया टैक्स के रूप में दिल्ली की जनता केन्द्र सरकार को देती है तब जाकर के केन्द्र की व्यवस्था चलती है लेकिन दिल्ली के लोगों को जब आज जरूरत है तो आप 1500 करोड़ रुपए की सब्सिडी नहीं दे सकते हो, इससे बड़ा सेमफुल कुछ नहीं हो सकता है! कुछ नहीं हो सकता है! क्योंकि हमने खुद डाटा पढ़ा है कि डेढ़ लाख करोड़ रुपए से ज्यादा दिल्ली के टैक्सपेयर टैक्स के रूप में दिल्ली के लोग टैक्स के रूप में सरकार को चुकाते हैं जिसमें से 40 हजार करोड़ रुपया हमारा बजट है, उससे एमसीडी से लेकर के केन्द्र सरकार इज द मोस्ट स्टेक होल्डर। सबसे ज्यादा पैसा केन्द्र के पास जाता है। एक लाख करोड़ रुपया से ज्यादा टैक्स का पैसा केन्द्र को जाता है। हमें सिर्फ 325 करोड़ मिलता है, एक लाख करोड़ से ज्यादा कौन दे रहा है? ये दिल्ली की जनता है, वो स्टूडेंट हैं, कोई गरीब आदमी है, कोई रिक्शा वाला है, जब वो माचिस की तीली भी खरीदता है, उस पर सेल्स ड्यूटी, एक्साइज ड्यूटी, न जाने कितने सारे टैक्स देता है। वो टैक्स पेयर का पैसा है, लेकिन आज टैक्स पेयर को जब एक मैट्रो नाम कर दे, ये पूरा का पूरा जो ट्रांस्पोर्टेशन सिस्टम है, आज जब उसपे सब्सिडी देने की बारी आ रही है तो केन्द्र सरकार करना नहीं चाह रही है। इसका मतलब ये साफ तौर पर दिखता है कि ये राजनीतिक षड्यंत्र के अलावा कुछ नहीं है। अगर आप कलकत्ता को हन्ड्रेड परसेंट वेव ऑफ कर सकते हो तो 50 परसेंट दिल्ली को क्यों नहीं कर सकते हो? देश की राजधानी है। कलकता को 11 हजार करोड़ दिया, तो 1500 करोड़ क्यों नहीं दे सकते, जब कि स्टेट गवर्नमेन्ट तैयार है। तो आपको

सोचना पड़ेगा कि हिन्दुस्तान के उन 16 राज्यों से भी स्टूडैंट यहां आकर पढ़ते हैं जिन 16 राज्यों में भारतीय जनता पार्टी की सरकार है और मेरा तो कहना है सदन के माध्यम से हिन्दुस्तान के उन तमाम नौजवानों को जो दिल्ली में आकर के पढ़ रहे है और आकर के पढ़ने की इच्छा रखते है कि पूरे देश के अंदर इसका विरोध होना चाहिए, पूरे देश के अंदर भारतीय जनता पार्टी मुर्दाबाद होना चाहिए, केन्द्र सरकार के खिलाफ पुतला फुंकना चाहिए और इनको ये साफ जताना चाहिए कि आप जनहित के मामले में इस तरह के अगर फैसले लोगे तो ये सदन, यहां के नौजवान, यहां के जनप्रतिनिधि इसको बिल्कुल भी बर्दाश्त नहीं करेंगे, नहीं करेंगे, नहीं करेंगे।

अध्यक्ष महोदय, इस पर हम इतना ही कहना चाहेंगे आपसे कि ये लोग कहते थे राम मंदिर बनाएंगे, मंदिर बनाएंगे, अयोध्या में मंदिर बनाएंगे। अयोध्या में तो मंदिर बना नहीं, टैंपल, क्या बोले थे वो? टैंपल इंटरप्राइजेज बन गया। 16 हजार गुणा ऐसा कौन सा बिजनेस फार्मुला है जी! नोटबंदी में, क्या बोलते हैं, जीएसटी में कोई फल–फूल रहा है तो सिर्फ इन्टरप्राइजिज, टैंपल इंटरप्राइजिज! चुनाव हुआ, बोले, ''काला धन आएगा, सब आदमी को 15–15 लाख मिलेगा।'' सबका जनधन का अकाउंट खोल दिए। गरीब आदमी सब लाइन में खड़ा था, बोला, ''अकाउंट खुल रहा है तो इसका मतलब कुछ न कुछ तो आएगा।'' सब आदमी उम्मीद में था, काला धन आएगा, नोट बंदी भी हो गया, सब ओर खुश हो गया कि काला धन आएगा। तो सब गरीब आदमी को पैसा मिलेगा, जनधन अकाउंट के अंदर लेकिन जनधन का अकाउंट खोल कर उम्मीद बांध दिए, काला धन भी आने वाला था, 15–15 लाख भी मिलने वाला था। अरे! हम तो केन्द्र सरकार से कहना चाहते हैं, 15 लाख तो छोड़ो, 15 हजार देके बोहनी ही कर दो। है कि नहीं, लेकिन नहीं, वो जनधन में 15 हजार का बोहनी नहीं हुआ लेकिन

मैट्रो का किराया बढ़ गया। आज छोटे से छोटा व्यापारी रो रहा है। संजीव झा जी बोले, इनके गांव में बाढ़ आ गया, बीसियों जिला बिहार का डूब गया, अब वहां का आदमी वापस दिल्ली आया, सोचा कि हो सकता है कि पूर्ण का फैक्टरी में नौकरी मिल जाएगा, वो पूर्ण का फैक्टरी ही बंद और सबसे बड़ी बात तो अलका बहन जी कह रही थी।

अध्यक्ष महोदयः ऋतुराज जी कन्क्लूड करिए, प्लीज कन्क्लूड करिए।

श्री ऋतुराज गोविन्दः तो वो क्या बोलते हैं, जयचंद शाह, उसका फैक्टरी या तो चल रहा है या नहीं चल रहा है। चल रहा है तो 16 हजार गुणा कैसे बढ़ गया, नहीं चल रहा है तो इसका मतलब ये हुआ कि नोटबंदी और जीएसटी का असर तो उस पर भी पड़ा। तो इनके पास कोई जवाब ही नहीं है। मैं एक चीज कहना चाहता हूं अध्यक्ष महोदय कि ये लोगों के पास एचीवमैंट के नाम पर साढ़े तीन साल में गाय–गोबर के अलावा कुछ नहीं है और ढ़ाई साल के अंदर सारा देश देख रहा है दिल्ली के अंदर शिक्षा में क्रांति, चिकित्सा में क्रांति, बिजली, पानी, शिक्षा, चिकित्सा, रोड, नाली, सारी बुनियादी चीजें हम दे रहे हैं। तमाम जगह पर ढ़ाई साल के अंदर ये कम्पेयर करने लग गए लोग कि एक तरफ गुजरात मॉडल है, एक तरफ ये दिल्ली का मॉडल है। गुजरात के अंदर ये साढ़े पांच हजार मिलता है गैस्ट टिचर्स को, हमारे यहां 36 हजार मिलता है गैस्ट टीचर को और हमने परमानेंट करने का आदेश दिया। वहां पर साढ़े तीन हजार मिलता है आंगनवाड़ी वर्कर्स को, हमारे यहां पर 12 हजार मिलता है आंगनवाड़ी वर्कर्स को अभी बढ़ाए हुए पैसे के हिसाब से वहां पर पाँच सौ मिलता है, बुजुर्गों को पेन्शन हमारे यहां 2500 मिलता है बुजुर्गों को पेन्शन, वहां पर दो सौ मिलता है विकलांगों को पेंशन । हमारे यहां दो हजार रूपये विकलांगों को पेंशन मिलता है, तुम्हारे यहां पर मिलता है विधवाओं को पेंशन तीन

सौ रुपया। हमारे यहां मिलता है 2500 हजार रुपया। ये सिर्फ ढ़ाई साल में करके दिखाया, एचीवमेंट के नाम पर एक नहीं एक लाख काम हैं लेकिन जब–जब पब्लिक इन्ट्रेस्ट की बात आती है।

अध्यक्ष महोदयः ऋतुराज जी अब कन्क्लूड करिए, प्लीज। कन्क्लूड करिए।

श्री ऋतुराज गोविन्दः तब–तब ये मोदी सरकार पता नहीं क्या साँप सूंघ जाता है, तो मैं आज यही कहना चाहता हूं।

अध्यक्ष महोदयः प्लीज ऋतुराज जी, अब कन्क्लूड करिए।

श्री ऋतुराज गोविन्दः अध्यक्ष महोदय, आज तक हमने जब भी भाषण दिया है, आपको कभी भी कहने की जरूरत नहीं पड़ी कि कन्क्लूड करिए। आज पहली बार कहने की जरूरत पड़ रही है, क्योंकि आज सुबह से कम से कम 10 मैट्रो स्टेशन पर गए, वहां पर गरीब अम्मा मिली, वहां पर गरीब नौजवान मिला, बिहार यूपी का नौजवान मिला, पढ़ने आता है, कॉलेज जाता है, स्टूडेंट है, एजूकेशन सैंटर जाता है, यूपीएससी की तैयारी करने जाता है और इतना ही नहीं है, महिलाएं मिली डेली वर्कर्स मिली जो कि गुड़गांव जाती हैं, नोएडा जाती हैं, जब भी जाती हैं, 32 कि.मी. से ज्यादा डिस्टेंस पड़ता है और एक तरफ से 60 रूपया दूसरी तरफ से 120 रूपया, कहां का न्याय है? अगर 120 रूपया रोज लगेगा तो महीना में कितना लगेगा? छः से सात हजार लगेगा। जिसकी तनख्वाह 20 हजार, जिसकी तनख्वाह 25 हजार है, वो सात हजार रूपया मैट्रो को देगा तो घर क्या लेकर जाएगा?

अध्यक्ष महोदयः गोविन्द जी अब कन्क्लूड करिए ऋतुराज जी।

श्री ऋतुराज गोविंदः पानी का बिल कहां से भरेगा, खाएगा क्या, कमाएगा क्या!

अध्यक्ष महोदयः रितुराज जी कन्क्लूड करिए अब प्लीज।

श्री ऋतुराज गोविंदः मैं इतना कहना चाहता हूं, बहुत–बहुत धन्यवाद अध्यक्ष महोदय, थैंक्यू।

अध्यक्ष महोदयः राजेश गुप्ता जी।

श्री राजेश गुप्ताः अध्यक्ष जी, आपने बोलने का मौका दिया, बहुत–बहुत धन्यवाद। वैसे लगभग सारे प्वाइंट्स कवर हो चुके हैं। ये जो मैट्रो के फेयर बढ़ाने की बात हो रही है या बढ़ ही गए हैं बल्कि कल से। मुझे ऐसा लगता है कि विपक्ष के साथी भी इस बात से बड़े दुःखी हैं। आज का जो माहौल मैं देख रहा हूं सुबह से चुप शांति से बैठे हुए हैं, बीच–बीच में थोड़ा बहुत उठ जाते हैं। लेकिन इनको भी पता है कि इनकी विधानसभाओं में ये दिक्कत हो रही है लेकिन बोल नहीं पा रहे ये। बड़े ताकतवर लोग हैं मुझे पूरी उम्मीद है कि....

... (व्यवधान)

अध्यक्ष महोदयः भाई आपका नाम लिखा हुआ है, ऐसा ना कहिए।

श्री राजेश गुप्ताः मुझे पूरी उम्मीद है कि ये भी उसका विरोध करेंगे क्योंकि ये भी जानते हैं कि इनकी विधानसभा में भी जिन लोगों इन्हें वोट देकर भेजा है, तकलीफ हर जगह हो रही है। लोग इनसे भी शिकायत कर रहे होंगे और सिरसा साहब को रात को नींद भी नहीं आती है। उन्हें मालूम है, लोगों की जब भी तकलीफ होती है, तो वो बोलते हैं। शर्मा जी को बहुत गुस्सा आता है। तो इन बातों पर गुस्सा जरूर आना चाहिए जो पब्लिक से जुड़े हुए होते हैं और ये मुद्दा सिर्फ फेयर इंक्रीज होने के तरीके से हम न देखें, ये रोड सेफ्टी का भी मुद्दा है क्योंकि दिल्ली सरकार

के अस्पतालों को देखने का सौभाग्य मुझे मिलता रहा है। अगर आप पास में ही जो ट्रॉमा सेंटर है, बहुत दूर जाने की जरूरत नहीं है। अगर आप वहां देखें तो जो सबसे ज्यादा एक्सीडेंटल केसिज आते हैं, वो बाइक्स और स्कूटर्स के आते हैं और जब आप इस तरीके का हाइक देंगे, फेयर इस तरीके से इंक्रीज होंगे, तो जो बच्चे है 18–19–20 साल के बच्चे हैं जो सबसे ज्यादा काम पर भी लगते हैं या कालेजेज में भी जाते हैं, वो अपने पेरेन्ट्स से आज ये डिमांड करने लगे हैं और अब पेरेन्ट्स भी सोचने लगे हैं कि इकॉनिमिकली ये है कि बाइक दे दो। एक तो ए टू व्हीलर तक पहुंच जाएगी और जब कैलकुलेशन करते हैं तो फायदा दिख रहा है। उससे रोड सेफ्टी के लिए भी बहुत बड़ा खतरा पैदा होगा क्योंकि बाइक्स सड़कों पर ज्यादा आयेंगी और चाहे कोई भी ट्रॉमा सेंटर हो, कोई भी हॉस्पिटल हो, दिल्ली के उसमें एक्सीडेंटल्स.... इन ऐनी केस दिल्ली पूरी दुनिया की एक्सीडेंटल कैपिटल है। सबसे ज्यादा केसिज हमारे यहां होते हैं।

इसके अलावा वूमेन सेफ्टी जब अभी मेरे कुछ साथियों ने कहा कि बहुत सारे लोग, ओला को शायद जैसे प्रमोशन की जो बात हो रही है। आप जानते हैं कितने केसिज पीछे आए हैं। एक अकेली लड़की उसके अन्दर जा रही है, एक अकेली बहन हमारी जा रही है उसमें, सेफ्टी के लिए मैट्रो बहुत ज्यादा सेफ है। क्योंकि इतने सारे लोग होते हैं या आदमी जब उससे उतरता है तब भी बहुत सेफ है, जब चढ़ता है तब भी बहुत सेफ है। लेकिन वूमेन सेफ्टी बहुत बड़ा इशू बनता है। जब खुद जो प्राइवेट ट्रांसपोर्ट लेंगे जब हम, तो उससे बहुत ज्यादा दिक्कतें आयेंगी। ओला हो चाहे ऑटो हो या कोई खुद अपनी स्कूटी चला रही हो, ये बहुत बड़ा इशू बनेगा। पॉल्यूशन, कुछ लोगों ने इस पर चर्चा करी और कमाल की बात है, अभी क्योंकि कल ही एससी ने उसको बेन करा। बड़ी सोचने की बात

है कि सुप्रीम कोर्ट ने अगर ये कहा है कि पाल्यूशन के उपर, पटाखे बैन कर देने चाहिए दिवाली के ऊपर तो कमाल की बात है! दिवाली तो साल में एक ही बार आनी है लेकिन जो स्कूटर चलने हैं, जो मोटरसाइकिलें चलनी हैं, वो तो रोज चलेंगी। ये तो रोज कई हजार पटाखे छोड़ने वाली कहानी है, इतना पॉलूशन होगा। अब हर बार हम ऑड–इवन करते हैं, तब भी कुछ लोगों को दिक्कत आती है लेकिन एक जो बहुत आसान था कि पब्लिक ट्रांसपोर्ट हम दें क्योंकि हमारे बहुत सारे साथी बाहर गए हैं और विपक्ष के साथियों की तो बाहर प्रॉपर्टीज भी काफी हैं। आपने वहां देखा ही होगा कि वहां पर पब्लिक ट्रांसपोर्ट का साधन इस किस्म से रखा गया है कि अगर मैं अपना ही उदाहरण दूं तो हम न्यू जर्सी से न्यूयार्क जाते हैं तो आज भी 20 डालर की टिकट है आने–जाने की, तो वो बहुत सस्ता पड़ता है इतने की पार्किंग लग जानी है न्यूयार्क के अन्दर। वहीं यहां पर एक मॉडल था कि अगर हम कनॉट प्लेस जाते हैं और अगर अपनी गाड़ी लेकर जाते हैं वहां पर खड़ी करते हैं वहां पार्किंग करते हैं, उसके पैसे लगते थे, मैट्रो बड़ी सस्ती पड़ती थी, मैट्रो पकड़ी और हम वहां पहुंच गए। लेकिन आज आपने मैट्रो के किराए को जिस तरीके से बढ़ाया, अगर मैं अपने परिवार के साथ वहां जा रहा हूं खास तौर से तीन या चार लोग जा रहे हैं, किसी हाल में भी गाड़ी वहां सस्ती पड़ेगी। एक एक्सयूवी जो 30–35 लाख रूपये की होगी, जिनमें ये जाते हैं, इनके पास तो वैसे 90 लाख वाली सिरसा जी के पास, उसकी तो एवरेज ही 5–6 की आनी है। तो ये तो मैट्रो में कभी सोच ही नहीं सकते, मैट्रो खरीदने की तो सोच सकते हैं। मैट्रो में सफर की कभी नहीं सोचेंगे और ये जो सर, ये जो हिन्दी का सफर था, उसे अंग्रेजी का सफर मत बनाओ। लोग सफर करना चाहते हैं, उस मैट्रो में आपने अंग्रेजी का सफर करा दिया कि नहीं, चार बंदे गए तो कार्ड में ही हो गया उनका तो काम। 200–400 रूपये तो

आने–जाने में उसके लग जाने हैं। गरीब आदमी सोच भी नहीं सकता जो कनॉट प्लेस में जाता था, पार्क में बैठकर आ जाता था। वो कुछ नहीं करता था। पिक्चर–विक्चर नहीं देखता था। उसके पास इतने पैसे नहीं हैं लेकिन वो सफर भी आज अंग्रेजी का सफर हो गया है। हिन्दी के सफर से बहुत दूर चले गए हैं। टाइम का कितना नुकसान होगा, आप ये सोचिए! इससे इकॉनमी को बहुत नुकसान है क्योंकि टाइम जो है, मैट्रो में सबसे ज्यादा सेव होता है लेकिन आदमी जब अंदाजा लगाता है कि पैसे बच रहे हैं, चलो यार, टाइम लग रहा है, कोई बात नहीं। क्योंकि जब वो टू–व्हीलर्स में घूमेगा, जब वो गाड़ियों में घूमेगा, वो दुनिया भर का उसके अन्दर नुकसान करेगा। अब सवाल ये है कि जब सुप्रीम कोर्ट ने भी ये कहा जब दिल्ली की हर तरफ से बात निकलकर आ रही है कि रेट बहुत नाजायज बढ़े हैं, गलत बढ़े हैं। दिल्ली सरकार हर साल 700–800 करोड़ रूपये इसमें देती है और अभी आगे भी 2600 करोड़ रूपये की डिमांड है। मुझे एक बात समझ में नहीं आती कि ये ही एमसीडी के अन्दर बार–बार सुना करते थे कि हम पैसे तो दे देंगे, हिसाब नहीं मांगेंगे। अरे! कहां गए 700–800 करोड़ रूपये जो हर साल जाते हैं? आप कह रहे हो नुकसान हो रहा है। अब ये तो कोई बच्चा भी, हम बहुत सारे यहां पर व्यापारी हैं, मेरे को ये समझ में नहीं आता कि अगर हम कोई भी व्यापार करते हैं, छोटी से छोटी आप दुकान खोलें, फैक्ट्री खोले अगर आप उसके रेट बढ़ायेंगे, गॉरन्टी की बात है कांपिटिशन जो है। आपको नुकसान में आ जाएगा और जो आपका कापीटेटर, वो सस्ते रेटों में होगा तो उसके पास चीजें चली जायेंगी। ये कौन सा तरीका है फायदे में आने का कि रेट बढ़ा दिए जाएं? अगर ऐसा होता तो जैसे अभी मेरे भाई ने मुझसे पहले कहा है कि दिल्ली की सरकार ने तो तीन साल लगातार टैक्स घटाए हैं, और रेवेन्यू बढ़ा। ये जो इनका हिसाब–किताब है, मैं एक आंकड़ा बताता हूं एक हिसाब–किताब मेरे पास

में है कि मई 2017 से पहले जब रेट उतने थे, जो हुआ करते थे, कई साल रहे, उससे पहले जो बीजेपी का ग्राफ था, ठीक—ठाक था, दिल्ली में हम सब ये मानते हैं। फिर भी उन्होंने रेट बढ़ा दिए सर, और हुआ बवाना इलेक्शन तो जितने परसेंट आपने रेट बढ़ाए, उतने ज्यादा परसेंट आपके पॉपुलेरिटी डाउन हो गई। अब सर, आपने फिर अक्टूबर में ये मेहरबानी कर दी हमारे ऊपर लेकिन क्योंकि ये सरकार एक पॉलिटिकल सरकार नहीं है, अगर एक पॉलिटिकल तरीके से देखते तो आज हम चर्चा मैट्रो पर नहीं करते सिरसा जी, आज हम चर्चा कर रहे होते दिल्ली के अन्दर जो हमने 6000 कमरे बनाए। ये गारन्टी दे रहा हूं मैं आपको। कभी आज तक सुनने में भी नहीं आया कि 6000 कमरे, कोई छोटी चीज नहीं होती लेकिन वो 6000 कमरे हमने बनाए, खोल दिए चुपचाप। लोगों को मालूम है जो बच्चे वहां पढ़ने के लिए जा रहे हैं, जो जनता वहां रहती है, उनको मालूम है। क्योंकि जगदीश प्रधान जी हमेशा कहते हैं, ''मेरे यहां पर स्कूलों की दिक्कत है।'' सबसे बड़ा विषय वहीं है लेकिन हमने चुपचाप खोल दिए। हमने इस पर चर्चा नहीं करी। चर्चा तो आज ही उसको तो हम कल भी प्रमोट कर लेंगे, परसों कर लेंगे। हमारे स्कूल्स में बच्चे जा रहे हैं। बच्चों को पता है, शिक्षा कैसे बढ़ी है। लेकिन आज हम चर्चा कर रहे हैं मैट्रो के ऊपर! क्योंकि दिल्ली की जनता से जुड़ा हुआ मुद्दा है। आप बढ़ाए जाओ। आपको इस बात को समझना चाहिए, आपकी पार्टी के लिए नुकसानदायक है। मैंने तो नोटबंदी के टाइम पर भी कहा था कि आप अपने घमंड के अन्दर अपनी बीजेपी को ही खत्म करने जा रहे हो। आप करते क्या हो? जीएसटी लगाओ, नोटबंदी कराओ। पब्लिक को तंग करोगे, पब्लिक आपको जवाब दे देगी जितने आप बढ़ाए जा रहे हो। अच्छा, एक हिसाब मेरी समझ में आ रहा था कि 32 कि.मी. के इन्होंने अब 60 रूपये कर दिए हैं तो बुलेट ट्रेन तो कई सौ कि.मी. चलेगी इस प्रापोशन में चलोगे तो 25—30 हजार की

टिकट हो रही है आज ही, अभी तो चली भी नहीं है तो ऐसा तो हो नहीं सकता कि बुलेट ट्रेन सस्ती हो मैट्रो से कुछ प्रोपोर्शन में तो रेट होगा और वो तो बहुत स्पीड में भी चलेगी। तो ये बुलेट ट्रेन के सपने, इस तरीके के सपने कोई किसी का कोई हिसाब नहीं देना, बस हर चीज में एक ही जवाब देना, रेट बढ़ा दो, पैसे दे दो, कोई हिसाब–किताब नहीं देंगे। कुछ इनकी बात हमारी समझ में तो आती नहीं है और शायद इनको भी समझ में आ रही है। जैसे मैंने शुरूआत में कहा कि आज इनको भी मालूम है कि बहुत दिक्कत हो रही है और इंडिया इस किस्म की प्राइम सेंसिटिव मार्किट है, हम सभी जानते हैं कि जरा सा अगर राजस्व को थोड़ा बहुत भी उपर नीचे कर दें तो डिमांड पर बहुत तेजी से असर आता है। जैसे कि मेरे साथियों ने बताया कि जो कम्प्यूटर्स थे, वो बहुत तेजी से कम हो रहे हैं और जिस कलयुग में जिस रावण की, जिस भस्मासुर की हम बात करते हैं, वो है तो पॉलूशन ही है। कोई अगर हमें सबको लीलने वाला कहला के अगर खत्म करने वाला है, कोई हमें आकर कल कोई और नहीं कर सकता। कोई धर्म–वर्म किसी को खत्म नहीं कर रहा, जो ये गलतियां फैलाते रहते हैं कोई देश किसी को खत्म नहीं कर सकता, कुछ खत्म नहीं होता। लेकिन ये पाल्यूशन है जो पूरी दुनिया को लील रहा है। चाहे वो अमेरिका के अन्दर इतने तूफान आ रहे हों, चाहे वो कहीं पर भूकंप आ रहे हो कहीं धरती फट रही हो, चाहे पॉलूशन से दिल्ली में बुरी पॉजिशन हो। सारी चीजें बेकार हो सकती हैं, रिकवर हो सकती हैं, दोबारा से लाई जा सकती हैं लेकिन जो पॉल्यूशन इस तरीके से बढ़ रहा है, जिस तरीके से हमारे बच्चों को, बुजुर्गों को सांस लेने में तकलीफें हो रही है। इस बात को समझें कि ये जो पब्लिक ट्रांसपोर्ट है, ये पैसे कमाने का माध्यम नहीं है, ये जनता को उनकी आदतों से अपने पर्सनल व्हीकल को छोड़कर पब्लिक ट्रांसपोर्ट को यूज करने का तरीका और जितनी डेवलप्ड कंट्रीज हैं, इस

दुनिया के अन्दर जहां पर गाड़ी लेना बहुत आसान है, जहां पर फॉसलफ्यूल बहुत सस्ते हैं, जहां टैक्सिज बहुत कम है, वहां पर लोग पब्लिक ट्रांसपोर्ट को यूज करते हैं क्योंकि ये उनकी पढ़ाई लिखाई का सूचक है और इसलिए वो बहुत सस्ते बनाए गए हैं वहां पर।

अध्यक्ष महोदय, मेरा इनसे हाथ जोड़कर अनुरोध है, मैं अपनी आखिरी बात यही कह रहा हूं कि ये सारी बातें क्यों समझ रहे हैं, इसको किसी भी तरीके से अब इन्होंने बढ़ा तो लिया है, जो ये कह रहे हैं लेकिन इसका पुरजोर विरोध ये भी करें, हम तो करेंगे ही और लगातार करते रहेंगे। दिवाली के ऊपर जो आपने, हमने तो स्कूलों का तोहफा दिया और जो आपने तोहफा दिया है बहन–बेटियों को कि भैया दूज पर जाओगी तो ये हालत हो जाएगी, स्कूटर के ऊपर चार बच्चे लाद लेना खुद अपने साथ में बैठ जाना और बहुत परेशानी होने वाली है। मैं इनसे हाथ जोड़कर निवेदन करता हूं कि इसको हो सके तो ये वापस लें, हमारा साथ दें, बहुत–बहुत धन्यवाद।

अध्यक्ष महोदयः धन्यवाद। श्री आदर्श शास्त्री जी।

श्री आदर्श शास्त्रीः बहुत बहुत धन्यवाद, अध्यक्ष महोदय। दिल्ली मैट्रो के जो फेयर आज बढ़े हैं, इसके ऊपर इस चर्चा में भाग लेने का अवसर देने के लिए।

अध्यक्ष महोदय दिल्ली मैट्रो की सोच की शुरूआत 1970 में हुई और 1998 में काम शुरू हुआ 2004 में चलना शुरू हुई, ये हम सब जानते हैं। कुछ लगभग 200 किलोमीटर की मैट्रो इस समय दिल्ली में चल रही है। 27–28 लाख लोग इसपे रोज सफर करते हैं। ये दुनिया में आज की तारीख में लगभग 12वीं सबसे बड़ा मैट्रो नेटवर्क बन चुका है। लोगों की जो राइडरशिप है जो लोग इसपे सवार होते हैं, उसमें ये 14 नम्बर पर था

और पिछले कुछ दो तीन महीनों से 15 नम्बर पे आ गया। अगर इसकी फेज–थ्री की जो बात करते हैं, उसको पूरा कर लेंगे तो ये दुनिया में टॉप टेन मैट्रो नेटवर्क्स में से एक बन जाएगी। ये बात साफ दर्शाती है कि ये मैट्रो नेटवर्क इस सोच से बनाई गई थी कि दिल्ली की जो आबादी है, आज दुनिया के चार सबसे बड़े शहरों में से एक की आबादी है। जो लगभग पौने दो करोड़ की आबादी दिल्ली की है, एनसीआर की ले लें तो लगभग जो ढाई करोड़ की आबादी है, उसके लिए एक आसान सब्सिडाइज्ड, एफिशिएंट ट्रांसपोर्ट का एक विकल्प सामने आएगा जिससे कई बातों के लिए, कई समस्याओं की रूकावट होगी। ट्रेफिक की समस्या कम होगी, रोड सेफ्टी बढ़ेगी, प्रदूषण कम होगा, ये सारी बातों को देखा गया और उस पारदर्शिता के साथ मैट्रो का काम चल रहा है। अभी 50–50 परसेंट ऑनरशिप दिल्ली सरकार की, केन्द्र सरकार की है तो ऑनरशिप और इसकी प्लानिंग में जो दिल्ली सरकार की भागीदारी आधी है, मगर ये बात समझ नहीं आती है कि ऐसा क्या फॉर्मुला लगा रखा है कि जहां पे दिल्ली की जनता के बारे में, उनकी सहूलियत के बारे में सोचना हो, उसमें दिल्ली सरकार की भागीदारी 50 परसेंट से घटा के जीरो कर दी जाती। केन्द्र सरकार इसपे निर्णय लेती है। एक साल के अन्दर दो बार इसका किराया बढ़ाया गया। कहां सात और आठ वर्ष पहले किराया नहीं बढ़ा और इसकी जिम्मेदारी, जवाबदेही, केन्द्र सरकार की 50 परसेंट की भागीदारी के नाते होती है जिसको बड़े आराम से दरकिनार कर रही है। ये ही उदाहरण अगर मैं बिजली में डीईआरसी का दूं। हमारे सामने विपक्ष के हमारे माननीय साथी बैठे हैं। कल अगर डीईआरसी के माध्यम से बिजली के दाम बढ़ जाए तो ये सब सड़क पे उतर आएंगे, हाहाकार मचाएंगे कि बिजली के दाम बढ़ा दिए और ये अरविंद केजरीवाल जी की सरकार है जो आज 29 प्रदेशों में दिल्ली अकेला प्रदेश रह गया है, जहां बिजली के दाम पिछले ढाई साल नहीं बढ़े।

भारतीय जनता पार्टी के प्रांतों में इस चुनाव के बाद उत्तराखंड, उत्तर प्रदेश में दोनों जगह आठ परसेंट और 11 परसेंट बिजली के दाम बढ़ चुके। तो सोचने वाली बात ये है कि जहां पे इनको नहीं समझ आता, वहां पे ये कानून रूल की बात करने लगते हैं और जहां पे इन लोगों को दिल्ली की जनता के साथ खड़े होना चाहिए, वहां पे इनके पास किसी भी बात का जवाब नहीं है। लोकतांत्रिकरण डेमोक्रेटाइजेशन बहुत जरूरी है। किसी भी ट्रांसपोर्ट सिस्टम का उदाहरण दूसरे खेमे में अगर आप देखें हवाई जहाज का भी ले लें तो हवाई जहाज के भी किराए बहुत मंहगे हुआ करते थे मगर जब लोकतांत्रिकरण हुआ, डेमोक्रेटाइजेशन हुआ तो आज दिल्ली से बम्बई भी दो हजार रुपये के किराए में हवाई जहाज में सफर किया जा सकता है। अर्थशास्त्र इस बात की गवाही देता है, इतिहास इस बात की गवाही देता है कि जहां पे भी आप सप्लाई, जहां पे भी आप डिमांड के लिए काम करेंगे, जहां पे भी आप ये कोशिश करेंगे कि ज्यादा से ज्यादा लोग किसी भी सर्विस का इस्तेमाल करें, वहां पे उसके दाम कम हो जाएंगे। चाहे वो हवाई जहाज का किराया हो, चाहे रेल का किराया हो, चाहे वो मैट्रो का किराया हो, बस का किराया हो और जहां पे भी आप किसी चीज के दाम को बढ़ाने की कोशिश करेंगे लोग उस सिस्टम को छोड़ते जाएंगे और दूसरे विकल्प खोजेंगे, जो मंहगे भी होंगे और समाज के लिए वातावरण के लिए खराब भी हो सकते हैं। इसमें सच्चाई ये है कि कई सवाल उठ के आते हैं यहां पे तीन हजार करोड़ की बात की गई। मुख्यमंत्री जी ने बोला के 15 सौ करोड़ की जिम्मेदारी हम देने को तैयार हैं केन्द्र सरकार अपनी दे। उसमें तो जवाब आ नहीं रहा मगर वहीं दिल्ली मैट्रो के साथ जब रिलायंस कम्पनी ने एयरपोर्ट एक्सप्रेस बनाई तो केन्द्र सरकार ने फटकार कर डीएमआरसी को बोल दिया कि 29 सौ 30 करोड़, 29 सौ 50 करोड़, 2 हजार 9 सौ 50 करोड़ रिलायंस को जमा कर दो। ये कहां का न्याय

है! एयरपोर्ट एक्सप्रेस जो रिलायंस ने बनाई, उसके लिए डीएमआरसी 2950 करोड़ रुपये जमा कर दे रिलायंस की लॉस की भरपाई करने के लिए। मगर दिल्ली की जनता की सुनवाई दिल्ली की जनता के लिए कोई न सोचे।

अध्यक्ष महोदय, ये पारदर्शिता की बहुत ज्यादा जरूरत है डीएमआरसी के काम करने के तरीके साथ। मैं डीएमआरसी की बैलेंस शीट देख रहा था, कई चीजे हैं उसमें, समझ नहीं आ रही डीएमआरसी को इस बात का जवाब देना चाहिए, उस बारे में सोचना चाहिए।

मैं छोटा सा उदाहरण दूंगा 2013–14, 2015–16 का मैं लॉस देख रहा था। ऑपरेशनल लॉस जो डीएमआरसी ने दिखाया है, सात करोड़ से साठ। 2013 ये 2014 में लगभग नौ गुना बढ़ गया। 60 करोड़ से 270 करोड़ 2015 में हो गया और 2016 में 270 करोड़ से 470 करोड़ हो गया। तो कोई तो मापदंड होगा, कोई तरीका होगा, कोई लॉजिक होगा। मैट्रो का नेटवर्क फेज– थ्री अभी पूरा नहीं हुआ, चालू नहीं हुआ। जो फेज–एक, फेज–2 चल रहा है, लगभग 170 किलोमीटर, उसमें ऐसा क्या हो रहा है जिसकी वजह से लॉस पिछले तीन सालों में 60 करोड़ से बढ़कर 470 करोड़ हो गया! इसकी जवाबदेही डीएमआरसी को देनी चाहिए। कई ऐसी बाते हैं जो डीएमआरसी के कहीं भी कागजों से साफ नहीं होती। डीएमआरसी के लगभग आज 200 से ऊपर के स्टेशन हैं, वो प्रोपर्टी है, एसेट है, वो बैलेंसशीट में कहां रिफ्लेक्ट कर रहा है, कई जो रेवेन्यू एडवर्टाइजमेंट्स ये आने चाहिए। दिल्ली मैट्रो ने 2009 में और 2011 में स्टेशनों पर ऑक्शन करने की बात करी थी; छोटी छोटी दुकानें। उनके बारे में क्या हुआ? 2010 में रिपोर्ट आई कि दुकानों को जो ऑक्शन हुआ, वो दुकाने न चलने की वजह से बंद कर दी गई। जहां पे 27 लाख लोग रोज चलते हैं दिल्ली मैट्रो के स्टेशनों पर और ऐसा क्या कारण हुआ कि वहां पे दुकाने नहीं

चलेंगी! आज उन मैट्रो के स्टेशन नीचे अगल बगल तो बहुत कुछ चलता है, दुकान चलती है। तो स्टेशन पे दुकान क्यों नहीं चली, इन सब सवालों का जवाब पूछा जाना चाहिए।

अध्यक्ष महोदय, दिल्ली मैट्रो को सबसे ज्यादा गाइडेंस दी थी हांगकांग मैट्रो ने। हांगकांग मैट्रो की गाइडेंस और प्लानिंग के बेस पे डीपीआर बनी 2002 में, 2001 में। जिसके माध्यम से दिल्ली मैट्रो काम करना शुरू करी। हांगकांग मैट्रो पर्चेजिंग पावर पैरिटी पे ये एनसीआर की रिपोर्ट है। एनसीआर की रिपोर्ट के मुताबिक हांगकांग मैट्रो जिसके गाइड लाइन्स पे दिल्ली मैट्रो बनी। आज वहां पे न केवल प्रॉफिटेब्ल है, पर्चेजिंग पावर पैरिटी में विश्व में दूसरे नम्बर पे सबसे सस्ती मैट्रो सर्विस है। यहां तक की हांगकांग एयरपोर्ट से हांगकांग शहर आने के लिए टैक्सी की जो लाइन होती है, टैक्सी की जो गाड़ियां होती हैं, उनको कानूनन उसमें एक ये नया कानून लाया गया जिससे उसको बोला गया कि टैक्सी को भी एयरपोर्ट पे खड़ा होना पड़ेगा क्योंकि मैट्रो के बाद टैक्सी वाले एयरपोर्ट पे खड़े होने को तैयार नहीं थे और एक यहां दिल्ली है, यहां उबर, ओला और बाकी टैक्सी की हम बात करते हैं।

कई ऐसे उदाहरण हैं। बड़े मैट्रो नेटवर्क ले लीजिए, चाहे लंदन का ले लीजिए लगभग पौने 4 सौ किलोमीटर का नेटवर्क है और जहां पे एक पाउंड उनका, हमारे 90 रु0 के बराबर है। पर्चेजिंग पॉवर पैरिटी में तीसरे नम्बर पे, सबसे सस्ती मैट्रो है दुनिया की। छोटी मैट्रो का नेटवर्क का एक्जाम्पल ले लीजिए, बैंकॉक का ले लीजिए। लगभग 70 किलोमीटर की मैट्रो है। केवल 70 किलोमिटर पर्चेजिंग पावर पैरिटी, पीपीपी में पांचवें नम्बर पे सबसे सस्ती मैट्रो है। तो ऐसा क्या कारण है, दुनिया भर में उदाहरण हैं बड़े और छोटे, हांगकांग मैट्रो जिससे हमने सीख के मैट्रो बनाई। जहां

पर परचेजिंग पावर पैरिटी में टिकट उनके हमसे सस्ते हैं। हमसे बड़ा नेटवर्क चला रहे हैं। हमसे ज्यादा स्टेशन है। हर स्टेशन से रेवेन्यू आ रहा है। हर स्टेशन से किराया आ रहा है। दुकानों का किराया आ रहा है, एडवर्टाइजिंग का किराया आ रहा है। कोई उसका जवाब नहीं। हम यहां पर काम कर रहे हैं। दिल्ली सरकार ने 6000 कमरे बनाए। राजेश भाई ने ठीक बोला। उसके बारे में प्रचार तो हम बाद में कर लेंगे। मैंने कल के दैनिक जागरण में फोटो देखी प्रधानमंत्री जी की। बराद नगर में जिस स्कूल में थे, उसकी। बड़ा अचम्भा हुआ देखके कि 15 साल मुख्यमंत्री रहे गुजरात के। स्कूल में जिसमें गये, बच्चे दरी पर बैठके पढ़ रहे थे और ब्लैकबोर्ड जमीन पर पड़ा हुआ था। दिल्ली सरकार में ढ़ाई साल में आज 6000 क्लास रूम हमने बनाके खड़े कर दिये!

अन्त में, अध्यक्ष जी, आपसे मेरा निवेदन है। मैं एक डिमान्ड रखना चाहता हूं आपके माध्यम से कि दिल्ली विधान सभा की एक ओवरसाइट कमेटी बनाई जाए और ओवरसाइट कमेटी को ये ताकत दी जाए कि डीएमआरसी को बुलाकर पूछा जाए कि किस तरह से ये फेयर फिक्सेसन होता है किस तरह से रेवेन्यू की इनकी क्या प्लानिंग है, किस तरह से ये लोग आगे सोच रहे हैं, एडवरटाईजिंग का रेवेन्यू निकालने का, स्टेशन पर दुकान बनाने का? कई इस तरह की बातें हैं जिसका जवाब डीएमआरसी को देना चाहिए और मैं उम्मीद करता हूं कि आप एक ओवरसाइट कमेटी का गठन करेंगे जिससे डीएमआरसी के बारे में ज्यादा जानकारी दिल्ली के निवासियों तक जा सकें, बहुत–बहुत धन्यवाद।

अध्यक्ष महोदयः श्री मनजिंदर सिंह सिरसा जी।

श्री मनजिंदर सिह सिरसाः ... (व्यवधान)

श्री राजेश गुप्ताः उसे भी सदन के पटल पर रखा जाए। हम देखना चाहेंगे कि उसमें क्या–क्या धांधली हुई है।

अध्यक्ष महोदयः सिरसा जी।

श्री मनजिंदर सिंह सिरसाः आ रही आवाज?

अध्यक्ष महोदयः नहीं, आ रही है आवाज। आ रही है। भई त्रिपाठी जी प्लीज। इस विषय को गम्भीर रहने दीजिए, थोड़ा सा प्लीज। माननीय सदस्य सोमनाथ जी, प्लीज। अकाली दल से चुनके आये हैं बैठिए।

श्री मनजिंदर सिंह सिरसाः अध्यक्ष जी, मेरी बड़ी चिन्ता है इनको।

अध्यक्ष महोदयः आपसे बड़ा प्रेम है, दोस्ती है।

श्री मनजिंदर सिंह सिरसाः अध्यक्ष जी, ये पिछले दस दिन पहले ये शुरूआत हुई।

अध्यक्ष महोदयः भई त्रिपाठी जी, ये बात ठीक नहीं है।

श्री मनजिंदर सिंह सिरसाः अध्यक्ष जी, धन्यवाद। इस माईक में आवाज आ रही है और मेरे को खुशी है कि आज मेरे दोस्तों ने कम से कम ये तो माना कि मेरी आवाज वहां तक नहीं पहुंचती है।

अध्यक्ष महोदयः ये माईक, हंसी में लेना जरा वैसे नहीं, डेढ़ साल बाद इस्तेमाल हो रहा है।

श्री मनजिंदर सिंह सिरसाः अध्यक्ष जी, दस दिन पहले से ये सारा घटनाक्रम शुरू हुआ कि मैट्रो का रेट बढ़ रहा है और अखबारों में जब ये विषय उठा तो सत्ता पक्ष के लोगों की नींद खुली। बड़ा अफसोस है दिल्ली के मैट्रो का किराया बढ़ना। मतलब कई लाखों लोगों का आर्थिक तौर पर

नुकसान होना। जो अपना घर संचालन करने के लिए जो पैसे का इस्तेमाल करते थे, आज उनको वो पैसा मैट्रो के भाड़े के रूप में ज्यादा देना पड़ रहा है। सबसे ज्यादा इसके अन्दर स्टूडेन्टस का नुकसान हो रहा है और औरतों का सबसे ज्यादा, हमारी मां–बहनों को जो घर चलाने के लिए पैसा रखती थी, आज उस पर अपना पैसा इस परपज के लिए खर्च करना पड़ रहा है। बड़ा अफसोस है कि दिल्ली के अन्दर जो सरकार है। ये सरकार की सबसे बड़ी अब तक की नाकामी है ढाई साल में। सरकार ने बहुत संयोजित तरीके से सब कुछ किया। पहले तो मुख्यमंत्री ने इसके उपर बयान दागा और इसके पीछे की मंशा अब समझ में आने लगी। जब हमारे दोस्तों ने उस कम्पनियों का नाम लेना शुरू किया तो समझ में आने लगा कि इसके पीछे क्या–क्या चल रहा था। आज समझ में आया की ढ़ाई साल से क्यों मैट्रो के फोर्थ फेज को रोका गया था। आज वो भी इन्टेन्शन सामने आने लग पड़ी।

अध्यक्ष जी, ये जो सब लोग बोल रहे है मैं इनकी सीरियसनेस आपको बताना चाहता हूं। 66 एमएलए हैं आम आदमी पार्टी के। आधा घण्टा कोरम नहीं पूरा हो सका इसके अन्दर। ये सीरियसनेस है, हमारे आम आदमी पार्टी की और उसके बाद दूसरी बार फिर से कोरम पूरा नहीं हुआ। न एम.एल. ए., न मंत्री, न उपमुख्यमंत्री, न मुख्यमंत्री। ये सीरियसनेस है दिल्ली के लोगों के प्रति इनकी। ये जवाबदेही है इनकी! और माफ करना मैं कहना नहीं चाहता था लेकिन क्योंकि अब मुझे ये विवश किया, खाने की लाईन में लाईन टूट नहीं रही थी वहां पे। वहां की चिन्ता है खाना खाने की, लेकिन दिल्ली के लोगों के काम की चिन्ता! इतनी सीरियसनेस है। दो–दो बार आपको ये घण्टी बन्द करनी पड़ी। दो–दो बार घण्टी बन्द करनी पड़ी। अध्यक्ष जी, यहां पर दिल्ली के लोगों की चिन्ता नहीं की जाती। यहां पर भाषण दिया

जाता है। मेरे मित्र ऋतुराज जी ने चाहे बोलते हुए कह दिया लेकिन कहा कि मैं भाषण दे रहा था और मेरे भाषण को रोक दिया गया। यहां पर भाषण दिया जाता है, दिल्ली के लोगों की चिन्ता नहीं की जाती। यहां पर अपने वोटरों को एड्रेस करने का काम किया जाता है ताकि भाषण देकर भाषणबाजी इस विधान सभा के अन्दर एक नया ट्रेन्ड शुरू हो गया जो पहले कभी आज की तीस साल में विद्यमान नहीं था।

... (व्यवधान)

अध्यक्ष महोदयः अजय दत्त जी, त्रिपाठी जी। अजय दत्त जी, बैठिए प्लीज। बैठ जाइए।

श्री मनजिंदर सिंह सिरसाः ये अमित शाह जी के ऊपर बोले। ये किस–किस विषय पर बोले, पर मैंने इनका इतराज नहीं उठाया। क्योंकि इनकी सच्चाई अब खुलने लग पड़ी। इनके पोतड़े खुलने लग पड़े। इनको डर लगने लग पड़ा। इनको डर लगने लग पड़ा। जब इनके पोतड़े खुलेंगे, अभी और खुलेंगे। अभी तो शुरूआत हुई है।

अध्यक्ष जी, मैं आपके माध्यम से बताना चाहता हूं, मैट्रो का रेट बढ़ाने का, मैट्रो का फेयर बढ़ाने का जो आपने खुद यहां पर एडमिट किया। तीन चीजें, हमारे मेम्बर साहिबानों ने जाने–अनजाने में अपने मुंह से एडमिट किया। पहली बात ये जो फेयर फिक्सेसन कमेटी थी इसकी रिपोर्ट तो आठ मई को मीटिंग भी हो चुकी थी और ये तय भी हो गया था कि रेट फिक्स हो रहे हैं और 10 मई से लागू भी करने थे। क्या कारण रहा इनके नॉमिनी ने जाके चीफ सेक्रेटरी के रूप मे किसने किसके कहने पर ओला और उबर को बेनफिट देने के लिए इनका नॉमिनी जाके वहां रेट बढ़वाता है, बन्द कमरे में। बन्द कमरे में तो रेट बढ़वाये जाते हैं। बाहर में आकर अखबारों

में ये बाद में दिया जाता है, चार महीने बाद, तब नहीं। तब नहीं बोला कोई भी। क्योंकि उबर और ओला से तय हो चुका था पैसा लेन देन। ये पैसे का लेन देन तय हो चुका था और इसी पैसे के लेन देन के चलते तीन महीने बाद भी, छः महीने बाद दिल्ली की सरकार की आंख खुलती है। छः महीने बाद! मुख्यमंत्री जी की आंख कब खुलती है, दिल्ली सरकार की आंख छः महीने बाद। कब खुलती है, जब अखबार में छपता है।

अध्यक्ष जी, चीफ सेक्रेटरी इनका वहां पर नॉमिनी था, फेयर फिक्सेसन कमेटी में। उसने एतराज नहीं उठाया। अब बोलते हैं कि हमारे कल चार मेम्बर गये थे। उन्होंने एतराज उठाया। मैं पूछना चाहता हूं अध्यक्ष जी, आपके माध्यम से मैं पूछना चाहता हूं सरकार के लोगों से कि अगर यही एतराज आपने छः महीने पहले वाली मीटिंग में उठाया था, अगर यही ऐतराज आपने किया होता, आज ये दिल्ली के लोगों को ये भुगतान न भुगतना पड़ता जो आपके कारण भुगतना पड़ रहा है।

... (व्यवधान)

श्री मनजिंदर सिंह सिरसाः अध्यक्ष जी, मैं बैठ जाता हूं।

... (व्यवधान)

अध्यक्ष महोदयः अजय जी प्लीज। आप बोलिए, बोलिए। प्लीज राजेश जी।

... (व्यवधान)

अध्यक्ष महोदयः राजेश जी, प्लीज। त्रिपाठी जी।

श्री मनजिंदर सिंह सिरसाः अध्यक्ष जी, मैं आपको याद दिलाना चाहता हूं। जब दिल्ली में श्रीमती शीला दीक्षित जी की सरकार थी। एक औरत

को कैसे संबोधित किया जाता है, मैं केजरीवाल जी से नहीं पूछूंगा। एक औरत को इसी तरह संबोधित किया जाता है, जैसे मैं कर रहा हूं। एक मां को इसी तरह सम्बोधित किया जाता है, जैसे मैं कर रहा हूं। न कि जैसे मुख्यमंत्री करते है, वैसे सम्बोधित किया जाता है। जब माननीय श्रीमती शीला दीक्षित जी दिल्ली की मुख्यमंत्री थीं, जब दिल्ली की मुख्यमंत्री शीला दीक्षित जी थीं। अध्यक्ष जी, तीन सौ करोड़ रूपया प्राईवेट कम्पनी को दिया जाता था बिजली के सब्सिडी के रूप में। तब यह कहा गया कि ये प्राइवेट कंपनियों को पैसा लूटाया जा रहा है। इतने बड़े कागज रखकर, दस्तावेज रखकर तब यह कहा जाता था कि देखिये, यह लूट हो रही है, हम इस लूट को रोकेंगे। अध्यक्ष जी, अब चार हजार करोड़ रुपया, वही रिलायंस जिसका ये नाम ले रहे थे ना, उसी रिलायंस की, मैं बताने जा रहा हूं, चार हजार करोड़ रुपया दिया जा रहा है और क्यों दिया जा रहा है, किसके कहने पर दिया जा रहा है। अरे! आपने तो दिल्ली की सत्ता यही कहकर ली थी....

... (व्यवधान)

श्री मनजिंदर सिंह सिरसाः आप उनका जवाब देंगे, आप दे दीजिए।

अध्यक्ष महोदयः चलिये, आप बोलिये, जो बोलना चाह रहे हैं, बोलिये।

श्री मनजिंदर सिंह सिरसाः चार हजार करोड़ रुपया उसी रिलायंस की कम्पनी को दिया जा रहा है, उसमें कितना पैसा इनको मिलेगा, ये बताएंगे।

... (व्यवधान)

अध्यक्ष महोदयः राजेश जी, प्लीज। वो उत्तर देंगे।

श्री मनजिंदर सिंह सिरसाः चार हजार करोड़ रुपया! अध्यक्ष जी, जब यह फिफ्टी—फिफ्टी की पार्टनरशिप में दिल्ली मैट्रो की स्थापना हुई थी ना, यह तभी तय किया गया था कि दिल्ली के लोगों के हित के लिए इसके जो एक्सपेंसेज होंगे, जो लॉसेस होंगे, जो इसके मेंटनेंस के चार्जेज होंगे, वो दिल्ली की सरकार अपने आप देखेगी, क्यों देखेगी, उसके ऊपर बियर होंगे, क्यों? क्योंकि दिल्ली के लोगों से ज्यादा किराया न लिया जाए, दिल्ली की सरकार इसकी चिंता करेगी। इसीलिए यह लॉसेस की जिम्मेवारी एक्ट के अंदर है, दिल्ली सरकार के पास थी। जब आपने फोर्थ फेज का काम रुकवाया, ढ़ाई साल तक, यह अब तक के रिकार्ड में है देश के रिकार्ड में है, ढाई साल तक काम रोका गया, क्यों रोका गया? क्योंकि प्राइवेट कम्पनियों से हाथ मिलाया गया था कि आपका व्यापार हम चालू कराएंगे। यह ओला और उबर से जो हाथ मिलाया गया था, इसके कारण ढ़ाई साल रिकार्ड में नहीं है। अध्यक्ष जी, अगर किसी के रिकार्ड में गूगल करें, यह गूगल करने का बहुत शौक रखते हैं, मुझे भी गूगल करके बताएं, कब हुआ? ढाई साल तक किसी प्रोजेक्ट को रोक कर रखा गया केवल इस मकसद से दिल्ली के लोगों के साथ सबसे बड़ा अत्याचार, अन्याय किया इस सरकार ने। अध्यक्ष जी, यह ऐसी सरकार है, बड़ी हँसी आती है, यह कहते हैं अब हम मैट्रो भी चलाएंगे, जिन लोगों से डीटीसी नहीं चलती, 1600 करोड़ रुपया ग्रांट इन एड दे रहे हैं, जिन टूटी बसों में कोई चढ़ना पसंद नहीं करता उनके लिए 1600 करोड़ रुपया कितने बड़े घपले के रूप में, कहां—कहां जा रहा है, जरा इसका हिसाब भी इस पटल पर लेकर आएंगे एक दिन आप? देंगे जवाब दिल्ली के लोगों को? नहीं दे पाएंगे। आप मत देना, इनको देने का मौका देना।

अध्यक्ष जी, अभी यह कहा जा रहा था, मुझे बहुत अफसोस हो रहा

है जब उस मां को देखता हूं, इन्होंने जिसकी बात की है कि 10 रुपये थे बेचारी की जेब में, 20 रुपये नहीं थे। उसको लाइन से बाहर हटना पड़ा। तब वो सोच रही होगी कि क्यों मैंने इस आम आदमी पार्टी को वोट दी, जो मेरे आज दस रुपये भी खा गए। मुझ गरीब को मैट्रो में चढ़ने से सरकार ने रोक दिया, आज वो रो रही होगी, मैं उस मां के आंसुओं को महसूस कर सकता हूं।

... (व्यवधान)

अध्यक्ष महोदयः एक सैकेंड।

श्री मनजिंदर सिंह सिरसाः अध्यक्ष जी, आप मत जवाब दीजिए, इनको देने दीजिए।

अध्यक्ष महोदयः पब्लिक सुन रही है सब। चलिये, आप बोलिये।

श्री मनजिंदर सिंह सिरसाः अध्यक्ष जी, ये इन्होंने बहुत अच्छी–अच्छी बातें कहीं। मेरे भाइयों ने कहा कि मैट्रो जो है, वो रिएल एस्टेट से अपने रेवेन्यू क्यों नहीं जनरेट कर रही। बहुत अच्छी बात कही। मैं कद्र करता हूँ इनकी भावना की, इनको समझ है काम की। पर मुझे अफसोस इस बात का है इनके मुख्यमंत्री को समझ नहीं है, जिसने ऐसे आदमी को एक्सटेंशन दी जो रेवेन्यू नहीं जनरेट कर पा रहा था। क्या मजबूरी थी उसको एक्सटेंशन देने की? किस कारण से आपने एक्सटेंशन दी? 50 परसेंट के भागीदार थे, क्या आपने ढ़ाई साल में कभी इस बात का संज्ञान लिया कि यह पैसा कहां से आएगा, यह पैसा कौन जनरेट करेगा और इसमें हमारी जिम्मेवारी है। दिल्ली के लोग हमारी इस मैट्रो में सफर करते हैं। आज तक दिल्ली की सरकार चुप रही, आज यह झूठ बोलते हैं। आज यह वही मैट्रो है जिसके 50 परसेंट के भागीदार वो हैं और कल जिन मैम्बर्स ने

मीटिंग में मुद्दा उठाया, मैं पूछना चाहता हूं जब ये पिछली मीटिंग में चार मैम्बर गए थे, क्या अरविंद केजरीवाल जी ने तब इनके मुंह में फेविकोल डाल भेजा था इनको? ये तब क्यों नहीं बोले? इनको कल बोलना याद आ गया। ये पहले क्यों नहीं बोले, क्यों? क्योंकि मंशा यह थी अरविंद केजरीवाल की तरफ से बंद कमरे में जाकर रेट बढ़वा दो, बाहर आकर मैं चिल्लाना शुरू कर दूंगा। बहुत सुनियोजित है। मैं मानता हूं इनकी इस कला का कोई मुकाबला नहीं कर सकता, कोई सानी नहीं है इस कला का उनकी, यह कला अगर किसी में है तो मैं दाद देता हूं। अरविंद केजरीवाल जी के अलावा यह कला किसी में नहीं है।

अध्यक्ष जी, मैं अगली बात... अभी माननीय मंत्री सत्येंद्र जैन जी ने कहा, अरे भइया, हमें विपक्ष का तो बोलने दो। आज भी नहीं बोलने दे रहे। सच बोल रहे हैं तो आपको तकलीफ हो रही है। सत्येंद्र जैन जी ने बहुत अच्छी बात कही, ये काबिल मंत्री हैं इस मामले में, बात बताने के मामले मे। बोले, अरविंद केजरीवाल जी ने एयरपोर्ट मैट्रो का दाम कम कर दिया। ओह! ओह! ओह! दाम कम कर दिया! अरे, मेरे भाई एयरपोर्ट मैट्रो पर तो रईस जाते हैं। यह दिल्ली मैट्रो का रेट क्यों नहीं अरविंद केजरीवाल जी ने कम किया, सत्येन्द्र जैन जी, यह भी बता दो। जिस एयरपोट मैट्रो का रेट अगर अरविंद केजरीवाल जी ने कम किया, मैं उस अरविंद केजरीवाल जी से पूछना चाहता हूं, सत्येन्द्र जैन जी के माध्यम से पूछना चाहता हूं। सत्येन्द्र जैन जी क्यों नहीं, उस अरविंद केजरीवाल जी क्यों.... क्योंकि मन में बेईमानी थी ओला और उबर को पैसा पहुंचाने की बेईमानी थी, इसलिए उस अरविंद केजरीवाल ने दाम कम नहीं किया। शेम करनी चाहिए। अध्यक्ष जी, आपने बोलने का मौका दिया...

... (व्यवधान)

अध्यक्ष महोदयः पूरा हो गया आपका। सिरसा जी, अब कन्क्लूड करिये।

श्री मनजिंदर सिंह सिरसाः अध्यक्ष जी, मैं कन्क्लूड कर रहा हूं।

अध्यक्ष महोदयः पूरा हो गया।

श्री मनजिंदर सिंह सिरसाः अध्यक्ष जी, अंत में अपनी दो बातें कहकर अपनी बात को समाप्त करूंगा। आप यह देखिये, इनका फेयर फिक्सेशन कमेटी के अंदर जो मैम्बर जाता है, वो आकर अपनी रिपोर्ट देता है। अभी तक किसी ने यह चर्चा नहीं की, वो रिपोर्ट चीफ सेक्रेटरी की ऑफिशियल रिपोर्ट की कॉपी यहां पर प्रोवाइड की जाए। मैंने अनऑफिशियल कॉपी ली है, मैं आपके पटल पर वो भी रखवाना चाहूंगा, आपको रिपोर्ट देता है, अरविंद केजरीवाल जी को रिपोर्ट दी जाती है चीफ सेक्रेटरी द्वारा कि यह मीटिंग के अंदर फेयर फिक्सेशन कमेटी ने किया है। तो अरविंद केजरीवाल जी चुप क्यों रहें। छः महीने तक उस रिपोर्ट को दबा कर रखा गया, जो चीफ सेक्रेटरी ने अरविंद केजरीवाल जी को दी थी। दिल्ली के तीस लाख लोगों के साथ इससे बड़ा धोखा नहीं हो सकता। आपको पॉलिटिकल स्टेटमेंट देने के लिए तो अखबार और यह मंच रहता है लेकिन ईमानदारी दिखाते छः महीने पहले जब वो रिपोर्ट आई थी, उसी दिन चलकर मैट्रो के मिनिस्टर के पास जाते, यूडी मिनिस्टर के पास, केन्द्र सरकार को कहते कि तीन हजार करोड़ रुपया हम देंगे। यह आपका दायित्व है। आप अपने दायित्व से इसलिए भाग रहे हैं तीन हजार करोड़ देने से, आप प्राइवेट कम्पनी को तो चार हजार करोड़ देते हैं, रिलायंस को चार हजार करोड़ देते हैं, वहां से कमीशनें आती हैं दिल्ली मैट्रो से कमीशन नहीं आनी, इसलिए तीन हजार करोड़ देने से आप भाग रहे हैं।

अंत में जो दो सवाल मेरे से पूछे गए, कहा गया कि पैसा कमाने

का तरीका बताएंगे बीजेपी वाले। मैं बताता हूं, पैसा कमाने का तरीका पूछना है तो सत्येन्द्र जैन से पूछो, जिन्होंने कोर्ट में कहा हवाले के पैसे मेरे पास हैं, हाई कोर्ट में कहा। मैं नहीं कह रहा, हाई कोर्ट में सत्येन्द्र जैन ने यह कहा कि हवाले के पैसे मेरे पास आए हैं। इस पैसे को व्हाइट किया जाए। अध्यक्ष जी, ये पैसे की बात करते हैं, हमारी गाड़ियों की बात करते हैं ना, मैं आपको बताना चाहता हूं...

... (व्यवधान)

अध्यक्ष महोदयः सिरसा जी, कन्क्लूड करिये प्लीज।

श्री मनजिंदर सिंह सिरसाः अध्यक्ष जी, मेरे से ज्यादा पैसे सत्येन्द्र जैन के पास हैं, फर्क इतना है उनके पास खर्चने का दम नहीं है क्योंकि बेईमानी के पैसे इनके पास है...

... (व्यवधान)

अध्यक्ष महोदयः कन्क्लूड करिये।

श्री मनजिंदर सिंह सिरसाः हवाले के पैसे हैं, व्यापार करना सीखना है तो इनसे सीखो, ये सामने बैठे हैं।

... (व्यवधान)

अध्यक्ष महोदयः कन्क्लूड करिये।

श्री मनजिंदर सिंह सिरसाः इनके पास हवाले के पैसे हैं, कोर्ट में जाकर कहते हैं मेरे पास हवाले के पैसे है।

... (व्यवधान)

अध्यक्ष महोदयः चलिये, आप कन्क्लूड करिये।

श्री मनजिंदर सिंह सिरसाः अध्यक्ष जी, अंत में एक बात कहना चाहता हूं...

... (व्यवधान)

अध्यक्ष महोदयः हो गया।

श्री मनजिंदर सिंह सिरसाः दिल्ली सरकार....

... (व्यवधान)

अध्यक्ष महोदयः कन्क्लूड करिये, हो गया।

श्री मनजिंदर सिंह सिरसाः कर रहा हूं। अध्यक्ष जी, अंत में मैं एक बात कहना चाहता हूं कि यह रेट नहीं बढ़ने चाहिए। दिल्ली के गरीब लोगों के साथ यह बेइंसाफी होगी। दिल्ली की चुनी हुई सरकार जिन लोगों ने वोट डाले, उनके साथ बेइंसाफी हो रही है। यह धोखा है। सरकार को तीन हजार करोड़ रुपये का ग्रांट इन एड देना चाहिए। अगर वो रिलायंस को ग्रांट इन एड दे सकती है, टाटा को ग्रांट इन एड दे सकती है तो फिर दिल्ली मैट्रो को क्यों ग्रांट इन एड नहीं दी जा सकती? इन लोगों को कहिये उबर और ओला के बहकावे में बिकें न, ईमानदारी से तीन हजार करोड़ दें ताकि दिल्ली के लोगों को यह राहत मिले और दिल्ली के लोगों का किराया न बढ़े, बहुत–बहुत धन्यवाद।

अध्यक्ष महोदयः राजेश ऋषि जी। बंदना जी नहीं है, राजेश ऋषि जी।

श्री राजेश ऋषिः अध्यक्ष जी, आपने मुझे मैट्रो के विषय में बोलने का मौका दिया, उसके लिए बहुत–बहुत धन्यवाद।

हमारे सिरसा जी डर के भाग रहे हैं, इस मैदान को छोड़कर। मैं चाहूँगा कि वो बैठें यहां पर, क्योंकि इन्हीं के द्वारा यह गेम खेला जा रहा है, इन्हीं

के द्वारा यह गेम बनाया गया और आज जो दिल्ली की जनता त्रस्त है, वो इन्हीं जैसे लोगों के कारण ही त्रस्त है। अंदर आकर झूठ बोलते हैं और बाहर जाकर झूठ बोलते हैं। सच्चाई के सामने कभी ये टिक नहीं सकते। मैं आपको बहुत–बहुत धन्यवाद देता हूं, साथ में मैं धन्यवाद देता हूं संजीव झा जी को, जिन्होंने आज नियम 54 के अंतर्गत मैट्रो के जो किराये बढ़े हैं, उसके मुद्दे को उठाया।

अध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से एक चीज बताना चाहता हूं कि दिल्ली की जनता जो गरीब है, जो अखबार नहीं पढ़ पाती, उसको ये नहीं पता कि ये किराये क्यों बढ़े। वो तो ये कहते हैं कि दिल्ली मैट्रो यानी कि दिल्ली सरकार की मैट्रो। वो ये नहीं समझ रहे कि ये केन्द्र सरकार की इसमें 50 परसेंट की भागीदारी है और 50 परसेंट की भागीदारी दिल्ली सरकार की है। किस तरीके से कमेटी बनी। किस तरीके से कमेटी ने किरायों को बढ़ाया। पहले मई में बढ़े अब फिर बढ़े। अब फिर 50 परसेंट की बढ़ोत्तरी हुई। ये सारा का सारा गेमप्लान जो हो रहा है, ये केन्द्र में बैठी सरकार कर रही है। ये हमसे नहीं, दिल्ली की गरीब जनता से बदला ले रही है जो दिल्ली की जनता ने हम जैसे आम आदमी को यहां पर लाकर खड़ा किया। ये बदला ले रहे हैं हमसे। मैं आज आपको बताता हूं कि जब मैं अपने आफिस से चला यहां आने के लिए, मेरा आफिस उत्तम नगर ईस्ट मैट्रो स्टेशन के बिल्कुल साथ बना हुआ है। जैसे ही मैं वहां पहुंचा, मुझे सात आठ वहां के स्टूडेंट्स जो वहां पर पढ़ने आते हैं, उन्होंने मुझे घेर लिया। उन्होंने मुझसे कहा कि देखिये, ऐसे ऐसे बढ़ गए किराये, हम लोग दूसरे शहर से आकर कमरा लेकर यहां किराये पर रह रहे हैं और यहां कोचिंग करने आते हैं और ऐसे बढ़ेंगे तो सरकार से कहें कि कि ये वापस लें। हमारी तो पाकेट मनी भी खत्म हो जाती है। ये स्थिति मेरे घर

की भी है। मेरी बेटी भी वहां से आती है, विश्वविद्यालय पढ़ने के लिए। उसने भी मुझसे डिमांड की कि अब इस बार पाकेटमनी मुझे बढ़ाकर देना क्योंकि अब मेरे पास किराया भी नहीं बचेगा। हर गरीब आदमी परेशान हो गया है इस मैट्रो के किराये के बढ़ने के कारण। मैंने अभी अखबार में पढ़ा था कि जो हरदेव सिंह पुरी केन्द्रीय आवास एवं शहरी मामलों के मंत्री हैं, वो बड़ा ठोककर कह रहे हैं कि ये जो समिति की रिपोर्ट है, इसको न तो केन्द्र सरकार बदल सकती है और न ही कमेटी। तो कमेटी बनाने का फायदा क्या? हमारी कमेटी के अंदर मेंबर हैं वो जाते हैं, बात रखते हैं, जब उन्होंने फाइनल करके भेजना ही है तो हमारी कमेटी का फायदा क्या, हमारे लोगों का फायदा क्या वहां पर? ये तो तुगलकी फरमान जारी कर रहे हैं। ऐसा लग रहा है कि इस समय केन्द्र में एक तुगलक शासक बैठा हुआ है जो तुगलकी फरमान जारी कर रहा है।

अध्यक्ष जी, मैं आपको एक चीज बताना चाहूंगा कि इससे पहले भी भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनी तब ये लोग अपना जो राम मंदिर के मुद्दे पर सरकार बनाकर आए, इन्होंने तब भी आकर वही हाल किया जैसे अभी मदनलाल जी बता रहे थे कि इन्होंने सरकारी संस्थाओं को बेचना शुरू किया। मैं आपको बताना चाहता हूं कि मैं आगरा में था उस समय। आगरा का आईटीसी होटल बिका। इन लोगों ने केन्द्र सरकार के जो होटल थे, उनको बेचना शुरू किया। जिस आदमी ने होटल को खरीदा, उस आदमी ने बताया कि जितनी क्राकरी है, उसके दाम में मैंने खरीदा। बाकी मैंने अण्डर द टेबल दिये। ये स्थिति है इन लोगों की अण्डर द टेबल का काम कर रहे हैं और देश की संपत्ति को बेचने का काम कर रहे हैं। इन्होंने विदेश संचार निगम बेचा, टाटा को बेचा क्योंकि उस समय रिलांयस खड़ा नहीं हुआ था। इन्होंने टाटा को बेचा, कोड़ियों के भाव बेचा। जितने की जमीन

थी, उसके चौथाई भी पैसे नहीं मिले। पूरा सिस्टम मिला उनको और अब स्थिति ये आ गई है कि ये देश के अंदर हर चीज में घाटा दिखाकर देश की बड़ी बड़ी संस्थाओं को बेचने की तैयारी कर रहे हैं। आज ये स्थिति है कि पहले इन्होंने रेलवे के किराये बढ़ाये, उसके बाद आज भी दिखा रहे हैं, बढ़ाने के बाद इनके घाटे हो रहे हैं। रेलवे के पास करोड़ों रुपयों का तो स्क्रैप पड़ा हुआ है ये स्क्रैप के साथ साथ रेलवे को अडानी को बेचने की पूरी तैयारी कर चुके हैं। ये अडानी और अंबानी की सरकार चल रही है। ये कोई आम आदमी की सरकार नहीं है, न जनता की सरकार है केन्द्र में इस समय। केन्द्र में जनता ने चुनकर भेजा है इनको। गरीब आदमी से वोट लेकर ये खड़े हुए हैं। इन्होंने सरकार बनाई है लेकिन सरकार बनाने के बाद किया क्या है इन्होंने? इन्होंने वही किया जो पहले कांग्रेस की सरकारें करती रहीं; गरीब से वोट लो, अमीरों के लिए काम करो और ये हाल इनका चलता चला आ रहा है जो देश के अंदर इस समय स्थिति पैदा हो गई है। नोटबंदी से मंदी के हालात हैं। जीएसटी आने के बाद आज सेल नहीं है लोगों के पास। मैं खुद भी व्यापार करता था। मैं राजनीति में आने से पहले छोड़ चुका था लेकिन आज मैं अपने भाइयों के पास बैठकर सुनता हूं तो मैं खुद हैरान हो जाता हूं कि कैसे कैसे वो काम कर पा रहे हैं। जीएसटी के आने के बाद आज बिजनसमैन की कमर टूटी हुई है और उसके ऊपर से ये किराये की वृद्धि। जो छोटे छोटे बिजनसमैन हैं, जो बेचारे सामान लेने के लिए जाते हैं, आते हैं, मैट्रो का यूज करते हैं, वो लोग भी परेशान हैं कि कैसे चलेगा। मैं चाहता हूं कि इस सदन में आज हमारे सभी साथियों ने इस मुद्दे के ऊपर एक एक बात रखी। हमारे जैन साहब ने तो वो चीज समझाई जो हमें आज तक नहीं पता था कि किस तरह से किराये का निर्धारण किया जाता है। हर स्कवैयर मीटर के ऊपर जैसे विदेशों में पांच आदमी गिने जाते हैं, यहां पर ग्यारह गिनने के बाद भी

यहां घाटे में जा रही है, ये बड़ा सोच का विषय है। हम तो चाहते हैं कि सीएजी से एक बार आडिट कराकर देख लो। केवल सीएजी के ऑडिट से ही हो सकता है कि किराये रुक जाएं। ऑडिट के डर से ही किराये रुक जाएं।

श्री मनजिंदर सिंह सिरसाः ऑडिट तो मेन्डेटरी है।

श्री राजेश ऋषिः सर मेन्डेटरी तो है लेकिन स्थिति क्या है, आप खुद देख रहे हैं। आज की स्थिति ये है कि जो जमीनें पारसनाथ को दी गईं, आपने देखा होगा कि हर जगह पर पारसनाथ के बड़े बड़े बंगले बने पड़े हैं, बड़े बड़े फ्लेट्स बने पड़े हैं, किसी को अभी तक अलाट नहीं किया। मेरे जनकपुरी में भी एक बहुत ही पॉश जगह पर है जिसको अभी मैट्रो वालों ने घेर लिया है। उसके ऊपर अभी फ्लेट्स बनाने की तैयारी चल रही है। तो ये फ्लेट बनाकर बेचेंगे या किराये पर देंगे, तो उससे बहुत सारी अर्निंग होगी। ये कोई तरीका नहीं हुआ कि जनता पर दबाव बनाते जाओ, किराये बढ़ाते जाओ क्योंकि जनता के पास दूसरा कोई ऑप्शन नहीं है। ये दूसरा आप्शन पैदा कर रहे हैं, ओला के माध्यम से। प्रधानमंत्री जी खुद जाकर बैठते हैं ओला को लाने के लिए। तैयारी में लगे हुए है वो। खुद बैठकर प्रचार कर रहे हैं।

मैं आपको बताना चाहता हूं कि जब वाजपेयी जी प्रधानमंत्री बने तो उन्होंने लखनऊ में एक चिटफंड कंपनी का उद्घाटन किया जी। चिटफंड कंपनी ने बड़े बड़े पोस्टर लगाये प्रधानमंत्री जी के। उस पोस्टर लगाने से क्या हुआ कि जनता का विश्वास जागा और उस चिटफंड कंपनी में लोगों ने लाखों करोड़ों रुपया इन्वेस्ट किया। वो चिटफंड पैसा लेकर भाग गई और आज तक उनको पैसा नहीं मिला। प्रधानमंत्री जी को कितना मिला होगा, ये तो हमें नहीं मालूम, अटलबिहारी वाजपेयी जी थे उस समय और

यही स्थिति आज है। आज मोदी जी भी बड़ी बड़ी कंपनियों का प्रचार कर रहे हैं। प्रचार करने के पीछे उनकी मंशा क्या है? उनकी मंशा एक ही है कि किस तरीके से फंड लिया जाए पार्टी के अंदर। किस तरीके से गैरकानूनी तरीके से इनसे काम करवाए जाएं। आज देश की सरकार, केन्द्र में बैठी सरकार मोदी जी की सरकार रिलायंस और अडानी जैसे लोग चला रहे हैं, इसलिए जनता को आज इनसे कोई उम्मीद नहीं है और मैं चाहता हूं कि आज आपने मुझे मौका दिया है बोलने का, मैं चाहता हूं कि जिस मुद्दे पर आज संजीव झा जी इस मोशन को लेकर आए हैं, उसका मैं पूर्ण समर्थन करता हूं और आप सब लोग भी समर्थन करें। मेरे विपक्ष के भाई एक बार बोल दें कि वो भी चाहते हैं कि किराया कम हो, एक बार ये बोल दें खाली, क्योंकि ये चाहते नहीं हैं कि किराया कम हो और बार बार ये उन्हीं को डिफेंड करने के लिए खड़े हुए हैं, केन्द्र सरकार को। अध्यक्ष महोदय, आपका बहुत बहुत धन्यवाद जो आपने मुझे बोलने का मौका दिया।

अध्यक्ष महोदयः श्री गुलाब सिंह जी।

श्री गुलाब सिंहः धन्यवाद अध्यक्ष महोदय, बहुत गंभीर मुद्दे पर आपने बोलने का मौका दिया।

ये सदन आज इस पर दो तीन दिन से इस मुद्दे पर चर्चा कर रहा है क्योंकि करीबन ढ़ाई साल पहले बहुत उम्मीद के साथ आम आदमी पार्टी की सरकार लोगों ने चुनी थी और उससे ठीक अगर हम बात करें 2014 में बहुत उम्मीद के साथ देश के प्रधान को लोगों ने चुना था लेकिन 2014 के लोकसभा चुनाव के ठीक एक साल बाद दिल्ली के चुनाव थे और दिल्ली के अंदर किस तरह से भारतीय जनता पार्टी का एक ही साल के अंदर उनका नेतृत्व देखते हुए सूपड़ा साफ हुआ, ये सबके सामने था। जो मोदी साहब के बारे में नारे लिखे जा रहे थे, वो नारे 'बहुत हुआ भ्रष्टाचार

अबकी बार मोदी सरकार था। 'बहुत हुआ नारी पर वार, अबकी बार मोदी सरकार' तो एक नारा उसमें और लिखने को कहा गया कवि को कि भई ऐसा लिखकर लाइयो जिसमें फूल भी हो। अब वो बेचारा कवि फंस गया बोले, ''पंक्ति भी मिलनी चाहिए। जमना भी चाहिए।'' तो वो बेचारा बड़ी मेहनत करके वो लिखकर लाया वो कहीं जमा नहीं उसके अंदर तो वो लिखकर लाया, बड़ी मेहनत की उसने कि घर घर मोदी, यही था न? हर हर मोदी घर घर मोदी। अब फंस गया वो वहां पर। 'हर हर मोदी घर घर मोदी, एक बार जिता दो, जनता की गोभी खोदी। भाई साहब, गोभी खोद दी पिछले तीन साल में जनता की, गोभी खोद दी जनता की गोभी खोदने का मतलब गर्त में बिठा दिया देश। आज पूरे देश के अंदर निराशा का माहौल है और यही दिल्ली के अंदर कर रहे हैं। यही कर रहे हैं दिल्ली के अंदर। हर काम के बीच में बाधा डालना। सच्चाई मानिये एक बार विपक्ष के नेता यहां पर बैठे होंगे, राजनीति का दौर आएगा। दो साल बाद, तीन साल बाद चुनाव होंगे। खूब आप हमारे ऊपर हमले करिए। खूब हम आपके ऊपर करेंगे लेकिन कम से कम फिलहाल तो राजनीति मत करिए। फिलहाल तो इस जनता के बारे में सोचें कि जिन्होंने सात सांसद आपको चुनकर दिए थे, क्या इस उम्मीद के साथ दिए थे कि जो केन्द्र सरकार के अंदर, संसद में लोकसभा में बैठते हैं, क्या एक बार भी इस सदन के अंदर... आगामी सत्र लगेगा, पूरी दिल्ली देखेगी, सातों सांसदों को कि क्या उनको दिल्ली की चिन्ता है, क्या वो एक बार भी जो मैट्रो का किराया बढाया गया है, क्या इसके ऊपर एक बार भी देश के प्रधान के सामने ये बात रखेंगें? क्या एक बार भी कहने की हिम्मत जुटा पाएंगे? नहीं जुटा पाएंगें। नहीं कर पाएंगें। लेकिन इस पूरे प्रकरण में, इस पूरी चर्चा में दो चीजें सामने निकल कर आ रही हैं, या तो ये राजनैतिक मंशा से किया जा रहा है या व्यवसाय की मंशा से किया जा रहा है। दो ही चीजें हो सकती हैं या

तो अरविंद केजरीवाल की जो पॉपुलेरिटी जो पूरी दिल्ली के अंदर बढी है, कुछ भी करो, उसको रोको। लेकिन जब–जब अरविन्द केजरीवाल की पॉपुलेरिटी को रोकते हो आप तो साहब, वो जनता का नुकसान होता है, अरविंद केजरीवाल की पॉपुलेरिटी बढती चली जाती है। आपको दो दिन पहले सीएम साहब जब अपना वक्तव्य यहां पर रख रहे थे और आपसे बहुत शालीनता के साथ चर्चा कर रहे थे, तो उनके शब्दों में कही आपको नाराजगी आई आपके सामने? आपने कहा कि हमें गाली दी। नेता प्रतिपक्ष ने कहा कि हमारे सम्मान को ठेस पहुंची है। पहली बात तो उनके कोई शब्द गलत नहीं थे। लेकिन भाजापा के नेता समय–समय ऐसे शब्दों का इस्तेमाल करते हैं जिसमें देश के आम व्यक्ति के सम्मान को ठेस पहुंचती है।

... (व्यवधान)

अध्यक्ष महोदयः क्या भाषा बोली इन्होंने? नहीं, कौन सा गलत बोला इन्होंने? एक शब्द गलत नहीं बोला। वो सीएम के पक्ष को रख रहे हैं। आपने अपने तरीके से रखा । आप बैठिए प्लीज, बैठिए। ओम प्रकाश जी, बैठिए प्लीज।

श्री गुलाब सिंहः मेरा उसके अंदर सिर्फ ये कहना है ओम प्रकाश जी कि व्यक्तिगत तौर पर आप मुझे.... मैं दिल्ली की सबसे...

... (व्यवधान)

विधान सभा से चुनकर जनता ने यहां पर भेजा है। करीब 10 मैट्रो स्टेशन वहां पर पड़ते हैं। रोजाना लोगों से मिलता हूं। और अगर आपको शब्दों का इतना बुरा लगा है तो व्यक्तिगत तौर पर चार गाली आप मुझे दे दीजिए लेकिन जनता की भलाई के लिए आप केन्द्र सरकार से 50

प्रतिशत वहां पर आप पन्द्रह सौ करोड़ हमें दिलाइए ताकि यहां पर दिल्ली के अंदर मैट्रो का दाम न बढ सके। यहां हम अपने सम्मान के लिए नहीं लड़ने के लिए नहीं आए, यहां पर हम अपनी इज्जत के लिए खडे हैं, यहां पर जनता की इज्जत के लिए लड़ाई लड रहे हैं। जनता के सम्मान के लिए यहां पर बात रख रहे हैं। तो थोड़ी बहुत शर्म हया है तो आपसे मेरा निवेदन है कि आप जाइए राजनीति दो साल बाद कर लीजिए लेकिन फिलहाल इस मैट्रो के किराए को बढ़ने से रोकिए।

माननीय अध्यक्ष महोदय, आपके सामने बहुत महत्वपूर्ण एक मैं प्रस्ताव रखना चाहता हूं कि इस पूरे मैट्रो के किराए के अंदर कहीं न कहीं जनता के सामने फैक्टस आने चाहिए और इसको लेकर विधान सभा के अंदर एक कमेटी गठन होना चाहिए। जो अगले दस दिन के अंदर अपनी रिपोर्ट जनता के सामने रखे। ये बेहद जरूरी है। जनता को गुमराह भी किया जा रहा है। जनता को गुमराह किया जा रहा है इनके सोशल मिडिया में बैठकर ट्विटर हैंडल से, फेस बुक हैंडल से जनता को गुमराह करने की कोशिश की जा रही है। इस लिए विधान सभा की कमेटी उसको विधान सभा के पटल पर रखे और जनता के सामने वो जाना चाहिए। मैने कहा था कि इसके अंदर पहली मंशा तो राजनैतिक हो सकती है और दूसरी व्यवसाय की, और व्यवसाय की जो बात हमारे कई सारे साथियों ने कही कि ओला उबर को लेकर जो बात यहां पर सामने आई, मुझे तो लगता है जिस तरह से बड़े–बड़े ट्रक्स के पीछे, टैम्पों के पीछे कुछ पक्तियां लिखी होती है। कही आने वाले समय में ऐसा तो नहीं कि हमें ओला और उबर के पीछे कोई पक्ति मिले कि पलट तेरा ध्यान किधर है, जय ओला और जय उबर इधर है। जय ओला और जय उबर इधर है। कहीं ऐसा तो नहीं कि इस पूरे के पूरे प्रकरण में भारतीय जनता पार्टी के कुछ नेताओं का पैसा आने

वाले समय में लगाकर और ओला और उबर को अपना खुद का व्यापार बनाने की कोशिश तो नहीं है, इसकी जांच होनी चाहिए। ये बहुत गम्भीर विषय है। इस लिए अध्यक्ष महोदय, मेरा आपके माध्यम से निवेदन है कि इस कमेटी का गठन तो बिल्कुल होना चाहिए क्योकि हम रोजाना.... मैं एक आम परिवार की बात रखता हूं। दिल्ली के अंदर तेरह हजार रूपये न्यूनतम मजदूरी करीबन है ओर आप सोचिए कि एक घर में चार लोग रहते हैं एक बेटा एक बेटी। बेटी स्कूल जाती है, बेटा कालेज जाता है। घर के अंदर एक वॉइफ है जो हाउस वॉइफ है और व्यक्ति द्वारका से मैट्रो पकड़ता है। और लक्ष्मी नगर या दिल्ली विधान सभा के आसपास में कहीं पर न्यूनतम मजदूरी करने के आता है जो उसको महीने के करीबन 13 हजार रूप्ये मिलते हैं। अब आप सोचिएगा कि साठ रूपये जाने के और साठ आने के, 120 रूपये के हिसाब से 30 दिन का 3600/–रूपया बन गया। और इतेफाक से उसका बेटा भी कॉलेज में पढता है। अब उसके भी 3600/–रूपया जोड़ लीजिए। मिलते कितने है उसको? एक बार उस आखिरी इंसान की तरफ देखिए कि वो कैसे पूरी दिल्ली को क्रॉस करके आपके कॉलेज में पहुंचता है, अपने व्यवसाय के पास पहुंचता है, अपनी नौकरी करने के लिए पहुंचता है और उसके पास कितना धन मैट्रो का किराया देकर बचेगा! उसकी तरफ देखने की जरूरत है। बहुत गम्भीरता के साथ और बहुत उम्मीद के साथ दिल्ली की जनता इस सदन की तरफ उम्मीद लगाए बैठी है। विपक्ष के अंदर आप बैठे हैं और क्यों बैठे है और पिछले 19 साल से बैठे हैं। ये सोचने की जरूरत है। आपके बोलने से कोई फर्क पड़ने वाला नहीं है। पन्द्रह साल लगातार शीला दीक्षित मुख्य मंत्री रही। वो आपके नाकारापने की वजह से रही। क्योंकि दिल्ली की जनता आप पर यकीन ही नहीं करती है। दिल्ली की जनता आप की जुमलेबाजी जानती है। दिल्ली की जनता भारत जलाओ पार्टी की सच्चाई जानती है।

कभी गाय की बात करते हैं, कभी गोबर की बात करते हैं, कभी कुछ करते हैं। इनको कोई फर्क नहीं पड़ता। किराया बढ़ना है तो बढ़ने दो। अभी कोई चुनाव थोड़े ही है। लोग मर रहे हैं तो मरने दो। ये कोई गाय थोड़े ही है। तो इन लोगों को फर्क नहीं पडता। इसलिए मेरा निवेदन है कि ये सदन कल भी इस विषय में चर्चा करने जा रहा है। जहां तक मुझे पता चला है। और इस किराये को लेकर इसकी बढोत्तरी को लेकर मेरा अध्यक्ष साहब, आपसे निवेदन है माननीय मुख्य मंत्री जी से निवेदन है कि हम सभी विधायको को जनता के बीच में जाना चाहिए और जनता को साथ लेकर एक बडे आन्दोलन की तैयारी भी करनी चाहिए, अगर केन्द्र सरकार इसमें नहीं मानती है तो। बहुत जरूरी है और हम सब इसके लिए तैयार हैं। और ईंट से ईंट बजा देंगे लेकिन कुछ भी करेंगे इस किराए को नहीं बढने देंगे, नहीं बढने देंगे, नहीं बढने देंगे, बहुत–बहुत शुक्रिया धन्यवाद।

अध्यक्ष महोदयः नरेश बाल्यान जी। जरनैल सिंह जी।

श्री जरनैल सिंहः धन्यवाद, अध्यक्ष जी।

अध्यक्ष जी जैसा कि कल उप–मुख्य मंत्री श्री मनीष सिसोदिया जी बता रहे थे। विपक्ष के साथी बोलते तो हैं पर कोई आंकडों पर आधारित बातें इनके पास नहीं होती। कोई फैक्ट फिगर नहीं होते, बस बोलना है, फलां–फलां कुछ भी बोल दिया। दो साथियों ने बोला। दोनों ने बोला जी, दस दिन के अंदर आपको मैट्रो के किराये की चिन्ता होने लगी। मैं सारे सदन का ध्यान आपके माध्यम से इस पत्र की तरफ दिलाना चाहता हूं जो 30 जून, 2016 को लिखा गया था। आज से लगभग सवा साल पहले लिखा गया था। दिल्ली सरकार की तरफ से दिल्ली मैट्रो को लिखा गया था और इसमें किराया बढ़ाना तो दूर, इसमें लास्ट ये इसमें हाई लाइट कर रखा है इसमें लिखा हैः– "This is further suggested that metro may think

of reducing the fair by fifty percent. 50 प्रसेंट फेयर कम करने की बात की थी during the---

... (व्यवधान)

peak hours so that occupency in the metro during this time is fully utilized कि जिस टाइम मैट्रो में भीड़ कम है उस टाइम मैट्रो का किराया ईवन आधा कर देना चाहिए। ये तो कह रहे हैं, हमने बढ़ाने की बात की है। तो बहुत ही ये शर्मनाक है कि बिना किसी आंकड़े के आधार पर विपक्ष के हमारे साथी कुछ भी बोल देते हैं। जबकि हकीकत कुछ और होती है। ये वो सरकार है जो दिल्ली के हर आदमी का सोच रही है, ये वो सरकार है जो दिल्ली में फ्री पानी देती है। आप लोगों को समझ नहीं आएगा। जब टैंकर माफिया से चंदा लेकर लड़ते हैं। ये वो सरकार है जो दिल्ली में आधे रेटों में बिजली दे रही है। इन लोगों को समझ नहीं आएगा। जो बिजली कम्पनी के मालिक से चंदा लेकर लड़ते हैं। ये वो सरकार है जो दिल्ली के स्कूलों का लेवल आज प्राईवेट स्कूलों से बेहतर बना चुकी है। इनको समझ आयेगा जिनके आज अपने प्राईवेट स्कूल चलते हैं। ये वो सरकार है जो मजदूरों की मजदूरी तेरह हजार रूपये महीने कर चुकी है। इनको समझ नहीं आएगा जो लोगों का शोशण करते आए हैं आज तक।

अध्यक्ष जी, एक तरफ वो सरकार है जो हर दिल्ली के आम आदमी से जुड़े हर मसले पर, हर जायज मसले पर बे हिसाब काम किये जा रही है... किये जा रही है । दूसरी तरफ वो लोग बैठे हैं जो सिर्फ फर्जी बातें करते हैं। अभी दो तीन दिन पहले अपने गांव गये थे जी। इनके फर्जीवाड़े की एक लेटेस्ट मिसाल दे रहा हूं आपको। वहां पर जाकर अपनी मिट्टी को भी चूमा अच्छी बात है जी। बताते है कि 1950 में इनका जन्म हुआ था। और बताते आऐ हैं कि देश को इस चीज पर बेवकूफ बनाते आए

हैं कि मैने तो बचपन में चाय बेची है। बोलते हैं ना? 1950 में इनका जन्म हुआ पर जो मैट्रो का जो वहां रेलवे स्टेशन बना, बडनगर का वो 1973 में बना है। तो या तो 23 सालों तक बचपन नहीं खत्म हुआ था या फिर झूठ बोल रहे हैं। ये फैक्ट है अध्यक्ष जी, बडनगर का रेलवे स्टेशन 1973 में बना है। साहब का जन्म 1950 में हुआ है। जिस स्टेशन पर ये चाय बेचने की बात करते हैं। तो इनकी बातें झूठी, इनकी कहानी झूठी, इनकी डिग्रियां फर्जी, इनके वादे जुमले। ऐसे फर्जी लोगों से बंदा उम्मीद भी क्या कर सकता है। अब जो मैट्रो के फेयर बढ़ रहे हैं, दिल्ली सरकार की तरफ से हर जायज कोशिश की गई है कि ये फेयर ना बढ़े और जहां इस दिवाली के मौके पर दिल्ली सरकार दिल्ली वालों को छः हजार नये कमरों का ताहेफा दे रही है। दिल्ली में नई नई सीवर की और पानी की लाईनें बिछा रही है, वहां पर मोदी सरकार की तरफ से दिवाली का ये तोहफा मिल रहा है कि भईया, जो थोड़ी बहुत दिवाली मनाने की भी सोच रहे थे ना, वो भी भूल जाओ। वो भी मैट्रो के कार्ड में डलवा लो पैसे जो दिल्ली के लोगों को परेशानी और ज्यादा बढ़े।

अब बात अगर फैक्ट एंड फिगर की करते हैं तो 2009 से लेकर 2016 तक आठ साल किसी को ये सुध नहीं आई थी कि किराये बढ़ाने हैं। आठ साल बाद एकदम ये जाग गये और फिर सारा ब्लेम दिल्ली सरकार के ऊपर। खुद संजीव भाई ने बोला, मैं भी गया, साथ में हमारे प्रवीण भाई भी गये सारे मैट्रो के ईडी से मिल के आये कह रहे, ''जी ये तो फेयर फिक्सेशन कमेटी की रिपोर्ट है, बाइंडिग है, किराये तो बढ़कर रहेंगे। मैं आज इस सदन के माध्यम से क्योंकि बातें सारी मेरे साथी कर चुके हैं। दिल्ली के अंदर किसी भी सूरत में बढ़े किराये बरदाश्त नहीं किये जायेंगे, चाहे इस समस्या का हल इस सदन में निकले, चाहे सचिवालय में जा कर निकले

और चाहे सड़कों में जाकर निकले। हम हर वो कोशिश करेंगे कि किराये बढ़े हुए वापिस हों और जो बात मेरे साथियों ने की है कि मैट्रो में क्या चल रहा है। आपने अलग अलग विषयों के ऊपर विधानसभा में कमेटियां बना रखी हैं तो इस सदन के माध्यम से लोगों को भी मालूम चले, दिल्ली की जनता को भी मालूम चले कि मैट्रो में क्या चल रहा है, मैट्रो से संबंधित मामलों पर भी एक कमेटी दिल्ली विधानसभा के सदन में बनाई जाये। आपने मुझे बोलने का समय दिया उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद।

अध्यक्ष महोदयः अब माननीय मंत्री जी

... (व्यवधान)

अध्यक्ष महोदयः देखिये नितिन जी...

... (व्यवधान)

अध्यक्ष महोदयः मेरी एक बार प्रार्थना सुन लीजिये। मुझे चार बजे हाऊस ऐडजॉर्न करना है। एक मीटिंग में जरूरी जाना है। माननीय सदस्यों की और से भी...

... (व्यवधान)

अध्यक्ष महोदयः प्रमिला टोकस जी। ये मैं स्वीकार कर लेता, प्लीज...

... (व्यवधान)

अध्यक्ष महोदयः मुझे संदेश मिला है कुछ माननीय सदस्यों को भी मीटिंग में जाना है सदस्यों को मीटिंग में जाना है भई प्लीज, अब नहीं। हां प्रामिला जी।

श्रीमती प्रमिला टोकसः अध्यक्ष जी, धन्यवाद, आपने मुझे बोलने का मौका दिया।

अध्यक्ष जी, सिरसा जी कह रहे थे कि जब मीटिंग हुई तो अरविंद केजरीवाल जी के मुंह में फेविकोल लगा के बिठा दिया गया, मैं सिरसा जी को बताना चाहती हूं, हैं नहीं यहां पर। मैं बोली वही के बताने के लिये कि हम 67 विधायक हैं, ये अरविंद केजरीवाल जी की आवाज हैं और आज ये हम 67 विधायक में से कितने विधायक बोले, वो सब अरविंद केजरीवाल जी की आवाज हैं। जो सिरसा जी कह रहे थे ना कि मीटिंग में फेविकोल मुंह में लगा के बिठा दिया गया और अध्यक्ष जी, वो कहते हैं कि हमारे केजरीवाल जी को परवाह नहीं है। मैं ये जानना चाहती हूं कि मेरे से दो सवाल किये। किसने किये? सिरसा जी से दो सवाल बताओ किसने किये?

... (व्यवधान)

श्रीमती प्रमिला टोकसः या उत्तर देना है तो जितने हमारे सदस्य बोले हैं अभी तक उनका सबका जवाब दें। नहीं तो ये बतायें किसने उनसे पूछा कि आप जवाब दो? या तो फिर हर चीज का जवाब दें वे यहां पर।

... (व्यवधान)

श्रीमती प्रमिला टोकसः और अध्यक्ष जी, ये तो कहते हैं कि केजरीवाल जी को परवाह नहीं है। क्या मोदी जी को परवाह है? नोटबंदी करके कहां चले गये थे? वो क्या भारत में थे? पब्लिक लाईनों में खड़ी है और वो हवाई जहाज में उड़ रहे हैं!

... (व्यवधान)

अध्यक्ष महोदयः प्रामिला जी, चलिये चलिये, आप चालू रखिये प्लीज।

श्रीमती प्रमिला टोकसः अध्यक्ष जी, मैं ये जानना चाहती हूं क्या हमारे

प्रधानमंत्री जी ने अभी तक जनहित में कोई कार्य किया है? मैं ये जानना चाहती हूं क्या उन्होंने एक भी कार्य ऐसा किया हो जो जनहित में जारी हो और हमारी अरविंद केजरीवाल जी ने कितने कार्य किये, हमारे सभी सदस्यों ने अभी अभी बताये सभी को और आप अध्यक्ष जी, यहां पर हमारे अध्यक्ष हैं, आप हमारे, हमारी पार्टी के अध्यक्ष हैं या उनके अध्यक्ष नहीं है? क्या हमारे प्रधानमंत्री जी, क्या बीजेपी के ही प्रधानमंत्री हैं या पूरे देश के प्रधानमंत्री हैं? आप देखेगें जो जाकेट पहने होते हैं, उस पर कमल का फूल होता है।

... (व्यवधान)

श्रीमती प्रमिला टोकसः और प्रधानमंत्री होकर वो बीजेपी का प्रचार करता है, ये कैसा प्रधानमंत्री! ऐसा पहली बार जिंदगी में हमने प्रधानमंत्री देखा कि अपनी पार्टी का प्रचार कर रहे हैं।

... (व्यवधान)

श्रीमती प्रमिला टोकसः क्या उनको देश का ख्याल है? नोटबंदी करके और जीएसटी लगा के अध्यक्ष जी, लोग ये कहते हैं कि जब हम बाहर खाना खाने जाते हैं कि भारत सरकार के अगर हम चार मैम्बर खाना खा रहे हैं तो भारत सरकार के चार मैम्बर हमारे साथ बैठकर खाना खा रहे हैं इतना जीएसटी लगा हुआ है। अब वही बात अब रेल में जायेंगे, मैट्रो में जाएंगे तो चार भारत सरकार के बंदे बैठकर जायेंगे उनके साथ। इतना किराया इन्होंने बढाया और मैट्रो में कौन जाता है? जो मिडिल क्लास है वही मैट्रो में जाते हैं। हमारी सरकार कहती है की हम ऐसी व्यवस्था करेंगे कि लोगों को मैट्रो तक हम कैसे पहुंचायें, वो सुविधा देने में लगी है लेकिन ये कहते हैं, नहीं, ये सुविधा नहीं देंगे। हम मैट्रो में तो किसी को जाने

ही नहीं देंगे। क्योंकि किराया इतना बढाया मैट्रो में जायेगा तो कौन... तो मुझे लगता है मोदी जी ज्यादा सोच रहे हैं। फिर ये तो सिरसा जी, अब आप कह रहे हैं कि मेरे प्रश्न का जवाब दीजिये। अगर आप जवाब देना चाहते हैं अभी हमने बिल पास किया गेस्ट टीचरों का तो आप पास करा दीजिये अगर आप भारत सरकार को प्रेजेंट करते हैं यहां पर।

अध्यक्ष जी, मोदी हर चीज में बताओ बहनो और भाइयो, यो काम होना चाहिए या नहीं होना चाहिए? बताइये मित्रो, ये काम होना चाहिए या नहीं होना चाहिए? कितने किसानों ने आत्महत्या की। बताइये, उन्होंने क्या किया अभी तक किसानों के लिये?

... (व्यवधान)

अध्यक्ष महोदयः कन्क्लूड करिये प्लीज।

श्रीमती प्रमिला टोकस : अध्यक्ष जी, मैं यहां पर सिरसा की बात पर बोलने के लिए उठी हूं उन्होंने कहा मेरे से क्वैशचन किया, अब मैं क्वैश्चन कर रही हूं, वो जवाब दें अगर वो भारत सरकार....

अध्यक्ष महोदयः जवाब कुछ नहीं, आप कन्क्लूड करिये, प्लीज। सिरसा जी, बैठिये। नहीं, नहीं, ऐसे नहीं बैठिये प्लीज। नहीं, मदन जी प्लीज।

... (व्यवधान)

श्रीमती प्रमिला टोकसः अध्यक्ष जी, मैट्रो में ज्यादातर....

अध्यक्ष महोदयः अखिलेश जी, बैठिये, नीचे बैठिये। नहीं मैं किसी को एलाऊ नहीं करूंगा।

... (व्यवधान)

श्रीमती प्रमिला टोकसः लेडीज सफर करती हैं और मैं एक लेडी होने के नाते यह जो किराया बढाया, मैं इसका विरोध करती हूं और आपने मुझे बोलने का मौका दिया, धन्यवाद।

अध्यक्ष महोदयः बस एक केवल अंतिम है सही राम जी। जिनका आज जन्मदिन है उनकी और से उनका जन्मदिन है, इसलिये मैं उनको रोक नहीं रहा हूं।

श्री सही रामः धन्यवाद अध्यक्ष जी।

अध्यक्ष जी, मैं सीधा सीधा मुददे पर आऊं। आज मैट्रो रेलवे के बढ़े हुए किराये पर चर्चा हो रही है और एक गहराई से अगर इस पर सोचा जाये तो ये किराया बढ़ाया क्यों जा रहा है, किन लोगों के कारण से बढ़ रहा है, ये सोचने का विषय है। आज से साढ़े तीन साल पहले दिल्ली में केन्द्र की सरकार चुनी गई। उस समय भी बड़ा प्रचार था, बहुत हुआ भ्रष्टाचार, अब की बार मोदी सरकार। एक सरकार ढ़ाई साल पहले चुनी गई; दिल्ली की सरकार, आम आदमी पार्टी की सरकार । उस टाईम भी भ्रष्टाचार का ही मुददा था।

अध्यक्ष जी, एक तरफ तो वो सरकार है जिनके अध्यक्ष का पुत्र तीन साल में सोलह हजार गुणा उसकी इन्कम बढ गई एक ही साल में जब कि वो खाली भारतीय जनता पार्टी के अध्यक्ष थे। तब इतनी प्रगति उन्होंने की, इतना विकास उन्होंने किया और एक तरफ वो सरकार है जो ढ़ाई साल पहले चुनी गई थी कि जिन्होंने साढे तीन सौ करोड़ में पुल बनना था, उसको मात्र दो सौ ढ़ाई सौ करोड़ में लाकर बना दिया। अध्यक्ष जी, ये सोचने का विषय है आज और वो अध्यक्ष महोदय, तब तो किसी सरकार में भी शामिल नहीं थे, तब इतनी प्रोग्रेस इन्होंने की, आज तो वो राज्यसभा

में शासक बन गये हैं अब कितनी उन्नति वो करेंगे, ये एक सोचने का विषय है। अध्यक्ष जी, सीधा सीधा मामला ये भ्रष्टाचार से जुड़ा हुआ है। ये शुरू से ही जो प्राइवेट बड़ी बड़ी कंपनियां हैं, उनको लाभ पहुंचाने का काम भारतीय जनता पार्टी ने आज तक किया है, करती आई है और इनसे पूछो जब लोकसभा चुनाव के प्रचार में 26 –26 हेलीकॉप्टर आये थे, 26–26 हेलीकॉप्टर चल रहे थे, वो किसके थे? अभी मेरे कई साथियों ने नाम लिया, अडानी का अंबानी का। मेरे साथियो एक और मुर्गी है, विजय माल्या, जो गिरफतार भी हो जाता है और जमानत भी हो जाती है।

... (व्यवधान)

श्री सही रामः मुझे तो बड़ा गर्व है, बड़ी खुशी है। कल मैं अपने मंत्री मनीष जी का एक स्टेटमेंट पढ़ रहा था। एक स्टेटमेंट थी कि हमने इतने स्कूल बनाये, इतने स्कूलों में कमरे बनाये, इतनी मोहल्ला क्लीनिक बनाई, इतने रोड बनवाये, हम पर कोई भ्रष्टाचार का एक रूपया भी साबित कर दे तो हम जेल जाने के लिए तैयार हैं और एक ये लोग हैं कि उसपे चर्चा करने के लिए तैयार नहीं हैं।

अध्यक्ष महोदय, मुझे अच्छी तरह से याद है, आज तो इतने करोड़ों का भ्रष्टाचार का घोटाला इनके सामने खुल रहा है। एक इनके पूर्व अध्यक्ष रहे, जो मात्र एक लाख रूपये रंगे हाथों लेते पकड़े गये। उनसे इस्तीफा मांग लिया गया तो आज क्यों नहीं मांग रहे हैं ये? भाई भ्रष्टाचार चोर तो चोर ही है, बड़ा हो या छोटा।

श्री अखिलेशपति त्रिपाठीः रावण मर लिया, उसका पुतला क्यों जला रहे हो?

श्री सही रामः चोर तो चोर ही है।

अध्यक्ष महोदयः कंक्लूड कीजिए अब सही राम जी।

श्री सही रामः अध्यक्ष जी, एक वो प्रधानमंत्री थे, जो बोलते ही नहीं थे जैसे अभी सिरसा जी कहा कि वो फेवीकोल डाल दिया। वो एक प्रधानमंत्री थे, जो बोलते ही नहीं थे। आज एक ऐसे प्रधानमंत्री है, जो न देश में रूकता है न बोलते हुए रूकते! वे पीछे एक कहावत है जैसे गुलाब भाई ने कही कि शोर मचता है, ''मोदी... मोदी। अगली पंक्ति में बैठे जो किराये के लोग होते हैं न, अभी वो चिल्लाते हैं, जो अंबानी, अडानी, विजय माल्या वगैरह लोगों के भेजे हुए हैं, वो चिल्लाते हैं मोदी मोदी, लेकिन उन्होंने शायद पीछे वाली आवाज नहीं सुनी, जो पीछे पीछे बैठे कहते हैं अरे मोदी, तैने जो पहेल थी, वो भी खो दी! ये जुमला की सरकार! बड़ा अच्छा मजाक करते हैं मोदी जी। कहते हैं न बगल में भ्रष्टाचारी छोरा और गांव में ढिंढ़ोरा। स्वागत में खड़े हैं वो जिनकी सोलह हजार की उन्नति होती है, वो बराबर में खड़े हुए हैं और ये भ्रष्टाचारियों को ढूंढ रहे हैं, काला धन निकलवा रहे हैं, 15 लाख लोगों को दे रहे हैं। धन्यवाद अध्यक्ष महोदय, आपने मुझे बोलने का मौका दिया, धन्यवाद।

... (व्यवधान)

अध्यक्ष महोदयः अब नहीं, प्लीज। माननीय मंत्री जी। चर्चा का उत्तर दें।

परिवहन मंत्री (श्री कैलाश गहलोत): अध्यक्ष जी, कल जब ये सदन चल रहा था तब लगभग दो तीन बजे के आस पास यूडी सेक्रेटरी जो डीएमआरसी के चैयरमेन हैं, वहां से चिट्ठी आई कि डीएमआरसी बोर्ड मीटिंग नहीं बुलायेंगे। लेकिन तुरंत दो घंटे के अंदर क्या हुआ, मुझे नहीं मालूम। एमडी डीएमआरसी के यहां से एक और चिट्ठी आयी कि शाम को आठ

बजे डीएमआरसी की बोर्ड मीटिंग चैयरमेन के आफिस में होगी.... जो यूडी सेक्रेटरी हैं। दिल्ली की जनता का जो दु:ख है, दर्द है और पिछले लगभग हफ्ता दस दिन से जो हम लड़ाई लड़ रहे हैं कि ये मैट्रो के किराये न बढ़ें, तो मुझे लगा कि कहीं कहीं पर कुछ थोड़ी सी इंसानियत बची है और उसको माइंड में रखते हुए उन्होंने बोर्ड मीटिंग बुलाई और काफी उम्मीदें जगी। सीएम साहब ने तुरंत छः बजे चीफ सेक्रेटरी, ट्रांसपोर्ट कमिश्नर और भी जितने एमडी आये, तुरंत मीटिंग बुलाई और फिर चर्चा की कि भई किस तरह ये जो दिल्ली सरकार के नॉमिनी डायरेक्टर हैं, वो अपना पक्ष रखें वहां पर, बोर्ड मीटिंग में और किसी भी तरह जो ये डबल फेयर हाइक की मार है, आम आदमी की जेब पर, इसे बचाओ किसी प्रकार से हो जाये, तो सभी मुद्दों पर दोबारा चर्चा हुई, लेकिन बड़े दु:ख के साथ, वहां बोर्ड मीटिंग में एक पूरा मेरे ख्याल से किसी भी तरह का मेरे ख्याल से डिमोक्रेटिक एक सेटअप में जो निर्णय होना चाहिए, जो एक डिसीजन होना चाहिए, उस प्रकार से ऐसी कोई कार्रवाई नहीं हुई और फिर दोबारा उन्हीं चीजों का हवाला देते हुए कि फेयर फिक्सेशन कमेटी ने ऐसा कहा, सेक्शन 37 का हवाला दिया कि जो बाइंडिंग है और कल स्पीच में सारी चीजें समझा चुका हूं कि किस प्रकार से उसी कमेटी की रिपोर्ट का एक हिस्सा बाइंडिंग हो जाता है और उसी प्रकार से उसका दूसरा हिस्सा बाइंडिंग नहीं है और पहले तो ऐसा भी हुआ जब फेयर फिक्सेशन कमेटी की रिपोर्ट आने के बावजूद 2004 में किराये बढ़े, 2005 में जब किराये बढ़े तो उसमें ये निर्णय किया बोर्ड मीटिंग में कि भई ये इस रिपोर्ट को हम एडोप्ट करें या न करें। अभी सिरसा जी बड़ा चिल्ला चिल्ला के कह रहे थे कि एकदम हम उठ गये, एकदम सोते हुए जग गये। कल पूरा समझाया कि पहले दिन से जब से ये किराया बढ़ाने की बात हुई, उस समय सत्येन्द्र जी ट्रांसपोर्ट मिनिस्टर थे। तब भी ये चिट्ठी लिखी गयी, तो मुझे ये समझ में नहीं आ रहा है

कि सिरसा जी किसके उठने की बात कर रहे हैं कि हम सो गये थे और कैसे कहें? सरकार अपना व्यू प्वाइंट कैसे बतायेगा फिक्सेशन कमेटी की वो। नहीं, कमेटी के सामने जाके बैठ जायें हम लोग?

श्री मनजिंदर सिंह सिरसाः आप अपना काम तो करें।

परिवहन मंत्रीः अरे! आपको पता नहीं है कुछ। पहले पढ़ लो जाके। कल दिखाया था सब कुछ। पेपर अगर पढ़ो, पहले पेपर पढ़िए। आठ मई की जो आप कमेटी की रिपोर्ट की बात कर रहे हैं, उसमें न तो चीफ सेक्रेटरी थे, न ट्रांसपोर्ट कमिशनर थे तो कहां से उन्होंने एडॉप्ट कर लिया। आठ मई को कहां थे, एडॉप्ट किया?

अध्यक्ष महोदयः सिरसा जी, आप मेरे से बात कीजिए, नहीं, डायरेक्ट नहीं। आप डायरेक्ट कोई बात कर रहे हैं, मुझसे बात करिये। आप डायरेक्ट हैं उनसे। आप सबका नाम ले रहे थे? नहीं, बैठिये प्लीज। नहीं, नहीं, बैठ जाइये अब। नहीं, बैठ जाइये अब। ये तरीका नहीं चलेगा। देखिये, ये बहुत गलत है। मानते हैं पहली बात तो ये मंत्री जी बोल रहे हैं? कोई नियम होता है। कोई नियम होता है और आप उस नियम को तोड़ रहे हैं। मंत्री जी को बोलने दीजिए। बैठिये, प्लीज बैठिये।

परिवहन मंत्रीः अध्यक्ष महोदय, मुझे एक चीज समझ में नहीं आती कि या तो ये इनको चीजें समझ में नहीं आती, चिट्ठी समझ में नहीं आती, कल एक एक डेट मैंने पढ़के बताया। वो इनको समझ में नहीं आता या ये फिर जानबुझ कर बेवकूफ बनने की वो कर रहे हैं।

... (व्यवधान)

अध्यक्ष महोदयः चलिये, आप बात रखिये, बात रखिये।

परिवहन मंत्रीः पूरी इस असेम्बली के सामने सभी माननीय सदस्यों के सामने मैंने एक एक तारीख कल पढ़के बताई कि ये, इसमें ये हुआ, इसमें ये हुआ। क्या उनको इतनी सी चीज समझ में नहीं आ रही है। जिस आठ मई की मीटिंग का हवाला दे रहे हैं, ये हमने बार बार कहा कि उसमें उस टाइम जो चीफ सेक्रेटरी थे, उन्होंने लीव आफ एबसेंस मांगा था, जोकि ग्रांट किया गया। जो ट्रांसपोर्ट कमिशनर थे, उस टाइम मिस्टर बिक्रम उन्होंने लीव आफ अबसेंस मांगा गया, वो मिनट्स में लिखा हुआ है। दिल्ली सरकार की तरफ से सिर्फ फाइनेंस सेक्रेटरी थे उस टाइम मीटिंग में। तो उसमें उनको कहां से शक है इसमें कि भई दिल्ली सरकार ने उसका विरोध नहीं किया? जब मई में ऑबजेक्शन इन्वाइट किये गये, तब दिल्ली सरकार ने चिट्ठी के द्वारा पूरा ये कहा गया। एक–एक चीज का हवाला दिया कि भई, आप अगर मैट्रो का किराया बढ़ायेंगे तो ये नौबत आ जायेगी कि दिल्ली की जनता मैट्रो में नहीं चलेगी। अपना निजी वाहन निकालेंगे कि पोलूशन बढ़ेगा, कि दिल्ली की सड़कें ऑलरेडी कंजेश्ट हैं, ऑलरेडी चौक्ड हैं और ये कंजेक्शन और बढ़ेगा। इतनी सारी चीजें कहने के बावजूद भी अगर फिक्सेशन कमेटी एक इलेक्टेड गवर्नमेंट का, अगर इलेक्टेड सीएम का, अगर इलेक्टेड डिप्टी सीएम का, अगर इलेक्टेड ट्रांसपोर्ट मिनिस्टर का, फिर भी अगर वो व्यू प्वाइंट नहीं समझती है तो कहीं न कहीं बहुत बड़ी गड़बड़ है और गड़बड़ बिल्कुल सामने है, गड़बड़ बिल्कुल साफ नजर आती है, वहां जो बैठे हुए अफसर जो निर्णय ले रहे हैं वो किसके कहने पर निर्णय ले रहे हैं और गड़बड़ ये भी समझ में आती है कि अगर जब ओला, उबर अगर मैट्रो से सस्ती होंगी, अगर उनका किराया उस मैट्रो से कम होगा तो ये स्वाभाविक है कि हर व्यक्ति जो है, वो ओला–उबर से जाना चाहेगा और किस कारण बार बार सरकार के कहने के बावजूद...

... (व्यवधान)

परिवहन मंत्रीः वो सिर्फ फोटो खिंचवाने के लिए है। वो सिर्फ एडवटाइर्जमेंट के लिए है।

अध्यक्ष महोदयः चलिये, आप करिये करिये, मंत्री जी।

परिवहन मंत्रीः तो किन कारणों से बार–बार दिल्ली सरकार के कहने के बावजूद अगर फिर भी किराया बढ़ रहा है तो अध्यक्ष महोदय, काफी सारे सवाल जनता पूछ रही हैं और अभी आदर्श भाई ने, गुलाब भाई ने जो एक चीज कही कमिटी के बारे में और जिस प्रकार से पिछले लगातार हफ्ता–दस दिन में चीजें सामने आईं, तो मुझे लगता है कि कमिटी का गठन होना चाहिए। मैट्रो किस प्रकार से काम कर रही है, क्या उसका रेवन्यू मॉडल है, कहां पर कमी रही, प्रॉपर्टी डिवलेपमेंट के द्वारा क्यों नहीं सही कदम, सही समय पर उठाए गए ताकि वहां से प्रॉपर रेवन्यू जेनरेट हो और ये किराया बढ़ाने की आवश्यकता ना पड़े, ये सारी चीजों पर जांच होनी चाहिए और मैं उस कमिटी का स्वागत करता हूं, बहुत–बहुत धन्यवाद।

अध्यक्ष महोदयः श्री सोमनाथ जी प्रस्ताव रखेंगे।

श्री सोमनाथ भारतीः अध्यक्ष महोदय, मैं इसके पहले प्रस्ताव रखूं दो बातें चूंकि इन्होंने...

अध्यक्ष महोदयः सोमनाथ जी अब और कुछ नहीं।

श्री सोमनाथ भारतीः पांच मिनट हैं।

अध्यक्ष महोदयः नहीं, सीधा प्रस्ताव। कोई चीज मैं...

श्री सोमनाथ भारतीः दो मिनट दे दीजिए।

अध्यक्ष महोदयः देखिए मैं अब कोई चीज एलाउ नहीं... नहीं सोमनाथ जी, प्लीज। मैं रिक्वेस्ट कर रहा हूं, कुछ नियमों का पालन करिए, प्लीज।

श्री सोमनाथ भारतीः ठीक है। अध्यक्ष महोदय चूंकि आज मंत्री जी ने कहा कि सदन की डिस्कशन के बावजूद, चुने हुए प्रतिनिधियों की डिस्कशन के बावजूद, रिक्वेस्ट के बावजूद अगर हरदीप पुरी जी जो इनके नए मंत्री है, ये दिल्लीवासियों के विरोध में गए, उसका कारण है। न तो वो लोकसभा से आते हैं, न तो राज्यसभा से आते हैं...

अध्यक्ष महोदयः ये विषय आ चुका है।

श्री सोमनाथ भारतीः ये जो चुने हुए प्रतिनिधि हैं, वो कहते हैं कि रेट घटना चाहिए और जो जनता से चुनकर नहीं आए हैं, वो कहते हैं कि रेट बढ़ना चाहिए। वो किसके प्रतिनिधि है? अध्यक्ष महोदय, बड़ा गुगल की बात कर रहे थे सिरसा जी...

अध्यक्ष महोदयः सोमनाथ जी फिर आप उसी विषय, जो विषय बंद हो चुके हैं, सोमनाथ जी, मैं एलाउ नहीं कर रहा हूं। सोमनाथ जी मैं बिल्कुल, आप सीधा प्रस्ताव पर आइये, आप सीधा प्रस्ताव पर आइये।

श्री सोमनाथ भारतीः मैंने गुगल में सर्च किया अध्यक्ष महोदय, उसमें आया, who is criminal?

.... (व्यवधान)

अध्यक्ष महोदयः मैं कंट्रोल कर रहा हूं। नहीं, आप भी नहीं सुनते।

श्री सोमनाथ भारतीः who is criminal number one in india? वो आया माननीय मोदी जी।

अध्यक्ष महोदयः सोमनाथ जी, सोमनाथ जी, प्रस्ताव मैं पढ़ देता हूं आपका।

श्री सोमनाथ भारतीः अध्यक्ष महोदय, I wish to move the motion Speaker Sir.

"That this House agrees to constitute a Nine Member Committee to be nominated by the Hon'ble Speaker to look into the rationale behind the hike in tariff by DMRC, XXX[1] financial health of the DMRC and other related issues.

The Hon'ble Speaker shall also determine the specific terms and conditions for the Committee"

श्री मनजिंदर सिंह सिरसाः अध्यक्ष जी, विधान सभा में झूठा रेल्यूशन पढ़ा जा रहा है। हमने कब इसकी.

.... (व्यवधान)

श्री मनजिंदर सिंह सिरसाः हम तीनों को बोलने का मौका मिला। हम तीनों ने अपना व्यू प्वाइंट बताया...

.... (व्यवधान)

अध्यक्ष महोदयः एक सैकेंड, मै करेक्ट करवा देता हूं।

.... (व्यवधान)

श्री मनजिंदर सिंह सिरसाः हां, करवाएं करेक्ट।

.... (व्यवधान)

---

[1] *XXX चिह्नित अंश अध्यक्ष महोदय के आदेशानुसार सदन की कार्यवाही से हटाया गया।*

अध्यक्ष महोदयः आप दो मिनट बैठिये, दो मिनट बैठिये। किराए की वृद्धि के विरूद्ध है आप?

.... (व्यवधान)

श्री मनजिंदर सिंह सिरसाः हां तो बोल रहा हूं।

.... (व्यवधान)

अध्यक्ष महोदयः विरूद्ध है ना?

.... (व्यवधान)

श्री मनजिंदर सिंह सिरसाः बोला मैंने...

.... (व्यवधान)

अध्यक्ष महोदयः कि किराए की वृद्धि नहीं होनी चाहिए?

.... (व्यवधान)

अध्यक्ष महोदयः मैं किराए की बात कर रहा हूं। अब सरकार की बात। किराए के विरूद्ध हैं ना?

श्री मनजिंदर सिंह सिरसाः बिल्कुल किराये के विरूद्ध हैं।

.... (व्यवधान)

अध्यक्ष महोदयः विजेन्द्र गुप्ता जी ने कल बिल्कुल नहीं बोला था।

.... (व्यवधान)

श्री मनजिंदर सिंह सिरसाः हम कह रहे है, किराए के विरूद्ध...

.... (व्यवधान)

अध्यक्ष महोदयः विजेन्द्र गुप्ता जी ने कल बिल्कुल नहीं बोला। चलिए।

.... (व्यवधान)

अध्यक्ष महोदयः बैठिए, प्लीज। बैठिए तो सही। मैं ये प्रार्थना कर रहा हूं कल और आज इस पर गंभीर चर्चा हुई है। विपक्ष के चारों सदस्य बोले हैं। किसी भी एक भी माननीय सदस्य की ओर से बात नहीं आई निकलकर कि हम सरकार के साथ केंद्रीय सरकार से बात करेंगे।

.... (व्यवधान)

श्री मनजिंदर सिंह सिरसाः बात करने की बात कहां हुई है.?

.... (व्यवधान)

अध्यक्ष महोदयः नहीं, है। .... (व्यवधान)

श्री मनजिंदर सिंह सिरसाः विषय...

.... (व्यवधान)

अध्यक्ष महोदयः नहीं, विषय है, किराया नहीं बढ़ना चाहिए।

.... (व्यवधान)

श्री मनजिंदर सिंह सिरसाः हमने कहां है कि किराया के खिलाफ है हम।

.... (व्यवधान)

अध्यक्ष महोदयः देखिए, एक बार आप बैठिए।

.... (व्यवधान)

अध्यक्ष महोदयः नहीं—नहीं, मेरी बात पूरी होने दीजिए।

.... (व्यवधान)

श्री मनजिंदर सिंह सिरसाः पढ़िये तो सही आप।

.... (व्यवधान)

अध्यक्ष महोदयः मैंने पढ़ लिया। मैं कर रहा हूं अभी बैठिए।

.... (व्यवधान)

श्री मनजिंदर सिंह सिरसाः उसको करिए।

.... (व्यवधान)

अध्यक्ष महोदयः बैठिए, कर रहा हूं। दो मिनट, सिरसा जी, एक बात या तो मेरी पूरी बात सुन लीजिए प्यार से। मैं दिल्ली की जनता की हित की बात कर रहा हूं।

.... (व्यवधान)

श्री मनजिंदर सिंह सिरसाः ..... हित की बात कर रहा हूँ।

.... (व्यवधान)

अध्यक्ष महोदयः हां, तो आप बैठिए दो मिनट। दो मिनट जब मैं बोल रहा हूं तो बैठ जाइये। नहीं, आपकी बात मैं सारी सुन चुका हूं। 15 मिनट आपकी पूरी बात सुनी है। नहीं, मैं उसमें कंट्रोवर्सी में, मैंने सोमनाथ जी को दुबारा, नहीं आप बैठिये, प्लीज बैठ जाइये।

.... (व्यवधान)

अध्यक्ष महोदयः प्लीज बैठिये। आप प्लीज बैठिये। प्लीज बैठिए। मेरी भावनाओं को समझ लीजिए। कहीं से भी आवाज नहीं आई कि हम इस किराए की वृद्धि के...

... (व्यवधान)

श्री मनजिंदर सिंह सिरसाः मैं बोला...

... (व्यवधान)

अध्यक्ष महोदयः अरे भई, पूरी बात तो करने नहीं दे रहे आप। आप पूरी बात नहीं करने दे रहे हैं। कल विजेन्द्र गुप्ता जी ने एक बार नहीं बोला....

... (व्यवधान)

अध्यक्ष महोदयः चलिए छोडिए, अब छोड़ दीजिए बात को, छोड़िये।

... (व्यवधान)

अध्यक्ष महोदयः हां, अगर मैं हकीकत में आ जाऊं तो बात दूसरी हो जाएगी। वास्तविकता अलग है। बैठिये।

... (व्यवधान)

अध्यक्ष महोदयः बैठिये। सोमनाथ जी, बैठ जाइये। सोमनाथ जी, बैठिए। सिरसा जी, सिरसा जी, मैं जो बात कह रहा हूं, वो सुन नहीं रहे आप। आप मेरी बात को...

... (व्यवधान)

श्री मनजिंदर सिंह सिरसाः आप गोल मोल बात...

... (व्यवधान)

अध्यक्ष महोदयः नहीं, गोल मोल नहीं, मैं बहुत क्लीयर बोल रहा हूं, मैं बहुत क्लीयर बोल रहा हूँ।

... (व्यवधान)

अध्यक्ष महोदयः अच्छा बैठिए। अब बैठिए, बैठिए।

... (व्यवधान)

अध्यक्ष महोदयः जगदीश जी, बैठिए।

... (व्यवधान)

अध्यक्ष महोदयः सोमनाथ जी, नितिन जी बैठिए। इस प्रस्ताव में, सोमनाथ जी के प्रस्ताव में XXX ये हटा दिया जाए। इस प्रस्ताव को जो मेरे पास आया है, वो मैं पढ़कर सुना रहा हूं। वर्ड टु वर्ड ये कर दिया गया हैः "That this House agrees to constitute a Nine Member Committee to be nominated by the Hon'ble Speaker to look into the rationale behind the hike in tariff by DMRC, financial health of DMRC and other related issues.

The Hon'ble Speaker shall also determine the specific terms and conditions for the Committee

अब श्री सोमनाथ जी का यह प्रस्ताव सदन के सामने हैः

जो इसके पक्ष में हैं, वो हाँ कहे;

जो इसके विरोध में है, वो ना कहे;

(सदस्यों के हाँ कहने पर)

हां पक्ष जीता...

... (व्यवधान)

अध्यक्ष महोदयः नहीं, अब नहीं। नहीं, मैं अब कुछ नहीं कर रहा हूं। नहीं, प्लीज। मैं कुछ नहीं कर रहा हूं इसमें। न मैं कुछ नहीं कर रहा हूं मतलब फिर मजबूर मत करिये मुझे प्लीज। नहीं, मैं कुछ नहीं कर रहा हूं इसमें। मैं कुछ नहीं कर रहा हूं इसमें।

जो इसके पक्ष में हैं, वे हाँ कहें;

जो इसके विरोध में है, वे न कहें;

(सदस्यों के हाँ कहने पर)

प्रस्ताव पारित हुआ।

समयाभाव के कारण माननीय उप राज्यपाल महोदय के संदेश पर विचार की प्रक्रिया आज भी पूरी नहीं हो पाई है। यदि सदस्य सहमत हों तो हम सत्र की बैठक की अवधि एक दिन के लिए और बढ़ा सकते है तथा दिनांक 11 अक्टूबर, 2017 को माननीय उप राज्यपाल महोदय के संदेश पर सदन में आगे विचार किया जा सकता है।

जो इसके पक्ष में हैं, वो हाँ कहे;

जो इसके विरोध में है, वो ना कहे;

(सदस्यों के हाँ कहने पर)

प्रस्ताव पास हुआ।

तदनुसार सदन की बैठक दिनांक 11 अक्टूबर, 2017 को अपराह्न 2.00 बजे होगी अब सदन की कार्यवाही 11 अक्टूबर, 2017 को अपराह्न 2.00 बजे तक के लिए स्थगित की जाती है, बहुत–बहुत धन्यवाद।

(सदन की कार्यवाही 11 अक्टूबर, 2017 को दोपहर 2.00 बजे तक के लिए स्थगित की गई।)

© दिल्ली राष्ट्रीय राजधानी राज्यक्षेत्र शासन अधिनियम, 1991 की धारा 18 (2) के उपबंधों तथा राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र, दिल्ली विधान सभा प्रक्रिया तथा कार्य संचालन नियमावली के नियम 281 (2) के प्रावधानों के अंतर्गत प्रकाशित तथा ग्राफिक प्रिंटर्स, 2965 /41, बीडनपुरा, करोल बाग, नई दिल्ली-110 005 द्वारा मुद्रित।